खण्ड-263, अंक-10
मंगलवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(1 मार्च, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 263 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा–मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वरआरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराज सिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान , श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथलरन सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रम सिंह, श्री

फूल सिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनबारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बल्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहन लाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री
भीखालाल, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंड़ड़ी, श्री
रक्षपाल सिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर राय, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामग्रधार कनौजिया, श्री
रामग्रनन्त पांडेय, श्री
रामग्रवध, श्री
रामग्रासरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुक्मसिंह राठौर, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक्वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विमलालक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्र प्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री

सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १ मार्च, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मुख्य अभियन्ता के दौरे का प्रोग्राम 'रोमन लिपि' में

**१—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को पता है कि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के दौरे के कार्यक्रमों की सूचना जो दी जाती है उसमें हिन्दी भाषा को देव नागरी लिपि में न लिख कर रोमन लिपि में लिखा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

मुख्य अभियन्ता के दौरे का केवल एक कार्यक्रम रोमन लिपि में गलती से बन गया था।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि यह किसकी गलती से बना और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिस वक्त वह कार्यक्रम बनवाया गया उस वक्त परिस्थितिवश उनके पास जो हिन्दी आशुलिपिक था वह मौजूद नहीं था। तो अंग्रेजी आशुलिपिक से उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बनाकर भेज दो क्योंकि कार्य बहुत जरूरी था और समय नहीं था। वह आशुलिपिक हिन्दी नहीं जानता था, इसलिये उसने रोमन लिपि में बनाकर भेज दिया। लेकिन अब कड़ाई से आदेश दे दिये गये हैं कि ऐसी गलती दोबारा न होने पावे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

इन्सालवेन्सी अदालत, अलीगढ़ के रिसीवर एडवोकेट के विरुद्ध शिकायत

*१—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ के सालवेंसी जज की अदालत में मुकदमा नं० १०, सन् १९४७ में मुकर्रर रिसीवर, श्री ब्रिज किशोर. एडवोकेट ने उपरोक्त अदालत द्वारा उपरोक्त मुकद्दमे में हुये दिनांक १ अप्रैल, १९६३ के आदेश के विरुद्ध कार्य क्यों किया ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

उक्त रिसीवर ने इन्सालवेन्सी न्यायालय के दिनांक १-४-६३ के आदेश के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया।

*२—श्री काशीनाथ मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी उपरोक्त न्यायालय द्वारा उपरोक्त मुकद्दमें में हुये आदेश को तत्काल कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे तथा उसके विरुद्ध आचरण करने वाले रिसीवर एडवोकेट के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करेंगे ?

श्री सैय्यद अली जहीर—

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ हाईडिल डिवीजन

*३—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ हाईडिल डिवीजन में कितने सब-डिवीजनल आफिसर, लाइन इंस्पेक्टर और उनके अधीन स्टाफ (वर्क चार्ज तथा स्थायी) हैं और उन्होंने १ अगस्त, १९६५ से ३१ जनवरी, १९६६ तक कितने नये इस्टीमेट, नये एग्रीमेंट और कितने नये कनेक्शन दिये ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

हाईडिल डिवीजन, अलीगढ़ में ६ सब-डिवीजनल आफिसर, १८ लाइन इन्सपेक्टर तथा ४१६ अन्य स्टाफ हैं। इस डिवीजन में १ अगस्त, १९६५ से ३१ जनवरी, १९६६ तक २,२२८ एस्टीमेट बने, १०२ एग्रीमेन्ट हुये और १,४८७ कनेक्शन दिये गये।

*४—श्री छत्रपति अम्बेश (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि अधिक स्टाफ होते हुये भी बहुत ही कम कनेक्शन दिये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

फतेहपुर—असोथर मार्ग पर बस सर्विस बन्द होना

*५—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन विभाग, कानपुर क्षेत्र द्वारा गत डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से चलाई जाने वाली राजकीय बसों को, जो फतेहपुर जिलान्तर्गत, फतेहपुर-असोथर मार्ग पर जो थरियांव गांव होकर चलती थी, किन विशेष परिस्थितियों के कारण मुख्य प्रबन्धक, रोडवेज, कानपुर क्षेत्र ने दिनांक १२ फरवरी, १९६६ से बसें न चलाये जाने के आदेश जारी कर दिये ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

प्राइवेट आपरेटर्स, जो फतेहपुर-असोथर बाया गाजीपुर मार्ग पर पहले ही से गाड़ियां चलाते थे, थरियांव तक अपनी गाड़ियां चलाने के लिये प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी से अपने उक्त मार्ग को बढ़वा कर थरियांव तक गाड़ियां चलाने लगे हैं। चूंकि रोडवेज ने थरिगांव-असोथर मार्ग के लिये कोई परमिट नहीं लिये थे अतः रोडवेज की बसों का चलाया जाना ९ फरवरी, १९६६ से बन्द कर दिया गया। रोडवेज की बसें केवल २४ दिसम्बर, १९६४ से चल रही थीं।

*६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या परिवाहन मंत्री मुख्य प्रबन्धक, रोडवेज, कानपुर क्षेत्र को सख्त आदेश तत्कालिक देंगे कि प्रभावित क्षेत्र विशेष के नागरिकों के हितों की रक्षा हेतु बसों का चलाना बन्द न किया जाय नहीं तो कठिनाई क्या है ? क्या यह सत्य है कि इससे विभाग को पर्याप्त आय थी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जब तक थरियांव असोथर मार्ग का राष्ट्रीकरण नहीं किया जाता तब तक रोडवेज की बसें उस मार्ग पर नहीं चलाई जा सकतीं। इस मार्ग का राष्ट्रीकरण विचारधीन है।

आमदनी पर्याप्त नहीं कही जा सकती।

श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या फतेहपुर–असोथर मार्ग पर ५ बसें चलाई जाती थीं और इनका चलाना दिसम्बर सन् ६४ से आरम्भ हुआ था और सन् ६५ क चलाई गई, इसके लिये परमिट नहीं था। तो किसके आदेश से यह बसें चलाई गई थीं जब आमदनी भी नहीं थी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इन बसों को वहां के जनरल मैनजर और आर० टी० ओ० को अन्डरस्टैन्डिग पर उन्होंने चलाया था।

श्री रामकिशोर वर्मा—

कानपुर के कमिश्नर ने परिवहन मंत्री को जो सूचना दी है उसमें लिखा है कि बिना परमिट के बसें चलाई जा रही हैं और इनका चलाना बन्द होना चाहिये। जब प्राइवेट आपरेटर्स ने जेनरल मैनेजर को नोटिस दिया तब वह बन्द किये गये। क्या इसकी सूचना मंत्री जी को है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

हां, यह बात सही है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

आपने स्वीकार किया कि बिना परमिट के बसें चलाई गईं और बिना परमिट बस चलाना कानूनन अपराध है तो यदि यह सही है तो पुलिस ने उन बसों के कितने चालान किये और अगर नहीं किये. तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री रामकिशोर वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बसें डेढ़ वर्ष के चलाई गई और उत्तर में कहा गया कि पर्याप्त आय नहीं थी। जब आय भी नहीं थी, आर० टी० ओ० ने रोका भी था, परमिट भी नहीं था तो वह कौन सा आधार था जिसके अन्तर्गत वह बसें चलती रहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

असल में जेनरल मैनेजर ने इस १९ मील लम्बे मार्ग रोडवेज की गाड़ियां चलाने के लिये इजाजत चाही थी और उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इजाजत इस शर्त के साथ दी कि वह आर० टी० ओ० से परमिट प्राप्त कर लें और फिर वह गाड़ियां चलती रहीं। अब जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया तब जवाब से इतना पता चला कि उनके पास परमिट नहीं था और अब उस पर जांच की जा रही है कि यह सब क्यों हुआ।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने आर० टी० ओ० के यहां दरखवास्त दी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त दी ही नहीं गयी।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि ऐसी सड़कों पर भी रोडवेज की बसें चलती हैं जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है तब इस सड़क के ऊपर क्या खास आपत्ति है जिससे यह नहीं चल सकती हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अराष्ट्रीयकृत सड़कों पर भी परमिट लेकर रोडवेज की बसें चल सकती हैं।

श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या यह सही है कि उसी जिले में एक वर्ष तक वह गाड़ियां चलीं बिना परमिट लिये क्योंकि प्राइवेट आपरेटर्स और आर० टी० ओ० के बीच में लेन-देन वाला मामला है ?

श्री हरीदत्त गांडपाल—

माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो जरूर जांच करवायेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[५वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

[१ मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पिपराघाट के ठेकेदार को भगतान की जांच

*१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री को देवरिया के एक विधायक द्वारा इस आशय की सूचना नवम्बर, १९६५ के तीसरे सप्ताह में मिली है कि जनरल मैनेजर, राजकीय रोडवेज, गोरखपुर ने गत एक वर्ष में ९६,००० गलत तौर पर बलिया–उजियार घाट रूट पर पिपराघाट के ठेकेदार को गाड़ियों के उतराई के रूप में प्रतिमास ८,००० का भुगतान कर दिया ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जी है।

*२—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पिपराघाट के ठेकेदार को ८,००० प्रतिमाह का पेमेंट किस अधिकारी के आदेश से किया गया और क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रतिमाह ८,००० रु० का भुगतान नहीं किया गया। उप प्रधान प्रबन्धक, आजमगढ़ तथा भूतपूर्व प्रधान प्रबन्धक, गोरखपुर के आदेश से भुगतान किया गया। इस पर जांच हो रही है।

चक्की भूसाडोही को ऊंचा करने की प्रार्थना

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चक्की भूसाडोही, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की आबादी को ऊंचा करने के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक १० अगस्त, १९६४ का लिखित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही हुई है और अब तक ऊंचा न करने का कारण क्या है?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

जीं हां। इस सम्बन्ध में जांच कराई गई टेक्नीकी दृष्टि से इस ग्राम को ऊंचा कराया जाना उपयुक्त नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि वह कौन से टेक्नीकी दृष्टिकोण हैं जिनके कारण इसको ऊंचा नहीं कराया जा सकता?

श्री गिरधारीलाल—

यह गांव घाघरा के दाहिने किनारे पर है और यह गांव बरसात में २ धाराओं के बीच में आ जाता है। इसके लिये मुनासिब है कि यह गांव यहां से हटा दिया जाय।

रोडवेज क्षेत्र, इलाहाबाद में ड्राइवरों व कण्डक्टरों का बकाया वेतन

*४—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि इलाहाबाद रीजन के कन्डक्टरों व ड्राइवरों का दिनांक १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६५ तक वेतन का कितना रुपया सरकार के जिम्मे बकाया है?

श्री मुजफ्फर हसन—

लगभग रु० १७,४००.१५ पैसे।

घोसी तहसील में बिजली

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् उप मन्त्री को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक २६ मार्च, १९६४ का भेजा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कई ग्रामों में बिजली लगाने की मांग की गई थी? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कौन कार्यवाही की गई और मांग के अनुसार किन-किन ग्रामों में बिजली देने का आयोजन है?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां—२६ मार्च, १९६४ के पत्र में दिये गये ग्रामों में से निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है :—

१—दुबारी
२—लखनोर
३—कटघरा शंकर
४—दरगाह
५—फतेहपुर।

*६---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के ग्राम मधुबन, कमल सागर और सूरजपुर के कितने-कितने व्यक्तियों के आवेदन-पत्र बिजली की मांग के लिये महीनों से सहायक अभियन्ता, बिजली विभाग, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के पास पड़े हुये हैं? और अब तक बिजली न ये जाने का कारण क्या है?

श्री जयराम वर्मा---

घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के ग्राम मधुबन, कमलासागर और सूरजपुर के जिन व्यक्तियों के आवेदन पत्र बिजली की मांग के लिये प्राप्त हुए हैं और उन को अब तक बिजली न दिये जाने के कारण की एक सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट १००८ पर)

स्याना क्षेत्र में नलकूपों की मांग

*७---श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सोजना झांया (विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर) के किसानों के अनेक प्रार्थना-पत्र उक्त गांव में नलकूप लगाने के लिये अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, डिवीजन, बुलन्दशहर को सन् १९६५ में बार-बार मिले हैं? यदि हां, तो नलकूप लगाने के लिये उक्त क्षेत्र में कब सर्वेक्षण कराया गया?

*८---क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम मंडी बकापुर में, जहां १,५०० एकड़ भूमि खाली है, सरकारी ट्यूबवेल लगाने के एक प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता सिंचाई ने सन् १९६५ में केवल इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये कि वहां ट्यूबवेल के निर्माण पर साधारण लागत से दस हजार रुपये अधिक लगात का अनुमान है?

*९---क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि नलकूप डिवीजन, बुलन्दशहर ने सन् १९६४ में मुख्य अभियन्ता से यह अनुरोध किया गया था कि ग्राम मंडी बकापुर (स्याना, बुलन्दशहर) में नलकूप बनाया जाय?

श्री गिरधारीलाल---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कुरावली में नलकूपों को बिजली

*१०---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले के टाउन एरिया कुरावली में जो सिंचाई के लिये प्राइवेट ट्यूबवेल लगे हैं उनको पूरी-पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है? इस कारण हजारों बीघा रबी व सब्जी की फसलें सूख कर नष्ट हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि बिजली बराबर मिलती रहे जिससे कि अन्न और सब्जी की पैदावार बढ़ सके?

श्री जयराम वर्मा---

टाउन एरिया, कुरावली, जिला मैनपुरी में सिंचाई के लिये प्राइवेट ट्यूबवेलों की पूरी बिजली दी जा रही है। केवल उसी परिस्थिति में, जब कि किसी उत्पादन यूनिट में गड़बड़ हो जाती है तो परिस्थिति को काबू में करने के लिये कुछ रूरल लाइन फीडर (Rural line feeder) क्रम से खोलने पड़ते हैं, क्योंकि सभी पावर हाउस बिना किसी स्टैन्डबाई (stand by) उत्पादन यूनिट के अपनी अधिकतम क्षमता पर चलाये जा रहे हैं।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया, कुरावली में कितने ट्यूबवेल लगे हुये है ?

श्री गिरधारीलाल—

यह प्रश्न दूसरा है। इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष—

कोई अच्छा प्रश्न पूछिये।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार.....

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जो यह कहा कि 'अच्छा' प्रश्न पूछिये तो जो आपने अस्वीकार किया है क्या वह अच्छा नहीं था ?

श्री अध्यक्ष—

वह 'बहुत' अच्छा था।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुरावली मे प्राइवेट ट्यूबवेलों को बिजली नहीं मिल रही है जिससे खेत सूख रहे हैं ? इंडस्ट्री वालों को बिजली मिलती है लेकिन उनको नहीं मिलती है। इससे सब्जी के खेत सूख रहे हैं। तो सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे उनको बिजली मिलती रहे और फसल न सूख सके ?

श्री गिरधारीलाल—

इस समय काफी सुधार हो गया है। ३, ४ महीने पहले ऐसी हालत थी कि लाइन में ब्रेक डाउन हो जाते थे। जहां तक इस कस्बे की बात है वहां पर ऐसी बात नहीं है कि अलग-अलग लाइन हों, इंडस्ट्री और ट्यूबवेल की अलग-अलग लाइन हों। दोनों की एक ही लाइन हैं। अगर ब्रेक डाउन होता है तो सभी पर होता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ट्यूबवेलों को बिजली न मिलने का कारण यह है कि माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा, जो खुले आम बिजली दिया करते थे उनसे अब वह अधिकार ले कर किसी अधिकारी को दे दिया गया है जिसके कारण यह कठिनाई हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या इस समय कोई कठिनाई हो रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

कहीं बिजली नहीं मिल रही है। सब जगह खेत सूख रहे हैं।

(उत्तर के लिये माननीय मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया :)

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस समय सिंचाई के नलकूपों को बिजली देने में प्राथमिकता है इंडस्ट्री के ऊपर ?

श्री गिरधारीलाल—

इस समय रूरल एरिया के अन्दर प्रायोरिटी इंडस्ट्री के ऊपर ट्यूबवेल्स को देते हैं।

गोमती नदी के औसानेश्वर घाट पर पम्प कैनाल बनाने का सुझाव

*११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि लखनऊ-सुल्तानपुर डिवीजन की शारदा: कैनाल की सभी नहरें सुल्तानपुर जिले के कादू नाले पर समाप्त हो जाती है ? ऐसी दशा मे बाराबंकी रायबरेली, सुल्तानपुर जिले की हजारों बीघा भूमि को सिंचाई के साधन उपलब्ध करने हेतु गोमती नदी के औसानेश्वर घाट पर पम्प कैनाल बनाने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कैनाल उक्त स्थान पर बनाने पर कितना धन व्यय होगा और कब इस योजना को प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—

गोमती नदी से जल पम्प करने की योजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण औसानेश्वर घाट के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी किया जा रहा है। चूंकि सर्वेक्षण का कार्य अभी जारी है और योजना की रूप रेखा पूरे तौर से तैयार नहीं है; अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता कि यह योजना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त होगी या नहीं और किस स्थान पर इसे बनाया जा सकेगा तथा इस पर कितना व्यय होगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

गतवर्ष १९६५ में बताया गया था कि इस योजना के सर्वेक्षण में एक वर्ष लगेगा और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये पानी की जल्द से जल्द आवश्यकता है तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्न करेगी कि इसका सर्वेक्षण कार्य जल्द से जल्द समाप्त हो जाय ?

श्री जयराम वर्मा—

सर्वेक्षण हो रहा है और आशा है वह जल्द ही समाप्त होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पार साल आपने यह कहा था कि साल भर में समाप्त हो जायगा। तो क्या समाप्त हुआ है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

इन जगहों पर सर्वेक्षण कार्य हुआ है लेकिन इसमें काफी कठिनाई मालूम पड़ी है। टेकनीकली वह ठीक नही मालूम पड़ा। खर्चा भी इसमें ज्यादा दिखाई पड़ता है लेकिन एक्जेक्ट इसमें कितना खर्च होगा यह बताना मुश्किल है।

सुल्तानपुर जिले में एक गांव है वहां सर्वेक्षण हो रहा है। वह कम खर्चीला दिखाई पड़ता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि लखनऊ-सुल्तानपुर में जितनी नहरें हैं वह काबू नाले में खत्म हो जाती है और उसके नीचे अगर वह पम्प कैनाल बनेगी तो लखनऊ सुल्तानपुर डिवीजन में नहरों को कोई लाभ न होगा, उस से जौनपुर डिवीजन की नहरों को लाभ होगा। तो इसके बाद सोमेश्वर घाट का इस्टीमेट आता है। तो क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लखनऊ-सुल्तानपुर डिवीजन की नहरों को भी पानी दिया जाय इसके लिये वे इसका सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्नकर्ता महोदय ने एक बार पहले भी इसका जिक्र किया था। वैसे मैंने इस पर यह आदेश दिया है कि जिस समय यह सवाल फाइनली लिया जायगा उस समय कैनाल के सवाल को लेने से पहले वे मेरे से बात कर लें और मैं प्रश्नकर्ता महोदय से भी कहूंगा कि वे उस समय अपनी मंशा को जाहिर कर दें ताकि उसकी रोशनी के अन्तिम निर्णय लिया जा सके।

हरदुआ ब्लाक में सिंचाई व्यवस्था

*१२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सिंघापुर, रामसिंह पुर, घनेसेरी, महादेवपुर, दासेपुर, शंकरपट्टी, हरदुआ, डीह, बैजल, पट्टी, काजीसराय, आनेगपुर, नैपुरा, परगना अठगांवां, ब्लाक हरदुआ, तहसील व जिला वाराणसी के लिये सिंचाई की क्या व्यवस्था की गयी है जब कि इस सम्बन्ध में उपरोक्त गांवों की जनता ने सिंचाई मन्त्री को दिनांक १० दिसम्बर, १९६५ को प्रार्थना पत्र दिया है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में लिखित ११ ग्रामों में से २ गांव थानेमपुर व नेपुरा बन्दोबस्ती ग्राम नहीं हैं : शेष ९ ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्र ७४५ एकड़ में से ४२५ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था वर्तमान नलकूप सिकन्दरापुर वार व कोइराजपुर से है। शेष ३२० एकड़ असिंचित क्षेत्र में से २२ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में प्रस्तावित नलकूप गढवा द्वारा होगी और शेष २९८ एकड़ असिंचित क्षेत्र के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में नलकूप प्रस्तावित किया जायगा।

फतेहपुर जिले को बिजली

*१३—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जिला फतेहपुर के किन-किन स्थानों में बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

जिला फतहपुर के जिन स्थानों का विद्युतीकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में होना है उनकी सूची विचाराधीन है।

*१४—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतलायेंगी कि टाउन एरिया किशनपुर में बिजली लगायी जाने का कार्य कब तक पूरा होना था ? अब तक क्यों नहीं हो सका ? तथा भविष्य में कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री जयराम वर्मा—

टाउन एरिया किशुनपुर के विद्युतीकर की अभी तक कोई योजना नहीं थी। इसके विद्युतीकरण की दिशा में जांच पड़ताल की जा रही है और यदि संभव हुआ तो इसका विद्युतीकरण आगामी वर्ष में किया जायगा।

श्री रक्षपालसिंह--

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले भर के विद्युतीकरण का जो फैसला लिया है वह सरकार के स्तर पर विचाराधीन है अथवा जिले के स्तर पर और उस कमेटी में हम विधायकों को सलाह देने की कोई व्यवस्था है अथवा नहीं, और यह निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--

इस का सर्वे किया जा रहा। इस की कुछ खास शर्तें हैं। और उसके हिसाब से इसमें जो जिले हैं उनके कमिश्नर, डी० एम० एग्रीकल्चर आफिसर, इंडस्ट्रीज आफिसर और एरिगेशन आफिसर और साथ ही जिला बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन सब की सलाह से जहां पर से यह ट्रान्समिशन लाइनें गुजर रही हैं उस के आस पास की जगहों के लिये विचार किया जाता है। ताकि कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न १५ परसेंट-मिल सके। इसी सिद्धान्त के मुताबिक उस जिले में सर्वे किया जा रहा है।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या मंत्री जी जिले में पानी की अधिक आवश्यकता को देखते हुए लखायी, छानपुर, चुनिया, बिछौरा, के प्रत्येक ब्लाक में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ताकि फसल ठीक हो सके ? फतेहपुर जिला जो शून्य हो रहा है, वह पिछड़ा हुआ भी है और आप ने उसके लिये कोई कार्य नहीं किया, तो क्या सरकार इस को हर ब्लाक में शीघ्र बिजली देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस मापदंड में अगर वह आयेंगे तो जरूर उन को ले लिया जायगा और इसी दृष्टिकोण से उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

जिन जिलों में सन् १९६५ में लट्ठे लग गये हैं उन्हें १९६६ में बिजली दे दी जायगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह लट्ठे जो फतेहपुर में गड़े हुए हैं वहां नहीं पहुंच रही है तो और जगह क्या पहुंचेगी ?

श्री रक्षपालसिंह--

किशनपुर के बारे में कहा गया कि संभव होगा तो बिजली पहुंच जायगी, तो वह टाउन एरिया तो है ही, व्यापारिक केन्द्र भी है और वहां उद्योग के विकास की अच्छी खासी गुंजायश है, क्या उसमें निश्चित रूप से अगले वर्ष म बिजली पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपका सुझाव है, इसका ध्यान रखेंगे।

श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या मंत्री जी को पता है कि फतेहपुर जिले में तीन पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होने के बाद भी दो म्युनिसिपल बोर्ड, दो टाउन एरिया और एक गांव में, कुल ५ स्थानों का विद्युतीकरण हुआ है। पिछले वर्ष जो एक लिस्ट दी थी तो उसमें २,००० से अधिक आबादी वाले ६४ गांव थे उनमें बिजली पहुंचाने का लक्ष्य बताया था वह भी पूरी नहीं किया गया। जिले की बनी हुई समिति ने फतेहपुर के २४ गांवों में बिजली पहुंचाने के लिये संस्तुति की थी

लेकिन उनसें इस वर्ष भी बिजली न हीं लगी। मैं तो स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जब प्रदेश के अधिक गांवों में बिजली लग गयी है तो अपनी इस गति को तेज कर के फतेहपुर जिले को और अधिक बिजली देने का विचार करेंगे।

श्री गिरधारीलाल--

जैसा कि कई दफा कहा जा चुका है, यह तो धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है। हम तो चाहते हैं कि थोड़े से थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा गांव के अन्दर बिजली हम लगा सकें और पिछले वर्ष काफी उत्साह के साथ जैसी कि सब की ख्वाहिश है, गवर्नमेन्ट की भी ख्वाहिश थी और तेजी के साथ काम चलाया गया, लेकिन पैसे की कमी के वजह से उसमें कुछ शिथिलता आयी है और फूड प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा जोर देने की वजह से अन्य काम कुछ धीमे पड़ गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि फतेहपुर उपेक्षा का पात्र बन गया है, यह भय है।

श्री दीपनारायणसिंह--

यह देखते हुए कि पड़ोसी इलाहाबाद जिला और कानपुर दोनों का विद्युतीकरण हो गया है, आपने जो कमेटी बनायी है उसमें हमारे जिले के छहों फतेहपुर के सदस्यों को शामिल करके और १ महीने में उसकी रिपोर्ट लेकर क्या इस काम को अधिक तेजी से करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र इसे करेंगे।

श्री रक्षपालसिंह--

फतहेपुर को कानपुर से कोयले की तेज दाम वाली बिजली दी जा रही है और रिहंद वाली लाइन वहां तक पूरी हो गयी है, तो क्या फतेहपुर को रिहंद वाली सस्ती बिजली देने की कृपा करेंगे?

श्री गिरधारीलाल--

सस्ती और मंहगी का सवाल नहीं है। हम तो सूबे में एक ही दाम करने जा रहे हैं।

त्रिवेदीगंज विकास खण्ड में नलकूप की मांग

*१५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के विकास खंड त्रिवेदीगंज, तहसील हैदरगढ़ के कितने आवेदन-पत्र वर्ष १९६५ में ट्यूववेल तथा पावर कनेक्शन प्राप्त करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत् विभाग, फैजाबाद को मिले हैं? और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जयराम वर्मा--

बाराबंकी जिले के विकास खंड त्रिवेदीगंज तहसील हैदरगढ़ में वर्ष १९६५ में ट्यूब वेल तथा पावर कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र अधीक्षण अभियन्ता, जलविद्युत् विभाग, फैजाबाद को नहीं मिला है।

*१६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि १९६५ में हैदरगढ़ से बहुता, लालपुर, शिवनाम, हसवापुर खैरा आदि ग्रामों के विद्युतीकरण की भी मांग की गई ? यदि हां, तो इन गांवों को बिजली पहुंचाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां,

इस विषय में की गई कार्यवाही संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १००९ पर)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

श्रीमन्, जो सूची दी गयी है उसमें बतलाया गया है कि बहुता, लालपुर तथा शिवनाम ये ऐसी जगह हैं जो लाभ रहित हैं । विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष, श्री भरतनारायण, सचिव, का मुझे एक पत्र दिनांक २८ जून, १९६५ का, संख्या १४४९ है, प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने मुझे लिखा था कि इन गांवों को पिछले वर्ष यानी १९६५-६६ के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिये सम्मिलित कर लिया गया है और उनका विद्युतीकरण सन् ६६ तक हो सकेगा । तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि जो सूचना उन्होंने अब दी है यह सही है या जो मुझे श्री भरतनारायण द्वारा दी गयी थी वह सही है ?

श्री जयराम वर्मा—

इस वक्त तो सूचना यही आई है कि सर्वेक्षण होने के बाद यही पता चला कि यह गांव बिजली के लिये लाभ रहित हैं। अब जो बात आप कहते हैं इसको भी देख लिया जायेगा कि क्या बात सच है। अगर वहां लाभ होगा तो यह काम वहां जरूर किया जायेगा ।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन, बाराबंकी का ही सवाल नहीं है, हर जिले का सवाल है । जो भी प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं उनका पता नहीं चलता है । मैंने खुद २०-२५ प्रार्थना-पत्र दिये और आज तक उनका कोई पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ । जब सेक्रेटरी से पूछता हूं वह कहते हैं मंत्री महोदय के पास होगा, मंत्री से यहां जब पूछता हूं वह कहते हैं सेक्रेटरी के यहां होगा . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछिये । इस पर बहस नहीं हो सकती ।

श्री विजयपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा आफिस या क्लर्क मुकर्रर करेंगे जहां पर कि प्रार्थना-पत्र दिये जा सकें और वहां से हमको सूचना मिल सके या वह इस विभाग को पुनः श्री शांन्ति प्रपन्न शर्मा को देने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

अध्यक्ष महोदय, इस बात को तो स्पष्ट किया जा चुका है कि चूंकि शर्मा जी के भाई की मृत्यु हो गयी है इस कारण वह विभाग का कार्य नहीं देख रहे हैं । जहां तक प्रार्थना-पत्र देने का प्रश्न है वह हर जिले में जो कमेटियां बनी हुई हैं वहां दिये जा सकते हैं । इसके अलावा भी अगर माननीय सदस्य जरूरत समझते हैं तो वे उनको यहां भी दे सकते हैं । जिस तरह से पहले काम होता था वही अब भी हो रहा है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिवेदीगंज ब्लाक की जो एप्लीकेशन्स हैं, जिनका रुपया भी जमा है, इसकी सूचना क्या विभाग ने भेजी है ? यदि नहीं भेजी है तो उन व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने गलत सूचना दी है, जांच करने की कृपा करेंगे ।

श्री जयराम वर्मा---

त्रिवेदीगंज ब्लाक के किसी निवासी की ओर से कोई एप्लीकेशन्स सुपरिन्टेण्डिंग इन्जीनियर को नहीं मिली। इसके विषय में माननीय सदस्य के पास कोई तथ्य हों तो वे कृपया दें, उसकी जांच कराई जायेगी।

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में ए० टी० आई० को भत्ता

*१७---श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि गोरखपुर रीजन में ए० टी० आई० को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? और कब से ?

श्री मुजफ्फर हसन---

नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

सगड़ी क्षेत्र में श्री कमलाकान्त द्विवेदी को पावर कनेक्शन

*१८---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के नलकूप नं० ११, ग्रुप सगड़ी से कितनी दूरी पर मनिकाडीह के श्री कमलाकान्त द्विवेदी को विद्युत् शक्ति पहुंचाई गई है ?

श्री गिरधारीलाल---

१०२० फीट।

*१९---श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बता सकते हैं कि विद्युत् शक्ति पहुंचाने का कितना खर्च उनसे किन-किन मदों में वसूल किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---

श्री कमलाकान्त द्विवेदी से विद्युत् शक्ति देने में २,७०१ रु० ३५ पैसे वसूल किये गये और ५९९ रु० विभाग ने खर्च किये हैं।

*२०---श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)---

क्या यह सच है कि श्री कमला कान्त द्विवेदी से विभागीय कर्मचारियों ने तांबे के तार की कीमत वसूल किया और लगाया अलमोनियम का ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री गिरधारीलाल---

जी हां। कनेक्शन देते समय तांबे का तार उपलब्ध नहीं था और अलमोनियम का तार लगाकर श्री द्विवेदी को कनेक्शन दे दिया गया। खर्चे का रुपया श्री द्विवेदी जी के जमा किये हुए रुपयों में से काटकर बाकी धनराशि उनको वापस दे दी जायगी।

जालौन जिले में कथित नहर बोहरा कोंच

*२१---श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में साख कुठौन्द से निकलने वाली बोहरा कोंच माइनर पर दिनांक १ नवम्बर, १९६४ से ३१ मार्च, १९६५ तक कितने-कितने मजदूरों, बेलदारों या अन्य विभागीय मजदूर कर्मचारियों ने काम किया ?

श्री गिरधारीलाल--

जिला जालौन में कुठौन्द शाख से बोहरा कोच नामक कोई माइनर नहीं निकलती है। अतएव उक्त माइनर पर दिनांक १ नवम्बर, १९६४ से ३१ मार्च, १९६५ तक मजदूरों व बैलदारों या अन्य विभागीय मजदूर कर्मचारियों से काम कराने का प्रश्न हीं नहीं उठता।

*२२--श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपरोक्त स्थानों पर उपरोक्त दिनांकों में काम करने वालों की एक फर्जी मस्टर रोल तैयार की गई है? यदि उत्तर नहीं में है,तो जिन मजदूरों ने काम किया है उनका पता सहित नाम देने की कृपा करेंगे?

श्री गिरधारीलाल--

प्रश्न ही नहीं उठता।

*२३--श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि १९६४ के अक्टूबर से ३१ मार्च, १९६५ तक झांसी डिवीजन के किन अधिकारियों में कौन-कौन सी तारीखों में उपरोक्त माइनर पर दौड़ा किया और कौन-कौन से काम की जांच की तथा कौन-सी सवारी काम में लाई गई?

श्री गिरधारी लाल--

प्रश्न ही नहीं उठता।

नौगढ़ ब्लाक में शमसेरपुर नहर को बढ़ाने की मांग

*२४--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंडा नहर की माइनर शमसेरपुर, ब्लाक नौगढ़, तहसील चकिया, वाराणसी जो मिर्जापुर से आई है उसको बढ़ा कर गांव फरसा तक करने में क्या कठिनाई है जब कि टेलगूल फरसा तक बनी है?

श्री गिरधारीलाल--

प्रश्न में उल्लिखित माइनर को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे प्रस्तावित सिंचन क्षेत्र के करीब दुगुने से भी अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो रही है। अतः माइनर को बढ़ाना लाभप्रद नहीं होगा।

*२५--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने आदेश संख्या ५४०६, दिनांक ८ जून, १९६५ द्वारा गांव के किसानों को सूचना जिलेदार द्वारा दिया कि कृषक-गण गांव फरसा को सूचित करें कि जो प्रार्थना-पत्र शमसेरपुर माइनर को बढ़ाने का दिये थे उसके संबंध में शमसेरपुर माइनर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि टेल गूल मरम्मत की जरूरत है और ऊपर जो टेलगूल पाट दिया गया है उसे कैनाल मैजिस्ट्रेट के यहां के बन्ध हटाने का आदेश हुआ है? यदि हां, तो टेलगूल की मरम्मत की गयी कि नहीं और पटी हुई गूल को तथा बन्द को अब तक हटाया गया कि नहीं?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--

जी हां।

द्वितीय भाग--

टेलगूल में कृषकों द्वारा बांध लगाये जाने पर कृषकों ही कैनाल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दायर किये थे जिस पर अदालत से बन्धा हटा देने के आदेश हुये परन्तु अपील में सेशन

कोर्ट से यह आदेश रद्द कर दिये गये। अतः जो बंधा लगाया गया था उसे नहीं हटाया जा सका। गूल की मरम्मत का कार्य कृषक-गण ही करते हैं। अतएव कृषकों ने टेलगूल को, जहां पर बंधा लगाया गया था, थोड़ा मोड़ देकर नई गूल निर्माण कर ली, जिसमें पानी सिंचाई के लिये चल रहा है।

बांदा जिले में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*२६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बांदा का पाठा एरिया असिंचित है? क्या सरकार इस एरिया में बोरिंग कराके ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेगी?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां, पाठा एरिया अधिकतर असिंचित है, परन्तु वहां ट्यूबवेल सफल नहीं हो सकते, क्योंकि भूमि पथरीली व असमतल है।

*२७—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बांदा में बोरिंग द्वारा पानी पर्याप्त मिल सकता है?

श्री जयराम वर्मा—

बांदा जिले में अब तक किसी भी राजकीय नलकूप की बोरिंग नहीं करायी गई है क्योंकि प्रारम्भिक सर्वेक्षण से ऐसा मालूम होता है कि यहां नलकूप सफल नहीं हो सकते हैं।

श्री मतोलासिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि नहरी तहसील के आधे हिस्से में कोई पथरीली जमीन नहीं है, प्राईवेट तीन बोरिंग हो चुके हैं छः छः इन्च के और वे कामयाब हैं?

श्री जयराम वर्मा—

नहरी क्षेत्र जो जिले में है वह तो ट्यूबवेल लगाने लायक है और नहरी क्षेत्र में ट्यूबवैल लगाने नहीं हैं क्योंकि वहां नहर का इन्तजाम है और जो जिले में सात प्राईवेट ट्यूबवेल लगे हैं उनमें दो ही सफलतापूर्वक चल रहे हैं और वे नहरी क्षेत्र में हैं।

श्री मतोलासिंह—

कालिंजर क्षेत्र का पाठी एरिया असिंचित है, वह नहरी नहीं है। उसमें बोरिंग भी छा छः इंच का सफल हुआ है। क्या इसकी जानकारी आपको है और वहां बोरिंग कराने के लिये आप तैयार हैं?

श्री जयराम वर्मा—

इसकी जांच करा लेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय सस्दय ने कहा है कि सात ट्यूबवेल प्राइवेट चल रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी बांदा जिले में जहां पर ट्यूबवेल लग सकते हैं वहां लगाने या टेस्ट कराने का कष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि सात ट्यूबवेल हैं और वो काम कर रहे हैं।

श्री मतोलासिंह—

वो नहरी एरिया में हैं, चार पांच पाठी एरिया में हैं, छः २ इंच का बोरिंग है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मतौलासिंह जी, आप यह पूछ लीजिये कि सात कहां-कहां लगे हैं, जो चल रहे हैं ।

श्री मतौलासिंह—

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सात ट्यूबवेल कहां-कहां चल रहे हैं और किस-किस क्षेत्र में हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, सात ट्यूबवेल्स की जगह तो नहीं दी हुई हैं । सूचना यह है कि दो ही सफल हुये हैं और दोनों नहरी क्षेत्र में हैं । अगर नहरी क्षेत्र में नहीं होंगे तो उनकी जांच कराई जायेगी ।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

बांदा क्षेत्र में नरेंदे और तिहारे में बोरिंग काफी सफलता से चल रहे हैं और पिछली बार मुख्य मंत्री ने ऐसा ही पाठे में भी देखा था । तो क्या वहां सर्वे कराके और सरकारी बोरिंग कराके पानी देंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

माननीय सदस्य लिखकर दें दे तो एक्स्पलोरेटरी ट्यूबवेल्स एक्सपर्ट से सलाह कर लूंगा ।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

सरकार ने इन दो कुवों के बारे में मालूम किया कि ये कैसे सफल हुए और राजकीय क्यों नहीं होते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

मैं बतला चुका हूं कि वह पठारी क्षेत्र है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मंत्री अपने अधिकारियों को आदेश देंगे कि वह माननीय सदस्य से मिलकर जहां वे बतावें वहां देख लें ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह चुके हैं कि जहां बतावेंगे वहां अन्वेषण कराने के लिये तैयार हैं ।

*२८—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया ।]

*२९–३० श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—

[६ठे शुक्रवार के लिये प्रश्न ६५–६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सिंचाई विभाग में अधिकारियों को एक्सटेंशन

*३१—श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने १ जनवरी, १९६२ से ३० नवम्बर, १९६५ तक कितने अतिरिक्त सहायक चीफ इंजीनियर्स व चीफ इंजीनियर्स को एक्सटेंशन दिये हैं और इन एक्सटेंशन का आधार क्या था ?

श्री गिरधारीलाल—

सिंचाई विभाग में अतिरिक्त सहायक चीफ इंजीनियर का कोई पद नहीं है। चार अतिरिक्त चीफ इंजीनियरों तथा २ चीफ इंजीनियरों को एक्सटेंशन दिये गये। ये एक्सटेंशन अधिकारियों की कार्यक्षमता और उपयोगिता तथा प्राविधिक (टेकनिकल) कार्यकर्ताओं की कमी को ध्यान में रखते हुए जनहित में बिये गये हैं।

टेंटिया बांध की सुरक्षा

*३२—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में टेंटिया बांध को कटाव से बचाने के लिये अविलम्ब कोई योजना बनाई जा रही है जिससे यह बांध इस वर्ष की बरसात के पूर्व सुरक्षित किया जा सके? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है? और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जयराम वर्मा—

इस बांध को कटाव से बचाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है। तत्पश्चात् सिंचाई अनुसंधान संस्था, रुड़की, से परामर्श करके योजना बनाई जा सकेगी। अतः इस समय योजना की रूपरेखा देना सम्भव नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

सिंचाई अनुसंधान को बांध के बारे में भेजने की आवश्यकता क्यों हुई जबकि पिछले साल इस बांध को बचाने के लिये कुछ कार्य किया गया था?

श्री गिरधारीलाल—

यह जटिल समस्या पूरी तरह से काबू में नहीं आ पाई है। रुड़की रिवर्स इंस्टीट्यूट से मश्विरा करके उसे फिर से किया जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

अगले १५ जून के बाद नदी का पानी बढ़ना शुरू हो जायगा। तेजी से कटाव शुरू हो जायगा, जिसमें कम से कम ५० हजार की आबादी को खतरा है, तो क्या सरकार रुड़की से सलाह करके १५ जून के पहले उसे पूरा करा देगी?

श्री गिरधारीलाल—

मैं उनसे सलाह मश्विरा इसी दृष्टि से कर लूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरी सूचना है कि यह ६ महीने से रुड़की में पड़ा है। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां कब भेजा गया और कब तक आ जावेगा?

श्री जयराम वर्मा—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बाढ़ से पहले इस काम को पूरा कराने की कृपा करेंगे ताकि बांध की मरम्मत होकर गांव और फसल बच सकें?

श्री गिरधारीलाल—

मैं सलाह कर लूंगा कि हमारे मीन्स के अन्दर हो जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार सतर्कता बरतेगी कि वह काम बाढ़ से पहले ही पूरा हो जाय ताकि पब्लिक एक्सचैकर का पैसा बरबाद न हो ?

श्री जयराम वर्मा—

घाघरा के बहुत बड़ी होने के कारण उसका बहाव हटता रहता है। अभी तक जो काम किया वह सफल नहीं हो पाया, इसीलिये रिसर्च की सलाह लेने की जरूरत थी।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

वहीं पर राप्ती के किनारे मेंड़ी के पास आपने ठोकर लगाई थी वह गिर गई, तो क्या उसके कमजोर बांध की मरम्मत हो गई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न ३३ में पूछ लीजियेगा। उसमें शायद आ जायगा।

बांसगांव तहसील में बिजली

*३३—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के ग्राम डेरवा, मखटिया, परसिया, मुआैना, सेमरा, छपरा, मीठवा, सहुवाकोल, वैरिया, खुटभार, दबरी ग्रामों में जिनकी आबादी १ हजार से ऊपर है, बिजली कब तक दी जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

ग्राम खुटमार का विद्युतीकरण दिनांक २९-११-१९६३ को हो चुका है। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की दिशा में जांच पड़ताल की गई परन्तु किसी ग्राम का विद्युतीकरण इस समय सम्भव नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

सरकार ने सेमरा, छपरा गांव के बारे में कब जानकारी प्राप्त की कि वहां विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ?

श्री जयराम वर्मा—

धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार अविलम्ब आदेश देगी वहां भी बिजली पहुंचाई जाय ताकि लोग ट्यूबवेल और पंपिंग सेट लगाकर सिंचाई कर सकें

श्री जयराम वर्मा—

जहां सिंचाई के साधन [illegible] बिजली की वजह से कठिनाई हो रही है, वहां पहले ठीक किया जा रहा है। वैसे तो जहां बिजली पहुंच जायगी वहां लाभ हो ही जायगा लेकिन धनाभाव के कारण वहां इस समय संभव नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस योजना पर विचार कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र या जिले में बिजली लगायी जा रही है वहां उन क्षेत्रों में विधायकों से सलाह ले लिया करें ताकि वे कुछ ठोस सुझाव दे सकें ? क्या इस तरह के कोई आदेश जिला अधिकारियों को मंत्री जी देंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

जहां तक जिला अध्यक्षों का सवाल है, उनका हर एक विधायक से संबंध होता है। उनके जरिये से सब विधायकों के सुझाव आ सकते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जिस प्रकार से पिछड़ी जातियों के लिये मंत्री जी ने विशेष अवसर देने की बात को मान लिया उसी प्रकार से गोरखपुर और देवरिया में राप्ती के बाढ़ एरिया को पिछड़ा हुआ प्रदेश मान कर, विकसित इलाकों से रुपया निकाल कर इन क्षेत्रों को बिजली देंगे ताकि उनकी सिंचाई का प्रबंध हो सके ?

श्री गिरधारीलाल—

जिन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना गया है, उन क्षेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और उन पर विशेष धन भी खर्च किया जाता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि इस संबंध में जो भी धन खर्च करना, है, उस खर्चे में इन एरिया के इन गांवों को भी जोड़ने की कृपा करेंगे जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है ? क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में सर्वे करा कर कोई रिपोर्ट मंगवाने की कृपा करेंगे कि इन एरिया में सिंचाई का साधन उपलब्ध करने से कितनी फसल बढ़ जायगी ? और इसलिये उसका प्रबंध करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

इस समय तो उन्हीं स्थानों को बिजली दी जा रही है जहां से बिजली की लाइने पास हैं और थोड़े पैसे में अधिक लाभ होगा। जो स्थान लाइन से दूर पड़ते हैं, उनको इस समय बिजली देना संभव नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

छपरा और सेमरा आदि गांवों के बारे में क्या मंत्री जी यह जानकारी करायेंगे कि ये गांव बिजली की लाइन से कितनी दूर हैं और अगर पास हैं तो उनको क्या वे बिजली देने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

यह दिखवा लिया जायगा कि कितनी दूर है।

*३४—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ-काकोरी बस सर्विस की मांग

*३५—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से लखनऊ जिले के काकोरी कस्बे तक सिटी बस चलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सिटी बस चलाने की कोई योजना नहीं है।

सिद्धपुरा में बिजली

*३६—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले के सिद्धपुरा कस्बा में बिजली के कनेक्शन घरों के लिये तथा पावर कनेक्शन अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ? और कब तक कनक्शन मिल जायगें ?

श्री जयराम वर्मा—

एटा जिले के सिद्धपुरा कस्बे मे बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

श्री रामसिंह (मैनपुरी)—

कब तक ये कनेक्शन किस-किस को दिये जा चुके हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

अब तक शंकर लाल गुप्त, रामेश्वर दयाल शर्मा, अक्षय मिश्र को बिजली दी जा चुकी है। बाकी कुछ के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

श्री रामसिंह (मैनपुरी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धपुरा कस्बे में कितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये और वह किस मास में दिये और क्या कारण है जिस से वह अभी तक विचाराधीन हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

यह प्रार्थना-पत्र श्री कृपा शंकर, सुरेश चन्द्र, तारा चन्द और बाबू राम के प्राप्त हुये हैं और जैसे ही फारमेलिटीज पूरी हो जायंगी कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

गोंडा में जीप दुर्घटना

*३७—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दिनांक १२ दिसम्बर, १९६५ को गोंडा नगर में एक जीप चालक द्वारा कुचल कर २ लोगों की हत्या तथा कई लोग घायल कर दिये गये ? यदि हां, तो जीप वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को क्या क्षतिपूर्ति दी गई अथवा देने का विचार है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां।

एक प्राइवेट जीप से दुर्घटना द्वारा दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा तीन व्यक्ति घायल हुए। जीप चालक तथा जीप चालक के बराबर बैठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है। प्राइवेट गाड़ी होने के कारण सरकार द्वारा क्षति पूर्ति देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जीप दुर्घटना से जिन की मृत्यु हुई है क्या वे सरकारी कर्मचारी थे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उनके सरकारी कर्मचारी होने की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सुखदेव प्रसाद—

मेरी इत्तिला है कि उनमें से एक सरकारी चपरासी था और दूसरा एक मेहतर था जिनकी मृत्यु हुई है जीप से। जबकि एक दूसरा आदमी जो लाइसेंसी नहीं था और मालिक चला रहा था गलत तरीके से तो इस स्थिति में क्या सरकार उनको कोई क्षतिपूर्ति देने की कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस दुर्घटना के लिये सरकार तो किसी तरह से जिम्मेदार नहीं है इसलिये क्षतिपूर्ति का सवाल तो नहीं उठता। वह उस गाड़ी के मालिक पर या जो तीसरी पार्टी जिम्मेदार है उसके खिलाफ दावा कर सकते हैं।

श्री सुखदेव प्रसाद—

वह दोनों कर्मचारी जिन की मृत्यु हुई है उस समय सरकारी ड्यूटी पर जा रहे थे, तो क्या इस पर विचार कर के मंत्री जी उन को किसी प्रकार की सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

हमारी यह सूचना ही नहीं है कि वह सरकारी कर्मचारी थे, हमारे पास तो केवल उनके नाम आये हैं।

श्री होरीलाल यादव—

वह आदमी जो गैरलाइसेंसी था और जीप चला रहा था उसका कोई चालान किया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उनका चालान अभी अदालत में भेजा जा रहा है।

*३८—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया।]

*३९-४१—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

[५ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

समोठी-मैसरासी मार्ग पर प्रस्तावित पुल

*४२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहनपुर नाला, जिला एटा, पर ग्राम (१) समोठी से मैसरासी मार्ग ग्राम, (२) नौरी से गोढ़ा को जाने वाला मार्ग तथा (३) ग्राम सिरसौल से ग्राम मंगदपुर विकास खंड सिढ़पुरा मार्ग, जिला एटा, में पुल बनाने का कार्य कबसे प्रारम्भ किया जा रहा है तथा कब तक बन कर तैयार हो जावेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

समोठी मैसरासी मार्ग पर पुल बनाने का प्रस्ताव अभी अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में है। अतः यह कहना संभव नहीं है कि इस पर कार्य अब आरम्भ होगा और पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा। बाकी दोनों मार्गों पर पुल निर्माण उचित नहीं समझा गया है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि मोहनपुर नाले पर पुल न होने से रास्ते में बड़ी कठिनाई होती है और इसका सर्वे करा के कब तक मंत्री जी वहां पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

यह सब तो दिखलवा लिया गया है। उसका एस्टीमेट १२ हजार रुपये का है और जब रुपया उपलब्ध हो जायगा यह कार्य पूरा किया जायगा।

गाजीपुर जिले में बिजली के कनेक्शन

*४३—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सैदपुर, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर जिले के रेलवे पर बस-स्टेशनों के न बनाने से उन क्षेत्रों में पिछले अनेक महीनों से ट्यूबवेलों, पंपिंग सेटों तथा औद्योगिक इकाइयों को नये विद्युत कनेक्शन देना बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

जी नहीं।

गाजीपुर जिले में सैदपुर मुहम्मदाबाद के ट्यूब वेलों तथा पंपिंग सेटों को बिजली कनेक्शन देने का कार्य चालू है, लेकिन गाजीपुर विद्युत उप-गृह की क्षमता कम होने के कारण तथा ट्यूब-वेलों और पंपिंग सेटों के विद्युतीकरणों की बहुत अधिक मांग होने के कारण औद्योगिक इकाइयों को बिजली के कनेक्शन देना फिलहाल बन्द कर दिया गया है। उक्त विद्युत गृह की क्षमता बढाये जाने का कार्य चल रहा है और यह कार्य शीघ्र पूर्ण होने की आशा है। इसके पूर्ण होने पर औद्योगिक इकाइयों को भी बिजली दी जायगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि गाजीपुर जिला रिह्न्ड क्षेत्र में है और वहां पर बिजली की कमी नहीं है लेकिन चूंकि सैदपुर और मुहम्मदाबाद में सब स्टेशन नहीं बन पाये हैं, वहां के इंजीनियरों का कहना है कि जब तक वहां पर सब-स्टेशन नहीं बनेंगे तब तक बिजली नहीं दी जा सकती है ? तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर सब-स्टेशन क्यों नहीं बनाये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

माननीय सदस्य दूसरी बात कहते हैं। उसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन यही है कि औद्योगिक इकाइयों को अभी हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इस समय वहां जो बिजली घर है उसकी क्षमता इतनी नहीं है। जब इसकी क्षमता बढ़ जायगी तो हम इन औद्योगिक इकाइयों को भी बिजली देंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय मंत्री जी को शायद यह जानकारी नहीं है कि यह क्षेत्र रिह्न्ड एरिया में है और वहां की बिजली की क्षमता काफी है। लेकिन सैदपुर और मुहम्मदाबाद में सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर न लगने के कारण वहां पर पंपिंग सेट वगैरह को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर सब-स्टेशन वगैरह क्यों नहीं बनाये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

गाजीपुर से मुहम्मदाबाद और गाजीपुर से सैदपुर तक ३३ के० वी० लाइनों तथा ३३/११ के०वी० उपविद्युत गृह मुहम्मदाबाद और सैदपुर पर गाजीपुर उपविद्युत बनाये जाने का कार्य प्रगति में है। जैसे ही यह कार्य पूरा हो जायगा, वहां की औद्योगिक इकाइयों को भी बिजली के कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

गाजीपुर जो कि उद्योगों में पाइलैट प्रोजैक्ट एरिया है और सरकार ६ लाख रुपया प्रति वर्ष पाइलैट प्रोजैक्ट औद्योगिक यूनिट के लिये देती है लेकिन जितने भी वहां पर कारखाने खोले गये हैं, बिजली नहीं दी गयी है। क्या माननीय मंत्री जी उन्हें बिजली देने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

इसका तो जवाब दे दिया गया है। जो कारखाने या इंडस्ट्रीज ट्रांसमिशन लाइन के नजदीक होंगे और हमारे ये जो सब स्टेशन हैं वे पूरे हो जायेंगे, तो उनको भी बिजली दे दी जायगी।

गाजीपुर जिले में नलकूप

*४४—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि गाजीपुर में ऐसे कितने ट्यूबवेल हैं जो १०० एकड़ से कम की ही सिंचाई कर सकते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

गाजीपुर जिले में केवल एक ही ऐसा राजकीय नलकूप है जो १०० एकड़ से कम की ही सिंचाई की क्षमता रखता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी एक हाई लेविल कमेटी बैठाकर इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे कि केवल एक ट्यूबवेल में १०० एकड़ से कम पानी मिलता है, यह गलत है। वहां पर बर्जनों ऐसे ट्यूबवैल हैं जो ६, ७ या ८ एकड़ तक ही सिंचाई कर पाते हैं।

श्री जयराम वर्मा—

वहां पर ५ ट्यूववैल ऐसे हैं जो बिल्कुल फेल हो गये हैं, जिनको ठीक करना है। १०० एकड़ क्षमता वाला ट्यूबवैल एक ही है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एवरेज डिस्चार्ज क्या है? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एवरेज डिस्चार्ज से कम कितने ट्यूववैल काम दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तो यह है कि क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि गाजीपुर में ऐसे कितने ट्यूबवैल हैं जो १०० एकड़ से कम की सिंचाई कर सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

तो इस में डिसचार्ज ही आ जाता है। मैं यह पूछ रहा हूं कि ऐवरेज जो डिसचार्ज नलकूपों का गाजीपुर जिले में है, उससे कम जो हैं कितने नलकूप ऐसे हैं जो कम डिस्चार्ज दे रहे हैं।

(उत्तर आने में कुछ बिलम्ब होने पर)

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, हम लोगों का प्रश्न दूसरे दिन के लिये रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हम लोग जब प्रश्न कर रहे थे, तो प्रश्न का उत्तर आया नहीं उसी बीच में आप ने कह दिया कि प्रश्नों का समय समाप्त। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बीच में किसी प्रश्न का उत्तर न आवे तो वह कैसे समाप्त हो जायगा। या तो आप इस को दूसरे दिन के लिये ऐडजर्न कर दें, नहीं तो बीच में समय समाप्त नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

नियमों में जो समय निश्चित है वह पहला १ घंटा है। अब १ घंटे में वृद्धि करना हमारे अधिकार के अन्दर नहीं है और अगर प्रश्न के बीच में ही १ घंटा हो जाता है तो सदन का गौरव इसी में है कि जो नियम है उसका पालन हम करें। अब उस में अगर आप परिवर्तन करना चाहें तो कर लीजिये।

नोट—तारांकित प्रश्न ४४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलासिंह यादव—

एक प्रश्न हमने किया और उस का उत्तर नहीं मिला। तो या तो उस क्वेश्चन को एडजर्न कर देते और उसके बाद समय अगर खत्म हो गया तो खत्म कर देते। लेकिन उत्तर भी नहीं आया और क्वेश्चन भी एडजर्न नहीं किया। तो इस बीच में समय कैसे समाप्त होगा ?

श्री अध्यक्ष—

फर्क क्या पड़ता है, क्वेश्चन आप ने किया और उस का जवाब नहीं आया और वे क्वेश्चन जिनकी कि बारी नहीं आयी .....

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने देखा, हमारे जितने प्रश्न थे किसी का भी उत्तर जो विभाग से आया था, एक तो पूरा नहीं आया और हमने चैलेंज किया कि उत्तर सही नहीं है। तो क्या आप इंस्ट्रक्शंस दे देंगे मंत्री जी को कि कम से कम इसको चेक तो करा लें कि ऐसा उत्तर क्यों आ गया।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन करूंगा कि इसमें नियम ५० के अन्तर्गत आप फायदा उठा सकते हैं इस वास्ते कि दो स्थितियां हैं, एक तो यह कि प्रश्न पूरे नहीं हो पाये और दूसरे यह कि आप असंतुष्ट हैं। तो आप नियम का फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं।

*४५-४६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में बिजली

*४७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के खड्डपुर विकास क्षेत्र के बाढ़ एरिया के गावों में कब तक बिजली लग जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

देवरिया जिले के खड्डपुर विकास क्षेत्र के बाढ़ ऐरिया के गांवों का विद्युतीकरण वर्तमान समय में संभव नहीं है।

*४८—श्री चन्द्रबलीसिंह

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में सरकारी ट्यूबवेल कितने ऐसे हैं जिन्हें अभी तक बिजली नहीं दी जा सकी है ?

४८—श्री गिरधारीलाल—

देवरिया जिले में ३४ सरकारी नलकूप ऐसे हैं जिन्हें अभी तक बिजली नहीं दी जा सकी है।

*४९—श्री चन्द्र बलीसिंह—

क्या सरकार वर्तमान अन्न संकट के समय शहरी क्षेत्रों में पंखे तथा रोशनी के लिये दी जाने वाली बिजली में कटौती करके खेती के काम के लिय ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

फिलहाल कटौती की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती।

कानपुर जिले में बिजली तथा नलकूप

*५०—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले के विकास क्षेत्र बिल्हौर के अन्तर्गत अब तक सरकारी नलकूप बनकर तैयार हो गये हैं जिनसे सिंचाई का कार्य हो रहा है? तथा कितने ऐसे हैं जो बन चुके हैं या बन रहे हैं किन्तु कार्य नहीं कर रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल—

कुल १८ नलकूप लगाये गये हैं जिसमें से ११ कार्य कर रहे हैं। शेष सात नलकूपों का विद्युतीकरण बाकी है, इसलिये नहीं चल रहे हैं।

*५१—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विकास क्षेत्र बिल्हौर में कितने सरकारी कूप चौथी योजना में बनाये जावेंगे?

श्री गिरधारीलाल—

यह अभी निश्चित नहीं है।

*५२—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर में पनकी पावर हाउस जो बनाया जा रहा है वह कितनी ताकत का होगा? कब तैयार हो जावेगा?

श्री गिरधारीलाल—

पनकी पावर हाउस की बिजली उत्पादन की क्षमता ६४००० किलोवाट होगी। इसमें दो टर्बोजनरेटर होंगे, जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता ३२००० किलोवाट होगी।

ऐसा अनुमान है कि पहला टर्बोजनरेटर अपना कार्य सन् १९६६ की अन्तिम तिमाही में प्रारम्भ कर देगा। दूसरा उसके तीन माह पश्चात कार्य प्रारम्भ करेगा।

पटियाली विकास खण्ड में नलकूप लगाने की मांग

*५३—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम नरथर जिनौल, टपरी नगला, डालू नगला तथा सजन, विकास खन्ड पटियाली, जिला एटा. की हजारों बीघा भूमि असिंचित है? यदि हां, तो २ मील दूरी पर स्थित ग्राम पुरसारी के नलकूप संख्या एक से बिजली लाइन लेकर विभागीय नलकूप लगवाने की व्यवस्था करायेंगे ताकि उपरोक्त गांवों की भूमि की सिंचाई हो सके?

श्री गिरधारीलाल—

हालांकि प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों की भूमि असिंचित है परन्तु यहां पर नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में मौजूदा नलकूप का कार्य संचालन संतोषजनक नहीं है।

सितारगंज सड़क पर बस दुर्घटना

*५४—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नवम्बर, १९६५ के प्रथम सप्ताह में कोई बस सितारगंज रोड पर जिला नैनीताल दो जोड़ा नदी में डूब गई जिसमें २८ आदमी मर गये? यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—..

किसी नदी में नहीं बल्कि एक झरने (रिब्युलेट) में एक बस गिर गई थी। इसमें कुल १२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। पुलिस द्वारा घटना की जांच हुई, मामला अदालत में भेजा जा रहा है। अदालत के फैसले के बाद ही सही कारण का पता चलेगा।

*५५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि लाशों के शरीर से लगभग ४० हजार के गहने लूट लिये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

*५६—श्री नाथूराम शिक्षक (ज़िला इलाहाबाद)—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में बस सर्विस

*५७—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में जाने वाली कितनी राजकीय बसें चल रही हैं तथा उनमें से ऐसी कितनी हैं जो कि १ लाख मील से अधिक चल चुकी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

८१ बसें चल रही हैं जिनमें से ७२ ऐसी हैं जो १ लाख मील से अधिक चल चुकी हैं ।

*५८—श्री हिम्मतसिंह—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुरानी बसों के चलने के कारण इस जिले में अधिकांश बसें लेट हो जाती हैं, तो सरकार उनको बदलने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह सही नहीं है कि बसें पुरानी होने के कारण लेट हो जाती हैं । बसों के लेट होने के कारण मार्ग का खराब होना व रेलवे क्रासिंग पर उनका रुक जाना, आदि, हैं । अतः उनके बदलने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५९—६१—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

वीर विनायक दामोदर सावरकर के निधन पर शोकोद्गार

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों तमाम देश में वीर सावरकर के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ । वीर साबरकर के निधन से हमारे देश की एक महान विभूति उठ गई । गांधी जी के प्रादुर्भाव होने से पहले वीर सावरकर ने हमारे देश को स्वतंत्रता के लिये बहुत नवयुवकों को प्रेरित किया । वीर सावरकर का साहस, उनका आत्म उत्सर्ग, उनकी देश भक्ति और देश को दासता की श्रृंखला से मुक्ति दिलाने के लिये उनके हृदय में प्रज्वलित अग्नि ने देश के नवयुवकों को नया मार्ग दिखलाया और संसार में क्रान्ति के इतिहास में वीर सावरकर जिस वक्त बन्दी बनाकर जहाज पर ले जाये जा रहे थे और समुद्र में कूद कर जिस प्रकार उन्होंने बचने का प्रयास किया वह एक बड़ा रोमांचकारी अंग बन गया है । यद्यपि वीर सावरकर दो वर्ष से स्वस्थ नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे, रोग शय्या पर पड़े हुए थे और उनका निधन आकस्मिक नहीं था, परिपक्व आयु पर निधन हुआ, किन्तु उनके उठ जाने से देश को बड़ी क्षति हुई है । कुछ समय से वीर सावरकर ज्यादा सक्रिय भाग नहीं ले रहे थे और जिस प्रकार उनका जीवन था उससे विदित होता है कि वे प्रायः अपने को पीछे रखते थे । वीर सावरकर निहायत देशभक्त थे, बड़े प्रभावशाली थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे और इस देश के सारे जीवन में, देश के स्वतंत्रता सग्राम के अन्दर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया । आज वीर सावरकर किसी दल विशेष के नहीं हैं बल्कि तमाम देश को उनके त्याग और तपस्या पर गर्व है । उन्होंने अपने देश के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और अपने त्याग और तपस्या के जरिये स्वतंत्रता सग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पन्ना जोड़ा है । इसलिये हमारी आइन्दा आने वाली सन्ततिवीर सावरकर की सदा ऋणी रहेगी और उनसे प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी । मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आदरणीय मंत्री महोदय ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे विरोधी दल को और अपने को भी सम्बद्ध करता हूं । वीर सावरकर महान देश भक्त, साम्राज्यवाद के घोर विरोधी थे। वह बहुत बडे क्रांतिकारी भी थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि अपने जीवन के प्रारम्भ काल से ही अपनी युवावस्था से ही जीवन के सारे सुख त्याग दिये और उनके हृदय में भारत को स्वतंत्र कराने की आग प्रज्वलित हुई । जब वह विद्यार्थी थे तभी उन्होंने एक संस्था कायम की और उस संस्था का नाम था "अभिनव भारत" । उसमें बहुत से सदस्य ऐसे बनाये गये जिन्होंने प्रण किया कि वे अपनी जान भारत को स्वतंत्र करने के लिये दे देंगे । जब वह फर्ग्युसन कालेज से निकलकर इंग्लैण्ड गये बैरिस्टरी करने के लिये तो इस नीयत से गये कि बाहर रह कर अथवा अन्दर रह कर किसी भी प्रकार भारत को वह स्वतंत्र करा सकें । वहां उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी कायम की ।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने की । १८५७ के स्वतंत्रता सग्राम को अग्रेजों ने सिपाय म्युटिनी का नाम दे दिया और उसका विजय दिवस मुकर्रर किया गया १९०५ में । जितने राजनीतिक दल थे सभी उदार दल थे । कांग्रेस भी उदार दल थी । उनके साहस का परिचय मिलता है इसी से कि उन्होंने एक इतनी जबरदस्त आवाज उठाई कि अग्रेज जिस दिन के लिये विजय उत्सव मना रहे थे सिपाय म्युटिनी कह कर वीर सावरकर ने उस दिन को प्रथम स्वतत्रंता संग्राम की संज्ञा दे कर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की । उनका लक्ष्य हमेशा यही रहा कि किसी तरह से भारत माता की दासता के बंधन टूटें । जब वह जहाज पर लाये गये तो जहाज से कूद गये और फ्रांस के तट पर निकले । गोलियों की बौछार के नीचे और समुद्र में डुबकी लगाते हुये वह वहां पहुंचे थे । वहां से वह वापस लाये गये तो तीन भिन्न-भिन्न अभियोगों के अन्तर्गत उनको ५० वर्ष की सजा हुई और उनको मांडले जेल भेजा गया। इसका भी एक ऐतिहासिक प्रसंग है । जेल के अन्दर उनकी बीवी मिलने गयी । तब उन्होंने कहा कि तुम्हे दुखी नहीं होना चाहिये । जीवन का यह अंग कि लड़के, लड़कियां पैदा करना, मकान बनाना, जीवन को सुखमय बनाना, इसकी हमने होली मनाई है । हमने दूसरे जीवन के स्वप्न को देखा है । अगर उस प्रकार से हमारे देश का निर्माण हो जाय तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया है । उन्होंने कभी साहस नहीं खोया और वह घूम कर बैल की तरह से तेल पेरते थे । इस प्रकार की घोर यातनाओं को सहने के लिये उन्हें जेल भेजा गया ।

दूसरी बात यह है कि जेल में रह कर उन्होंने काव्य की रचना की । वे साहित्यकार थे, नावलिस्ट थे और कविता भी करते थे। उन्होंने जेल में कई रचनायें कीं। जब उनको जेल में कलम दावात नहीं मिली तो उन्होंने जेल की दीवार पर लिख लिया और उसे कंठकर लिया। उन्होंने अनेक चीजें लिखी । उनका त्याग और बलिदान का जीवन था । उनका लक्ष्य था कि हमारी मां स्वतंत्र हो और हमारा भारतवर्ष अखंड रहे । उन्होंने इस लक्ष्य को लेकर संसार के एक कोने में रह कर सारा जीवन व्यतीत कर दिया । लेकिन अपने लक्ष्य से

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जरा भी विचलित नहीं हुये । वह लौह विचार के लौह पुरुष थे । उन्होंने इस बात की कभी चिन्ता नहीं की कि उनके कितने फालोअर्स रह गये हैं । सारे जीवन भर उनका यह ध्येय चलता रहा ।

उनमें एक बड़ी भारी विशेषता थी कि उन्होंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया । आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, सचमुच में उनका जीवन हमारे युवकों के लिये प्रेरणादायक है । उन्होंने अपने सामने एक लक्ष्य रखा था कि मां को स्वतंत्र करने के लिये, देश की सेवा करने के लिये और राष्ट्र की सेवा करने के लिये सारे जीवन के सुख को इसी में मिला दिया और अपने भौतिक जीवन के आनन्द को तिलांजलि देनी । उन्होंने इसको कर के दिखा दिया । मैं शब्द नहीं ढूंढ़ रहा हूं कि किन शब्दों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूं । हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र बना रहे, भारत अखंड हो और हम इसके लिये त्याग और बलिदान करने के लिये सदैव तैयार रहें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार तक हमारे दल की ओर से समवेदना पहुंचा देने की कृपा करें ।

*श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक वीर सावरकर का सम्बन्ध है, थोड़ा सा मेरा उनका साथ १९४२ में हुआ था । वीर सावरकर उन लोगों में से थे कि शायद ही इस युग में इस तरह का नेता दूसरा हुआ हो, क्योंकि मैंने उनको निकट जाकर देखा था । वे बड़े स्पष्टवादी थे और देश की अखंडता के लिये जिस तरह से उनके हृदय में आग जलती थी उसका परिचय मुझे उस समय हुआ जब देश के विभाजन की बात हुई थी । उन्होंने एकदम तय किया कि हमें हिन्दू सभा ज्वाइन करना है । इस प्रकार से वे क्रान्तिकारी जीवन के बाद हिन्दू सभा में आये । जहां तक उनके विचारों का सवाल है, वे अपने विचारों पर दृढ़ रहे और स्पष्ट है कि इस प्रकार के नेता यदि देश में होते तो यह देश इस तरह से खंडित नहीं होता क्योंकि मरते समय, जो उन्होंने अपनी विल की है, उसमें उन्होंने बिलकुल साफ लिख दिया है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी लाश का कोई प्रदर्शन न किया जाय और हमारी मृत्यु पर देश में कोई हड़ताल न की जाय । यह चीज है कि हमको उनके कर्म से सबक लेना चाहिये न कि केवल प्रस्ताव पास करके इसको समाप्त कर दें । उनकी मृत आत्मा के साथ मेरा और मेरी पार्टी का हृदय है और मैं चाहूंगा कि मेरी और मेरी पार्टी की ओर से उनके परिवार तक समवेदना पहुंचाने की कृपा की जाय ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय बनारसीदास जी ने विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन, वीर सावरकर का जीवन बहादुरी का क्रान्तिकारी जीवन रहा है जो कि भारत के नौजवानों को सदा प्रेरणा देता रहेगा । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से, ऐसे वीर बहादुर और क्रान्तिकारी नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी भावनायें उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, वीर सावरकर के बारे में ज्यादा कहना इसलिए उचित नहीं समझता कि उनके बारे में देश का ऐसा कौन नौजवान है जो भली भांति परिचित न हो ? जितने उच्च कोटि के नेता थे और थे उनमें वीर सावरकर देश प्रेम में पीछे नहीं थे । उनके सम्बन्ध में माननीय विरोधी दल के नेता ने जो बातें कहीं बहुत थोड़ी हैं । उनका जीवन मुकम्मिल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इतिहास है । मैं अपने आपको और अपने दल को माननीय बनारसीदास और नेता विरोधी दल से सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे दल की तरफ से उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, अखबार में यह अफसोसनाक खबर पढ़ कर कि वीर सावरकर का एक काफी लम्बी बीमारी के बाद इन्तकाल हो गया बड़ा अफसोस हुआ । इसलिये कि जबसे मैंने अखबार पढ़ना सीखा उसी वक्त से वीर सावरकर चाहे किसी भी खयालात के आदमी थे, लेकिन अखबार में उनका नाम बराबर आता था । उनका एम यही था कि भारतमाता आजाद हो । बहरहाल, आजादी के बाद में वक्त-वक्त पर अपने खयाल पेश करते रहे, हालांकि ८२ साल की उम्र के बाद उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन नौजवान आदमी यह महसूस करता है कि एक ऐसा नेता आज हिन्दुस्तान से उठ गया जिसके अल्फाज और खयालात से कुछ रोशनी आइन्दा के लिये भारतमाता की आजादी को बरकरार रखने के लिये ले सकते थे । उनके जो खयालात और अमल रहा इस दौरान में, उनको सामने रख कर आज हिन्दुस्तान के हर नौजवान का, हिन्दुस्तान में रहने वाले हर शख्स का फर्ज हो जाता है कि भारतमाता की आजादी कायम रखने के लिये जितनी कुर्बानियां वीर सावरकर ने दीं उनकी मिसाल सामने रखें । इसलिये मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से पूरा इजहारे गम करता हूं और मंत्री जी और नेता विरोधी दल से अपने खयालात को शामिल करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके परिवार तक मेरी और मेरे दल की तरफ से श्रद्धांजलि भेज दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

जो विचार वीर सावरकर जी के सम्बन्ध में इस सदन में व्यक्त किये गये हैं उनसे अपने आपको मैं सम्बद्ध करता हूं । प्रायः जो इस सदन के सदस्य न हों उनके सम्बन्ध में चर्चा उनके देहावसान के अवसर पर नहीं करते । किन्तु वीर सावरकर उन व्यक्तियों में थे जिनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वे हमारे संग्राम और क्रान्तिकारी युग के अग्रणी थे । तारुण्य काल में जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा, स्नातक होने के पूर्व ही उन्होंने अपने देश और मातृभूमि, जननी जन्मभूमि के लिये अपने आपको समर्पित किया और उस साधना में आग से खेलना मंजूर किया तथा जीवन के सारे सुखों का परित्याग किया । ऐसे क्रान्ति के अग्रदूत के लिये हमारे हृदय में आदर, सम्मान और निष्ठा की भावना होना स्वाभाविक है । यह ठीक है कि गांधी युग में हमने क्रान्तिकारी दृष्टिकोण का परित्याग किया तो भी मैं समझता हूं कि जिन्होंने केवल अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिये बिना स्वार्थ भाव के एक पथ ग्रहण किया और अपने आपको उसके ऊपर न्योछावर किया, वह हमारे आदर के पात्र हैं । जिस तरह से हम आज अब्दुल हमीद की बात करते हैं, तारापोरवाला की याद करते हैं, उसी तरह से हमारा कर्त्तव्य है कि हम वीर सावरकर तथा अन्य उनके तुल्य व्यक्तियों को अपने इतिहास में अन्तर्निहित कर लें और उनके प्रति सदैव श्रद्धा रखें और हमारे देश के बालक और जवान उनके जीवन से सदा प्रेरणा प्राप्त करते रहें ।

इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आदरणीय सदस्यों से कहूंगा कि वह अपने स्थान पर एक मिनट मौन खड़े होकर उनको सामूहिक श्रद्धांजलि भेंट करें ।

(सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर १ मिनट के लिये खड़े हुए ।)

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने केवल एक माननीय रामकिशोर वर्मा जी की सूचना को स्वीकार किया है, जिसे विकास मंत्री जी की सेवा में कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं । अन्य नियम ५२ की जो सूचनायें हैं, उनको मैं स्वीकार नहीं कर सका हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

मैंने, श्रीमन्, जिला परिषद् के कर्मचारियों के बारे में एक सूचना दी थी, वह असन्तुष्ट हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जो विकास का काम करते हैं और जिस विकास के काम पर सरकार इतनाअधिक धन खर्च करती है, उसके कर्मचारी उपेक्षित रहे हैं। उस सम्बन्ध में आपने क्या विचारकिया। न हो सके नियम ५२ में तो, सिर्फ वक्तव्य के लिये ही माननीय मंत्री जी के पास भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, यह चीज तो बजट विवाद में ही आ सकती है। आपकी सूचना को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि उसे नियम ५२ में लिया जाता।

श्री राजेन्द्रसिंह—

बजट के अलावा उसको वक्तव्य के लिये भेज दें, तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि उनका बहुत महत्व है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो दिया है, उसे भी आप वक्तव्य के लिये भेज दीजिये, बड़ा खास मामला है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, नियम ५२ में हो या कोई भी प्रश्न हो, वह सुनिश्चित होना चाहिये। ऐसे वाक्य कि "कुछ लोग ऐसे हैं" "कहीं ऐसा हुआ है" इस तरह की बातों पर नियम ५२ नहीं आ सकता। जो निश्चित नहीं होगा, उसे हम नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं ले सकते हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत कप्तानगंज के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने के बारे में दिया था, वह गन्ना पेरा नहीं जा रहा है। ५०–६० लाख मन गन्ना वहां पर पड़ा हुआ है कटा हुआ, जो बेकार हो रहा है, उसे दूसरी मिल में दे दिया जाये, ताकि समय पर उसकी पेराई हो सके। इसके कारण वहां के किसानों में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

किसानों के पास ५०–६० मन गन्ना बिना पेरे हुये पड़ा हुआ है, तो यह तो एक ही दो किसानों के पास भी पड़ा हो सकता है, यह प्रश्न कोई लोक महत्व का नहीं हो सकता। अतः ऐसे प्रश्न नियम ५२ में कैसे स्वीकार हो सकते हैं?

श्री बांकेलाल—

नहीं, ५०–६० लाख मन है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें ५०–६० मन ही लिखा हुआ है, मैं किसे ठीक समझूं?

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की कुछ स्थायी समितियों की नामजदगी की तिथि मैंने ३ मार्च, १९६६ निश्चित की थी, किन्तु अब विभिन्न नेताओं का हस्ताक्षरित निवेदन मेरे पास पहुंचा है कि इस तिथि को ३ मार्च, १९६६ से बढ़ाकर १३ मार्च, १९६६ कर दिया जाये।

१३ मार्च को तो रविवार है, इस वजह से १२ मार्च कर दिया जाय या १४ मार्च कर दिया जाय।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

१४ मार्च कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अब उसमें जो १३ मार्च नाम निर्देशन के लिये था उसे १४ कर दिया गया, सूक्ष्म परीक्षा के लिये १५ या १६ मार्च और नाम वापसी के लिये १७ मार्च रहा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय संसदीय मंत्री को चाहिये कि वे निश्चित रूप से माननीय नेता विरोधी दल तथा और सब लोगों से कार्यक्रम के लिये कोई तारीख तय करके तब निश्चित रूप से उसकी घोषणा करें ताकि बार-बार आपको तारीखें न बढ़ाना पड़ें क्योंकि इस तरह से समय-समय पर आपको तारीखें बढ़ानी पड़ती हैं। गत वर्ष भी ऐसा हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

अब इस समय तो, माननीय नेकराम जी, इसी तारीख को स्वीकार कर लें, अगर आगे चल कर उस तारीख में कोई असुविधा हुई तो उसे तब्दील कर लेंगे।

(कुछ ठहरकर)

तो अब इस तरह से कार्यक्रम रहा :—

१४ मार्च को नाम निर्देशन, १५ मार्च को सूक्ष्म परीक्षा और १७ मार्च को नाम वापसी और यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो वह २४ मार्च को होगा।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं, अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३७, सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री वित्तीय वर्ष १९६६-६७ का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे ।

(श्री जगनप्रसाद रावत के खड़े होने पर)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् । इस सार्वजनिक विभाग द्वारा सड़कों और भवनों के विकास सम्बन्धी सिंहावलोकन पुस्तिका आज सुबह ही हम लोगों को दी गयी है । श्रीमन्, हमेशा हर विभाग को यह आदेश दिया गया है कि कम से कम तीन दिन पहले हम लोगों को विभागीय विवरण सम्बन्धी साहित्य मिल जाने चाहिये लेकिन अभी तक ऐसी परिपाटी चली आरही है कि जिस रोज बजट पेश होता है उस रोज ही वह देते हैं ताकि माननीय सदस्य इनको न पढ़ सकें और न तो सही माने में सम्बन्धित विभाग के ऊपर चर्चा ही हो सके । इसलिये आपसे मैं यह चाहूंगा कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें कि भविष्य में ऐसी चीज न हो और हमेशा कम से कम ३ दिन पहले वार्षिक विवरण सम्बन्धी पुस्तिका हम लोगों को मिल जाया करे ताकि हम लोग उसे पढ़ सकें और उसके ऊपर अपने विचार सदन में रख सकें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय मंत्री, जरा इस पर ध्यान रखें कि अगर ३ दिन पहले न हो सके तो एक दिन पूर्व तो जरूर ही मिल जानी चाहिये, यह शार्टेस्ट पीरियड है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, तीन दिन के पहले तो वह निश्चित रूप से छप चुकी है, फिर आप क्यों उसमें कटौती करते हैं कि ३ दिन के बजाय १ दिन कर दिया जाय ? हम लोग इसके लिये तीन दिन में एक घंटा भी कम करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अगर आप एक दिन कर देंगे तो ये शाम को ५ बजे ही उस दिन रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

एक दिन का मतलब यह है कि बहस शुरू होने के कम से कम २४ घंटे पहले तो होना ही चाहिये ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

श्रीमन्, मैंने असेम्बली विभाग को तो कल ही भेज दिया था, लेकिन आज माननीय सदस्यों को मिला है, इस पर मुझे खेद है । आगे से मैं यह प्रयत्न करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

यही तो टम्बेश्वर प्रसाद जी कहते हैं कि आप ५ बजे या ४ बजे ही उस दिन रखेंगे । इसलिये आगे से इसका ध्यान रखा जाय ।

श्री जगनप्रसाद रावत—

आगे से इसका ध्यान रखा जायगा ।

यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चारों अनुदानों को एक साथ ही रख दूं ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री जगनप्रसाद रावत—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत १४,४४,४६,७०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत ९६,७०,९०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत २,२४,८५,३०० रुपये की मांग, वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १८,६६,३४,६०० रुपये की मांग, वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस वर्ष के बजट के लिये कुछ कहने से पूर्व कुछ शब्दों में ६५–६६ के बजट और उस सिलसिले में जो कार्य हुये उनको निवेदन करूंगा । ६५–६६ में कुल बजट हमारे रिपेयर्स, मेंटिनेंस और कार्य करने के लिये २६ करोड़ २७ लाख का था । इसमें से ६९५.८४ लाख भवनों के लिये था और इनमें से ४२८.८२ लाख और योजनेतर भवनों के लिये २६७.०२ लाख था । इसी तरह से सड़कों के लिये १,३२२.७१ लाख था । इसमें योजनागत सड़कों के लिये ७६७.९६ लाख रुपये था और योजना इतर सड़कों के लिये ५५४.७५ लाख

था। कुम्भ मेले के लिये १८.८४ लाख था। मरम्मत और रखरखाव के लिये ५६३.८८ लाख था जिसमें से भवनों के लिये १८.०४ लाख, सड़कों के लिये ५३९.०८ लाख और मुतफर्रिक के लिये ६.७६ लाख था। योजनागत भवनों के लिये ४२८.८२ लाख था। उसमें से इस वर्ष के अन्त तक ३२० लाख रुपये खर्च करने का हमारा अनुमान है। इसमें से बचता है १०८.४६ लाख, यह हम खर्च नहीं कर पायेंगे। इसका कारण यह है कि भिन्न-भिन्न विभागों से जो कार्य हमारे पास आते हैं उनके अधिकांश के ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल हमें नहीं मिले। दूसरी बात यह है कि हमको भवन निर्माण के लिये जमीन मिलने में भी कठिनाइयां हुई। अब जो योजना इतर भवनों के लिये २६७.०२ लाख का था वह हम इस साल के अन्त तक पूरा का पूरा खर्च कर लेंगे। इसमें मेरठ और इलाहाबाद मेडिकल कालेजेज, कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनने हैं और बाबूगढ़ मेरठ में फ्रीडम फ्राम हंगर कैम्पेन पोल्टरी प्राजेक्ट के लिये कुछ इमारतें बननी हैं।

अब सड़कों के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि ७६७.०९६ लाख का हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्लान था। इसमें से हम सब रुपया खर्च कर लेंगे केवल ६० लाख रुपया खर्च नहीं होगा और वह इसलिये नहीं खर्च कर सकेंगे क्योंकि हमें रोड रोलर्स नहीं मिले और सीमेंट की भी दिक्कत शुरू में थी और वह समय पर नहीं मिल पाया। ४०० मील सड़कें बननी थीं और इस साल तक ३५५ मील सड़कें बनीं। २० पुल बनने थे, इनमें से १६ पुल हो जायेंगे। पुलों के सिलसिले में जो काम बच गया वह इसलिये कि, जैसे मैंने निवेदन किया, सीमेंट की हमारे यहां कमी थी।

अब जो योजना के बाहर सड़कें थीं उसके लिये हमारे पास ५५४.७५ लाख था। इसको हम पूरे का पूरा खर्च कर लेंगे। ६१-६२ में जब तीसरा प्लान शुरू हुआ था तब हमारे सड़कों की लम्बाई १४५०० मील थी और ६६ के मार्च तक वह लम्बाई १६६६० मील हो जायगी यानी इस तृतीय, पंचवर्षीय योजना में हम २ हजार १ सौ मील नई सड़कें बना पायेंगे। इस बीच में ८० पुलों को बनाया गया है अगर १६०० मील लम्बी सड़को का नये तरीके से सुधार किया है और अभिनवीकरण किया है। इस साल हमने अयोध्या में सरयू के ऊपर भी पुल पूरा किया है। अयोध्या के इस पुल के महत्व को सभी माननीय सदस्य जानते हैं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक का मार्ग इस पुल के न होने की वजह से पूरे तरीके से उपयोगी नहीं हो सकता था। इस कारण हर प्रकार से यह महत्वपूर्ण पुल बना है। इसके साथ-साथ रामपुर में कोसी का जो पुल बनाया गया है; वह भी थोड़े समय में पूरा किया गवा है।

कुम्भ मेले के लिये प्रारम्भ में जो हमको काम सौपा गया था वह काम केवल १८ लाख रुपये का था। हमको वहां पर २ पौन्टून ब्रिज बनाने के लिये कहा गया। २ पौंटून वहां पर पहले से थे लेकिन आशा वह की गई कि यात्रियों की संख्या इस वर्ष बहुत होगी तो बजाय २ के ६ पौन्टून ब्रिज बनाने की बात निश्चय हुई। इस प्रकार से २ और नये ६ पौन्टून ब्रिज मिलाकर कुल ८ पौंटून ब्रिज बनाने पड़े और उनको पूरा किया गया। इन पौन्टून बिज का इस्तेमल लाइट विहिकुलर ट्रेफिक के लिये होता है। लोडेड विहिकिल्स इनके ऊपर से अलाउड नाहीं है। लेकिन वहां पर इस बात का अनुभव किया गया और लोडेड ट्रक्स को उनके ऊपर से अलाउ किया और इसमें हमको सफलता मिली। आगे भी हम इस बात की कोशिश करेंगे कि पौन्टून ब्रिज से लोडेड ट्रक को पार ले जायं। इस काम में १८ लाख रुपया पहले बजट में रखा गया था लेकिन बाद में वह जाकर ११२ लाख हो गया। हालांकि समय कम था लेकिन हमारे कर्मचारियों की मेहनत से यह काम थोड़े समय में ही पूरा हो गया। इसलिये इस कार्य के लिये मैं उनको जरूर धन्यवाद दूंगा।

[श्री जगनप्रसाद रावत]

पायलेट प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पायलेट प्रोजेक्ट का काम हमको चार जिलों में करने के लिये दिया गया। वे जिले थे गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया और आजमगढ़। इसके लिये ७० लाख रुपया इस करेन्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको खर्च करने के लिये दिया गया लेकिन शुरू में हमें यह पता नहीं चल पाया कि कितना रुपया हमको खर्च करना है। इसलिये इस रुपये को बजट में नहीं रख सके। इस रुपये की स्वीकृति गवर्नमेंट आफ इंडिया से आती है। जब तक वह पूरे आंकड़े हमारे पास न भेज दें तब तक हम उसको बजट के अन्दर नहीं रख सकते हैं। जब वहां से वे फिगर आ जाते हैं तभी हम उनको बजट में रखते हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमने इस की काफी कोशिश की और काफी खर्च किया। १० मील नई सड़क बनाई और १६ मील जो मौजूदा सड़क है उसको रिकंस्ट्रक्ट इस करेन्ट ईयर में कर लेंगे। यह जो पायलेट प्रोजेक्ट की स्कीम है इसके लिये कुल रुपया १३ करोड़ ५० लाख इसमें रखा गया था। १९६४-६५ में इसमें केवल हमको २० लाख रुपया मिला। ६५-६६ में यह पता नहीं चल पाया कितना रुपया मिलेगा लेकिन फिर भी इस बात की हमने कोशिश की और आखिर में हमको ७० लाख रुपया मिला जो हमने खर्च किया। इसके साथ-साथ हमारा काम इसलिये नहीं हो पाया कि जब योजना मन्जूर होती है तो उसके बाद हम उसको बजट में रखते हैं। फिर जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, तब काम शुरू होता है। दूसरे फाइनेन्शल ईयर में जो रुपया मिलता है, जहां से रुपया आता है उसकी गति मन्द है। उसका कारण आपके सामने स्पष्ट है। जो पिछले साल भर में इमरजेन्सी आई उसके कारण वहां से रुपये का प्रवाह हमारा अवरुद्ध हुआ तो उसका असर यह पड़ा कि उसके कारण रुपया खर्च नहीं कर पाये अधिकांश माननीय सदस्य जो योजना में रुपया लग रहा है या सड़कों का जो नाम उनमें लिखा हुआ है उनको देख कर अनुमान लगाते हैं कि हमने कितना काम किया, लेकिन इसके बाद भी कुछ तरीके हैं, कुछ नियम है कि जिनके आधार पर रुपया खर्च किया जाता है और उनके कारण कमी यदि वे संतुष्ट नहीं हो पाते तो मेरी प्रार्थना है कि वे मुझ से बात कर लिया करें। हर समय विभाग की गलती से ही पूरे का पूरा काम होना संभव नहीं होता, उसके और दूसरे कारण भी हो सकते हैं।

अब मैं थोड़ा सा जिक्र लैटरल रोड का करना चाहता हूं। यह सड़क बरेली से अमीनगांव तक बन रही है और उस पर ३७ करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें से ४ करोड़ ५२ लाख रुपया इस साल व्यय किया जायगा। इसका फील्ड सर्वे बहुत जरूरी था जो ४०० मील का हमने पूरा कर लिया है और २४० मील की भूमि अर्जन की प्रोसीडिंग्स भी हमने पूरी कर ली है। इसके अलावा मिट्टी डालने आदि का काम भी हमने काफी पूरा कर लिया है। इस योजना में ५ बड़े पुल होंगे, ३८ बीच के साइज के पुल होंगे और ४८ छोटे पुल होंगे। इन ५ बड़े पुलों पर काम शुरू हो गया है और मीडियम साइज के जो पुल हैं उनमें १४ पर काम शुरू हो गया है और बाकी और जगह भी हम जल्दी ही काम शुरू करने वाले है। इसमें भी एक कठिनाई हुई। हमको इस योजना के लिये १०९ रोलर्स की जरूरत थी। हमको अभी तक मुश्किल से ६० रोलर मिल पाये हैं और बाकी रोलर्स बराबर प्रयत्न करने पर भी हम हासिल नहीं कर पाये। गवर्नमेंट आफ इंडिया की भी मजबूरी है, उनको पूरे हिन्दुस्तान को देना पड़ता है, लेकिन हम उनके लिये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना काम तेजी से कर सकें। दूसरे, लैटरल रोड में यह भी है कि उसके बनाने का ढंग कुछ दूसरा है। पहले हमको मिट्टी को रोलरों से दबाना पड़ता है और उसकी कई तहों को दबाना पड़ता है। उसके बाद उस पर मिट्टी और पत्थर आदि पड़ता है। यह एक नया प्रयोग है और इसमें कुछ देर जरूर लगती है, लेकिन काम चल रहा है।

एक निवेदन श्रम शक्ति योजना के बारे में है। यह स्कीम तीन साल पहले हमारे सामने आयी और इसमें ६८० मील सड़कें हमको बनानी थीं। और १७५ मील सड़कों का पुनर्निर्माण हमको करना था। ५ करोड़ का इसमें खर्च था। शुरू शुरू में जब यह योजना आई तो इसमें

कई दिक्कतें थीं। एक तो टीम लीडर हमको लोकल लेना पड़ता था, दूसरे यह काम हम ठेकेदारों से नहीं करवा सकते थे, इसके अलावा जिस क्षेत्र की सड़क थी उसी क्षेत्र के मजदूर हमको चाहिये थे। इसके अलावा भूमि अर्जन की भी कठिनाई आती है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

पटेल आयोग में जिन सड़कों की सिफारिश थी उसमें से आप ने किसी पर काम नहीं किया वहां, हमारे यहां भूमि अर्जन की दिक्कत नहीं है।

श्री जगनप्रसाद रावत—

१९६४-६५ में ७४ लाख रुपया हमने इस पर खर्च किया और ७४ या ७५ मील सड़कें हमने पूरी कीं। और इस समय हम ५० लाख रुपया आरम्भिक स्कीम में खर्च कर पायेंगे और ६० मील हम सड़कें कर लेंगे। इसके अलावा हम चाहते तो थे ६० लाख रुपया आरम्भ की स्कीम के लिये, लेकिन मिला ५० लाख ही और इस साल केवल २५ लाख मिलेगा जबकि हम ७५ लाख मांग रहे हैं—गवर्नमेंट आफ इंडिया से।

अब एक निवेदन सरेंडर्स के सिलसिले में कर दूं। सन् ६४-६५ में २७८.५५ लाख हमने सरेंडर किया। सन ६५-६६ में हमको जाब्ते से तो १८७ लाख रुपया सरेंडर करना है, लेकिन १४० लाख रुपया इसमें से हम चालू काम में खर्च कर रहे हैं। वह सरेंडर हमको ४७ लाख का रह जाता है और उसके कारण हैं। एक तो यह कि जो बहुत सी आवश्यक इमारतें बनने से रोक दी गयीं उसमें ७० लाख रुपया हमारा खर्च होता। दूसरे जो जमीन नहीं मिली तो ५२ लाख रुपया सरेंडर करना पड़ा। कुछ सीमेंट, रोड मैटल और रोलर्स की वजह से ३४ लाख रुपया सरेंडर करना पड़ा और ३१ लाख इस वजह से सरेंडर हुआ कि एस्टीमेट्स से कम में काम हो गया। तो यह उसका ब्योरा है।

१९६४-६५ में जो कुल वर्कलोड काम का था वह १६.७९ करोड़ था। इस साल हमारा २५.५४ करोड़ होगा। तो इस तरह से जो १९६४-६५ में हमने कार्य किया था उससे सन् ६५-६६ में ९ करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हुआ है।

अब मैं १९६६-६७ के बजट पर आता हूं। १९६६-६७ के बजट में काम और रख रखाव के सिलसिले में हमें २३.८१ करोड़ रुपया खर्च करना है। इसी तरह से भवनों में जो प्लन्ड बिल्डिंग्स हैं उसमें ६१८.२५ लाख। इसमें जो योजनागत भवन हैं उन पर ३४९.६९ लाख और जो योजना के बाहर हैं उन पर २६८.५६ लाख। सड़कों पर ११८४.८३ लाख—इसमें योजनागत सड़कों पर ६०६.७३ लाख और योजना के बाहर वाली सड़कों पर ५७७.९० लाख। ऐसे ही मरम्मत के सिलसिले में ५७१.२० लाख खर्च होगा। इसमें भवनों पर १८.४७ लाख और पुलों पर ५४५.९७ लाख खर्च होगा। और मुतफर्रिक खर्चा है ६.७६ लाख। भवनों में अधिक भवन वह हैं जो इस वर्ष बन रहे हैं या अधूरे हैं। उन्हीं पर रुपया खर्च होना है। इसमें एक नया आइटम है १०.५६ लाख रुपया मेडिकल कालिज झांसी के कंस्ट्रक्शन के लिये और दूसरा मेडिकल कालेज गोरखपुर में बनेगा, उसके लिये है। इन दोनों बिल्डिंग्स की कास्ट ४ करोड़ के करीब होगी।

सड़कों के संबंध में १९६६-६७ के बजट में योजनागत सड़कों और पुलों के लिये जो हमारी सीलिंग है वह ६ करोड़ है और यह अधिकतर जो काम चल रहे हैं उनको पूरा करने में खर्च होगा। इस वक्त १३२० मील नयी सड़कें और ९१० मील पुरानी सड़कों के सुधार और ५६ नये पुल, इसी पर यह रुपया खर्च होगा। इसमें ८० लाख रुपया वह होगा जो नये कामों के सिलसिले में खर्च होगा। उन नये कामों में होंगे जो कि आर्टिरियल रोड्स हैं, स्टेट

[श्री जगनप्रसाद रा त]

हाईवेज के जो मिसिंग गैप्स है और लिंक्स है, उन पर यह खर्च होगा। मुझे खेद है कि धन के अभाव के कारण बहुत से ऐसे काम जो हम पिछले वर्ष करना चाहते थे, जिनका हमने सर्वे आदि भी करा रखा था, उन्हें पूरा नहीं कर पाये। फिर भी २१० मील नयी सड़कें हम बना पायेंगे ४६० मील सड़कों का हम रि-कंस्ट्रक्शन कर पायेंगे, उसमें सुधार होगा। १६ नये पुलों को भी हम बना पायेंगे। जो नये पुल हमने इस साल शुरू किये थे वे थे—एक तो भिन्ड–इटावा रोड पर चम्बल और यमुना नदी पर, दूसरे इलाहाबाद में गंगा पर। इन पर काम शुरू कर दिया गया है और जल्दी ही यह काम पूरा हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिये माननीय मंत्री जी ने कौन-कौन से ठोस कदम उठाये, जो इमारतें गलत बनती हैं उनके लिये क्या कदम उठाये, सीमेंट और तारकोल की गड़बड़ी की जो शिकायतें मंत्री जी के पास पहुंचीं उस पर उन्होंने क्या कदम उठाये ? इसकी ओर भी कुछ प्रकाश डालेंगे, मंत्री जी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं वह भी सब बताऊंगा।

जो सड़कें है उन पर ट्राफिक का वजन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस बार यह प्रयत्न किया गया है कि २०८.१६ लाख की जो योजना हमारी है नयी सड़कों की, उसमें हम २०.६० लाख रुपया खर्च करेंगे उन सड़कों को मजबूत करने में। सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के सिलसिले में एक बात मैं अर्ज कर दूं कि हमको साढ़े तीन हजार रुपया फी मील के हिसाब से मेन्टीनेन्स ग्रान्ट मिलती है। चूंकि पहले सड़कों पर कम वजन चलता था, इसलिये हमको तीसरे वर्ष उनकी मरम्मत करानी पड़ती थी। लेकिन अब जिस रफ्तार से ट्राफिक चलता है उसको देखते हुये हर वर्ष उनकी मरम्मत करानी आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ लेबर और मैटीरियल की कीमत भी बढ़ती जा रही है। परिस्थितियां कुछ ऐसी इस बीच आयीं कि हम ज्यादा पैसा खर्च इन पर नहीं कर पाये। वास्तव में यह वर्ष ६६–६७ जो है यह चौथी योजना का प्रथम वर्ष होना चाहिये था, किन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा अभी हमारे सामने नहीं है। गलतफहमी इसके कारण यह हो गयी है कि इस आशा में कि हम ६६–६७ में चौथी योजना को शुरू कर देंगे हमने कुछ प्रोफार्मा माननीय सदस्यों के पास भेजे थे और यह निवेदन किया था कि वे अपने अपने सुझाव मेरे पास भेजें। और सबको यह आशा थी कि ६६-६७ में उन सुझावों पर विचार करके कोई कार्य हो सकेगा परन्तु हमें यह नहीं मालूम था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कम खर्च करने को मिलेगा। मैं उन सुझावों पर कुछ निर्णय नहीं कर पाया और न ही माननीय सदस्यों को बता पाया कि इसके लिये उनको जिस निराशा से तकलीफ है, उससे मुझे भी तकलीफ हुई है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि ६६--६७ के लिये हमको ईयर टु ईयर प्लान के लिये रुपया मिला है। उसमें हमारी ९ करोड़ की मांग थी परन्तु हमें सैन्टर से केवल ६ करोड़ रुपया ६६–६७ के लिये मिला है। इस लिये हमें इस कार्य को करने में कठिनाई है; यह आप भली भांति समझ सकते हैं। जैसा मैंने निवेदन किया कि एडवान्स ऐक्शन के लिये हमारा टार्गेट था कि हम ९२५ मील का सर्वे करा लें लेकिन हम ५६३ मील का ही सर्वे करा पाये।

श्री बांकेलाल—

मैं जानना चाहता हूं कि जिन सड़कों का सर्वे हो चुका है उन सड़कों को बनाने में क्या देरी है।

श्री जगनप्रसाद रावत—

अध्यक्ष महोदय, अगर सारी रामायण पढ़ने के बाद माननीय सदस्य राम और रावण में फर्क नहीं कर सकते तो इसका मेरे पास उत्तर नहीं है।

इसी तरह से स्थायल सर्वे भी किया गया है। ३५ लाख रुपया इसलिये रखा गया था कि हम इससे यंत्र और पुल बनाने का सामान खरीदें। उसमें हमने २५ लाख रुपया खर्च किया है। इसमें हमने रोलर्स वगैरह मुहैया किये हैं। एक आम शिकायत थी कान्ट्रेक्टर्स से काम कराने की। हमने विभाग से काम करवाने की भी कोशिश की है। इसमें हमें सफलता मिली है और कुछ किफायत भी हुई है। कहीं-कहीं तो ऐसा हुआ है कि टेन्डर्स जो होते हैं वे ऊंचे होते हैं। कई पुल ऐसे हैं जिनके दो दो तीन-तीन दफे टेन्डर्स मांगने पर भी टेन्डर्स नहीं मिले। जैसे बेलन के पुल पर ही नहीं मिले। हमने विभाग से काम कराना शुरू किया है। जो हमारी एस्टीमेटेड कास्ट होगी जो हम कांट्रेक्टर्स के लिये निर्धारित करते थे, हमें आशा है कि हम उससे कम में ही काम पूरा कर सकेंगे। कुछ पुल हमने डिपार्टमेंट्स की तरफ से बनाये हैं। आगरा जिले में उटां गांव और खारी का पुल, रामपुर जिले में पिलाखर का पुल, भंसीटा का पुल हरदोई जिले में, धौरा और सोमेश्वर का पुल नैनीताल जिले में। राप्ती पर भी जो सुपरस्ट्रकचर था वह हमारे विभाग द्वारा ही किफायत से पूरा किया गया है। एक जनवरी, १९६६ से हमने एक ऐसा यूनिट कायम किया है जो विभाग के द्वारा ही अपने काम को कराया करेगा।

शिकायत के सिलसिले में मैं एक निवेदन कर दूं कि आज कल जो पुलों की कास्ट होती है ७.५ मीटर के आर० आई० सी० क्लास "ए" लोडिंग पुल के लिये, उसकी दूसरे सूबों में जो लागत होती है वह चार हजार रुपये पर रनिंग फुट से होती है। हमने जो विभाग द्वारा बनाये हैं उसमें केवल तीन हजार रुपये ही लागत पड़ी है। १९६४-६५ में डिवीजन ३५ लाख पर एक हुआ करता था; अब हमने उसको ३८ लाख पर एक कर दिया है। ५ डिवीजन हमने कम भी किये हैं। केन्द्रीय सरकार का बहुत दिनों से यह सुझाव था कि रोड प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की जाय। ऐसे बोर्ड प्रत्येक सूबे में बनाये जायेंगे। हम भी इसकी स्थापना पर विचार कर रहे हैं। दूसरे सूबों और केन्द्र से विचार करके कि वह कैसा बोर्ड चाहते हैं, हम उसकी स्थापना करेंगे। यह हमें बहुत सी बातों के बारे में सलाह देगा कि कौन से नये तरीके अपनाये जायं। इसमें रिसर्च भी होगी और आर्थिक दृष्टि से जिन तरीकों से हमें लाभ होगा उनको यह बोर्ड हमें बतायेगा।

अब तक म्युनिसिपल बोर्ड जिनकी आबादी २० हजार से ज्यादा होती थी उन्हीं की सड़कों के लिये केन्द्रीय सरकार हमें सहायता देती थी। शेष के लिये हमें खर्चा वहन करना पड़ता था। अब केन्द्रीय सरकार और म्युनिसिपल बोर्ड्स में जो सड़कें हैं उनके लिये भी सहायता देगी। इसके लिये हमें ५.६५ लाख रुपयों का लाभ होगा।

रिसर्च और एक्सपेरीमेंट के सिलसिले में भी हमने कोशिश की है। इसके साथ ही साथ तीन बड़ी-बड़ी फैक्टरियों के लिये, जिनकी रिसर्च दूसरे स्थानों पर होती थी, यानी नैनी की दो फैक्ट्री और कानपुर की फर्टिलाइजर फैक्ट्री के बारे में भी जांच पड़ताल करके इस विभाग ने अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट को उन लोगों ने संतोषजनक माना है।

एक बात वर्कचार्ज के बारे में भी कह देना चाहता हूं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, इसकी दशा से हमें संतोष नहीं है। पिछली मर्तबा हमने ५-५ रुपया करके दो बार में १० रुपया उनको तरक्की दी थी। उसके बाद हम कोई और तरक्की उनको नहीं दे सके हैं। पहले उनका कोई रजिस्टर नहीं जाता था लेकिन अब रजिस्टर और सर्विस बुक रखे जाने की आज्ञा दे दी गयी है ताकि हर बार उनके साथ बिलकुल नये सरीखा व्यवहार न किया जाय। इनमें से कुछ को हम रेग्युलर भी बनाना चाहते हैं। आशा है एक अच्छी खासी तादाद को हम रेग्युलर कर देंगे। इस वक्त तक उनको त्योहारों की बहुत कम छुट्टियां मिलती थीं, कजुअललीव बिलकुल नहीं मिलती थी लेकिन अब उनको हम कैजुअल लीव देना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त

[श्री जगन प्रसाद रावत]

त्योहारो की भी छुट्टी ली जायंगी। वर्क चार्ज की लेबर पी० डब्ल्यू० डी० के अतिरिक्त इर्रीगेशन, पावर और रोडवेज आदि अन्य विभागों में भी है। इन विभाग्रों से आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और जितना संभव हो सकेगा, उनको रियायत देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

कर्मचारियों को रेग्युलर करने का आधार क्या होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

लेंग्थ आफ सर्विस तथा नेचर आफ वर्क आदि ही कर्मचारियों को रेग्युलर करने के आधार होंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

आपकी सड़कों पर जो लेबर और मेट काम करते हैं उनको आप कितनी तनख्वाह देते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उनका वेतन वैसे तो करीब-करीब एक सा है लेकिन जिन क्षेत्रों में जिस तरह से मिलता है उसी के हिसाब से दिया जाता है। निगरानी और देख रेख के संबंध में जितनी कड़ाई हम कर सकते हैं वह की गई है। सन् ६५-६६ में १४ गजटेड अफसरों को सेंश्योर किया गया और १७ के खिलाफ इन्क्वायरी पेंडिंग है और उसका नतीजा मिलने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

यह कब से पेंडिंग है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह इसी साल की बात है। इसी तरह से नान-गजटेड आफिशियल्स में ८ को डिसमिस किया गया और १९ की तरक्की रोकी गई है और १ को रिवर्ट किया गया है और ५ केसेज में जहां गवर्नमेंट की हानि की गई थी उनसे वसूली की गई है। ८३ केसेज में अभी इन्क्वायरी चल रही है।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

डिपार्टमेंटल ऐंटी-करप्शन कमेटी आपके यहां है, वह क्या करती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

हमारे यहां एक विभागीय ऐंटी करप्शन कमेटी है जिसके चेयरमैन डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं और उसमें एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और डायरेक्टर पी० डब्लू० डी० हैं। यह कमेटी जो मामले आते हैं उनकी जांच करती है और जहां शक होता है वहां यह जांच करते हैं, मैटीरियल टेस्ट करते हैं अपने टैस्ट हाउस में और बाहर से भी टेस्ट कराते हैं अगर जरूरत होती है। यदि खराबी पाई जाती है तो ठेकेदार और स्टाफ के लोगों को सजा दी जाती है। यह कार्यवाही जो मैंने अभी बतायी वह इस कमेटी के ही नतीजे पर हुई है। अब जो कमियां और खामियां माननीय सदस्य यहां बतायेंगे और जो सुझाव देंगे उन पर ध्यान दिया जायगा और जो कमियां होंगी उनको दूर करने की कोशिश की जायगी और सुझावों को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

बलिया जिले में उजियार घाट और ताड़ी घाट के पुल की योजना के संबंध में क्या योजना है और क्या प्रयास है और कब तक बनने की संभावना है ? और दोहरी घाट और बरि हाट घाट के बारे में भी बता दें।

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह ताड़ी घाट और उजियार घाट के पुल पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हैं, उनकी स्टडी टीम ने जांच की है। जब वह आदेश देंगे और रुपया देंगे हम उन्हें पूरा करा देंगे। हमारे ऊपर अब वह नहीं है, जो आज्ञा वह देंगे हम करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

दोहरी घाट के संबंध में नहीं बताया गया...

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नोत्तर में मैं दोहरी घाट के संबंध में कई बार बता चुका हूं, उसके टेंडर्स मांग गए थ लेकिन जब तक आदेश नहीं मिलता और रुपया नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

जो नई रोड सिकन्दरा से निकली है वह विभाग की है या नहीं है, क्या बात है ?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

मंत्री जी ने जो रूरल मैन-पावर की बात कही है तो उसमें नए ब्लाक्स लिए जा रहे ह या नहीं और लिए जा रहे हैं तो किस आधार पर ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि—अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय मंत्री जी ने लगभग एक घंटे में जो इतने लंबे चौड़े आंकड़े बता दिए हैं मैं समझता हूं कि जो साथी सदन में बैठे हुए हैं और जो व्यक्ति गैलरी में बैठे हुए हैं, वे इन आंकड़ों में ही उलझ कर रह गए होंगे। मुझे इस बात का भी खेद है कि वित्त मंत्री जी के जो काम करने की किताब है वह भी अभी आयी है। ११-१/२ बजे जब मैं नोटिस आफिस में गया तो वह किताब उस समय तक नोटिस आफिस में नहीं आयी थी जिसमें ये सारे नक्शे वगैरह बने हुए हैं। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि माननीय मंत्री जी ने सारी बातें बतला कर कुछ अपने अफसरों के खिलाफ ऐक्शन लेने की बात भी कही। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले साल जब हमारे दोस्त, माननीय लखपत राम शर्मा जी, ने कट मोशन मूव किया था तो उस समय उन्होंने कुछ उदाहरण पेश किए थे, जिसमें सी० आई० डी० इन्क्वायरी की रिपोर्ट तक का जिक्र उन्होंने अपनी तकरीर में किया था। मुझे मालूम हुआ है कि जिन लोगों को सस्पेंड करने की बात कही गयी है उनमें वह एक भी अफसर नहीं हैं जिनके बारे में माननीय लखपत राम शर्मा ने अपनी तकरीर में जिक्र किया था। इससे जाहिर होता है कि हम लोग साल व साल जो कट मोशन के जरिए या अपोजिशन के या उधर बैठने वाले साथी जो कुछ भी सुझाव माननीय मंत्री जी को देते हैं उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। और अगर दिया जाता तो पिछले साल की तकरीर में जिन लोगों के नाम लिए गए थे, जरूर उन पर कोई न कोई कार्यवाई होती और माननीय मंत्री जरूर उसे बताते। इस वक्त चारों अनुदानों को मिलाकर कुल रकम ३६ करोड़, ३२ लाख, ४० हजार और ५ सौ रुपये हो गयी है जिसके बारे में आज गौर किया जा रहा है। जबसे एमरजेंसी का वक्त हुआ और चीन ने हमारे देश पर हमला किया उस वक्त से उत्तर प्रदेश में इस विभाग की और भी जिम्मेदारी बढ़ गयी है। अपनी बात कहने के पहले मैं यह चाहता हूं कि आज इस सदन में जो इस संबंध में बहस हो वह दो चीजों को सामने रखते हुए हो कि जो सिविल जरूरियात हैं, रोजाना की जरूरियात हैं, वे पूरी हो रही हैं और दूसरी इस विभाग के जरिए से जो एमरजेंसी के सिलसिले में हमारी सड़कों का, जैसे कि चीन तिब्बत में तैयारियां कर रहा है, वैसे हम अपने देश और प्रदेश की रक्षा करने में हाथ बटा रहे हैं या नहीं।

मैं इस सिलसिले में पहले माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के चन्द अल्फाज जो कि उन्होंने कांस्टीटुएन्टी एसेंबली में २७ नवम्बर, १९४७ को पढ़े थे, पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं:—

"First must come first and the first is the security and stability of India."

आज जब हम इस चीज को सामने देखते हैं, जबकि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की बातें करते हैं तो हमें उसे जोड़ना पड़ता है चीन की उन तैयारियों से जो उसने पिछले ५-७ सालों से तिब्बत को हड़पने के बाद कीं। उसने सन् १९५५ में चेन्दू हलासा से ताकला कोट तक सड़क बना ली है जिससे हमारे प्रदेश को रास्ता है। वहां तक उसने सड़क तैयार कर दी १९५५ में और दो आदमी जो हिमालयन ऐक्सपीडीशन के थे सिडने विगनैल और जान हैरप, उनको पकड़ लिया और पकड़ कर ताकला कोट में बन्द रखा। तो वहां से उनको सीक्रेट मालूम हुआ कि—

"In two years time a strategic highway would link Lhasa and Taklakot, and extension of the Chungking-Chambo-Lhasa road would enable the Chinese to establish a huge army within 250 miles of Delhi."

यह सीक्रेट उन्हें वहां से मिला कि दो साल के अन्दर चाइनीज ताकलाकोट तक सड़क बना लेंगे और दिल्ली से २५० मील दूर पर वे अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे। इमरजेंसी की बात जब हम अपने सामने रखते हैं तो दिमाग में यह सवाल उठता है कि हमने अब तक इस संबंध में क्या किया। ३६ करोड़ की मांग इस विभाग के लिए जो सदन के सामने रखी गई है इसको बढ़ती हुई एमरजेंसी और रोजाना की जरूरयात को सामने रख कर मंत्री जी जितना मांग लें उतना ही थोड़ा है, लेकिन शर्त यह है कि मांगा हुआ रुपया उचित तरीके से खर्च हो और जो रुपया खर्च किया गया है वह भारत की सेक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए कहां तक सही हुआ और हमारी डे टु डे जरूरियात के लिए कहां तक खर्च हुआ है ? अगर वह उचित तरीके से खर्च हुआ तब तो संतोष होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो चीन ने दो साल के अन्दर सारी तैयारी कर ली और दूसरी तरफ जो सड़क अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ को चलती है और जिस मार्ग पर १९५७ में सरजू ब्रिज का उदघाटन माननीय गिरधारी लाल ने किया था उस ब्रिज के बाद पिथौरागढ़ तक मैं आज भी कह सकता हूं कि अगर फर्स्ट क्लास गाड़ी या कार न हो और कहीं अगर ब्रेक में गड़बड़ हो जाय तो गाड़ी में बैठे हुए आदमी बच नहीं सकते हैं। १० साल से वहां गाड़ियां चल रही हैं। १९५७ में ब्रिज खुला, लेकिन उस सड़क पर जो सरजू से लेकर पिथौरागढ़ तक चलती है मुझे सफर करने का मौका मिला तो पाया कि अभी भी सिंगिल वे ट्रैफिक है। कांक्रीट और डामर का कहीं पता नहीं, और जो सेफ्टी साइन्स लगे रहते हैं उनका कहीं नाम ही नहीं है। पता लगा कि वहां एक स्पेशल डिवीजन बना दिया गया है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के अधीन। लेकिन हालत यह है कि बार्डर डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी पिथौरागढ़ आप अल्मोड़ा होकर तो आसानी से जा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं टकनपुर होकर पिथौरागढ़ जाने का मौका मिले तो दो दिन बाद आप पहुंच सकते हैं। यह उस सड़क की हालत है।

तो जब हम देखते हैं कि चीन तिब्बत के अन्दर पूरी तयारी कर रहा है, हमारे यहां पी० डब्ल्यू० डी० बार्डर एरिया के अन्दर जो एक मुख्य सड़क है, जो बार्डर डिस्ट्रिक्ट है जहां से नैपाल का बार्डर बिल्कुल सामने दिखलाई देता है, ८, १० मील से ज्यादा का फासला नहीं वहां हमारा सप्लाई का सामान कैसे पहुंचे ? मुझे अफसोस होता है कि ३६ करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा और स्टेबिलिटी के लिए भी खर्च नहीं कर सकते फिर यह रुपया किस काम आने वाला है ? जैसा प्रधान मंत्री जी ने कांस्टीट्यूएंटी असेंबली में कहा था, फर्स्ट थिंग फर्स्ट उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

१९५८ में बम्बई में चीफ इंजीनियर्स की कानफरेंस हुई जिसमें आपने लक्ष्य बनाया कि १९८१ तक २५,००० मील रोड यू० पी० में बनायेंगे। यह भी आपने कहा कि हम किसी भी गांव को ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो ४ मील से ज्यादा पक्की सड़क से रह जाय या ढाई मील से ज्यादा कच्ची सड़क से रह जाय। अगर इस चीज को हम मानें तो आप का लक्ष्य यह है कि ४ मील से ज्यादा पक्की सड़क न हो और ढाई मील से ज्यादा कच्ची सड़क न हो। आपको यू० पी० के अन्दर जरूरत पड़ी है ४८,७०० मील के करीब सड़क और अगर आप दूसरे सूबों से मुकाबला करते हैं तो केवल बिहार को छोड़कर फी स्क्वायर माइल के हिसाब से बम्बई, मद्रास, पंजाब से पीछे हैं। सन् ४६-४७ में हमारा यह बजट ४५ लाख था, लेकिन आज बढ़ कर ३६ करोड़ हो गया है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए जितने रुपये की जरूरत हो मंत्री जी को उसे मिलना चाहिए, लेकिन हमको यह यकीन होना चाहिए कि रुपया हमारा सही रूप से खर्च हो रहा है अथवा नहीं। अगर मंत्री जी इस बात का विश्वास नहीं दिला सकते तो फिर इससे काम नहीं चलेगा कि घंटे भर खड़ा हो कर आंकड़े दे दिए। दुनिया में बहानेबाजी से काम चलने वाला नहीं है।

[श्री रियासत हुसैन]

हर साल आडिट रिपोर्ट आती है और आपके विभाग की रिपोर्ट भी छपती है, उसको देखा जाय तो काफी वक्त लगता है, लेकिन उनमें से दो चार बातों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आपकी चीफ टेक्निकल एग्जामिनर आर्गनाइजेशन है । १९५९ में सेट अप हुई थी । उसने उन केसेज को एग्जामिन किया जिनमें २० हजार से अधिक रुपया खर्च हुआ और जिनमें डिफेक्ट्स निकले । १९५९-६० में १३२९ केसेज एग्जामिन हुए जिनमें से ९८४ में डिफेक्ट था । ६२-६३ में २४९ केसेज में १७६ तथा ६३-६४ में ३०६ केसेज में २०९ केसेज में डिफेक्ट था । टोटल मिलाकर १,८८१ मामलों की जांच की और उनमें १,३६९ केसेज में डिफेक्ट्स पाए गए, यानी ७५ परसेंट केसेज में डिफेक्ट्स पाए गए । डिफेक्ट्स इस तरह के पाए गए कि ज्यादा रुपया अदा कर दिया गया, एक्सपेंडीचर कम किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया, ठेकेदारों से खासतौर से हमदर्दी रखी गयी, तरफदारी की गयी । ८० केसेज में ठेकेदारों के काम की वजह से सरकार को ५० हजार का नुकसान हुआ । आडिट आबजेक्शन्स को देखा जाय तो अकेले ६४ में १३.७६ लाख के बाउचर नहीं मिले । इस तरह सब मिला कर १३२.५७ लाख रुपये के आबजेक्शन्स आउटस्टैंडिंग के पाए गए । माननीय मंत्री जी ने नहीं बतलाया कि उस आर्गनाइजेशन ने जो डिफेक्ट्स निकाले उनको रिमूव करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी और क्या नहीं की गयी । हर इंसपेक्शन रिपोर्ट के लिए आपके आर्डर्स हैं कि ६ महीने के अन्दर आब्जेक्शन्स का जवाब मिल जाना चाहिए । लेकिन १९५४-५५ से २३४ ऐसी इंसपेक्शन रिपोर्ट्स हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है ।

अब जरा कांस्ट्रक्शन के बारे में देखिए । आपके कांस्ट्रक्शन वर्क्स को इंजीनियर पास करते हैं और काम ठेकेदारों से कराते हैं । अभी आपने यह कहा कि इस सिस्टम को एबोलिश करना चाहते हैं । क्या वजह है कि जो आप कांस्ट्रक्शन कराते हैं उनमें भी बहुत से डिफेक्टस रहते हैं ? दो इमारतें आपने अक्तूबर, १९५९ में बनाई जो बनने के बाद से ही टपकने लगीं । इन इमारतों के लिए ६७,२२७ रुपये का बजट था और छत की मरम्मत के लिए मुआइना किया गया । ठेकेदार का कुछ नहीं हुआ और उनकी मरम्मत के लिए २१,५०० रुपये फिर से मंजूर किए गए और अक्तूबर, १९६२ में यह काम पूरा किया गया । इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि ठेकेदार का क्या किया गया ।

इस डिपार्टमेंट के वर्कमेन के बारे में मंत्री जी ने बात कही । अगर इस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा काबिले गौर बात है तो इनकी ही है । एक तरफ तो इसमें बड़े बड़े इंजीनियर लोग हैं जो १,८००–२,००० रुपये के ग्रेड में वेतन पाते हैं और दूसरी तरफ इस डिपार्टमेंट के वर्कमैन हैं जो सड़क पर ड्यूटी देते हैं और मिट्टी डालते हैं । इनको ६० रुपये माहवार वेतन मिलता है और महंगाई वगैरह के नाम पर कुछ नहीं मिलता है । लेकिन यह भी ६० रुपये का ही काम करके देते हैं । सिर पर टोकरी रख कर इस तरह से घुमाकर मिट्टी डालते हैं कि जो मिट्टी २ स्क्वायर फ़िट में पड़नी चाहिए उसको ये १० स्क्वायर फिट में डालते हैं । यह बेचारे अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए रोते चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया जाता है । अब मुकाबला कीजिए । लखनऊ में पी० डब्लू० डी० के आफिस की काफी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें चीफ इंजीनियर रहते हैं । एक इंजीनियर-इन-चीफ की नई जगह बनाई गई है । यह जगह चीफ इंजीनियर के अलावा बनाई गई है । एक साहब रिटायर हो रहे थे तो उनको रखने के लिए यह जगह बनाई गई है । इनकी तनख्वाह २,००० रुपये माहवार है । कोई गारंटी नहीं है कि कितने साल तक इनको रखा जायेगा । मालूम ऐसा होता है कि २,००० रुपये माहवार की इनको पेंशन दी गई है । मैंने इसके बारे में सारा बजट टटोल डाला, लेकिन कहीं भी इंजीनियर-इन-चीफ के नाम से कोई जगह नहीं मिली । चीफ इंजीनियर की जगह है । पता नहीं चलता कि यह जगह कहां से और कैसे आ गई ? जब तक हम खुश रहेंगे तब तक आप इस जगह पर बने रहेंगे ।

दूसरी तरफ आप देखिए कि चीफ इंजीनियर के अलावा दो एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं। इनका भी वेतन १,८००-,२००० का है। दो डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं जिनका वेतन १,५००-१,८०० है। दस सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स पी० ए० की जगह कार्य कर रहे हैं जो टैक्निकल हैंड्स हैं। आपके लखनऊ में डिपार्टमेंट्स में इतना स्टाफ रहता है। दस टेक्नीकल हैंड्स पी० ए० की जगह पर कार्य कर रहे हैं। दो डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं और सब से ऊपर इंजीनियर-इन-चीफ हैं। इन सबका खर्चा कितना पड़ता है? पांच लाख सत्तर हजार पांच सौ, सिर्फ तनख्वाह। डी० ए०, टी० ए० छोड़ दीजिए।

दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में दस डिवीजन हैं, एक पहाड़ का डिवीजन और बनाया गया। हर डिवीजन में एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रखना चाहिए। उसकी जगह पर २३ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स हैं। एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के ऊपर डिवीजन में डेढ़ लाख रुपया सालाना खर्च होता है। कितना सरप्लस हो गया? वर्कमैन चिल्लाता है। उसकी तनख्वाह अलग-अलग जिलों में अलग-अलग है। बलिया में ५० रुपये, उसी को पीलीभीत में ४५ रुपये, उत्तर काशी में पहाड़ का पायेगा ५० रुपये और अगर नेपाल का है तो ११५ पायेगा, चमोली में पहाड़ का है तो ७५ रुपये और गोरखपुर का है तो १०० रुपये पायेगा, गोरखपुर में ४५ रुपये देंगे। एक तो उनके लिए परमानेंट व्यवस्था नहीं और वह भी इनती अनश्योर है कि बलिया में कुछ और मुरादाबाद में कुछ। सारे कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स के आंकड़े इन २० हजार वर्कमैन पर आयद कर दिए, लेकिन इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर्स से इसका कोई वास्ता नहीं।

इसके साथ-साथ इस विभाग द्वारा प्रेसीडेंट आफ इंडिया तक के आदेशों का पालन नहीं हुआ। २९ दिसम्बर, १९६२ को लिखा—

"The President is pleased to decide the fixation of any pay of industrial work charge employees on their appointment under the relevant fundamental rules as amended from time to time."

प्रेसीडेंट आफ इंडिया ने फंडामेंटल रूल्स के मुताबिक उनकी पे फिक्सेशन के लिए लिखा परन्तु आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। १९५७ में पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट की जो रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बैठायी उसने भी कहा था—

"With their permanent appointment the members of the establishment will become entitled to all the privileges of the Government service like leave, salary, pension etc. This is likely to improve their efficiency in the long run. This will still leave a large number of employees who are employed on the actual contrsuction work."

उसका आज तक आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया ६०७४१-डब्लू ई पी। XXIII —पी० डब्लू० डी०—७७—डब्लू० सी०—५७, दिनांक ८ मार्च, १९६० को चीफ इंजीनियर को कि गैंगमेट, बेलदार को डी० ए० मिलना चाहिए, लेकिन लेकिन वह भी आज तक नहीं दिया जा सका। चौधरी गिरधारीलाल जब मिनिस्टर थे तो १७ मई, १९६१ को माननीय प्रतापसिंह के सवाल के जवाब में इस बात का एश्योरेंस दिया था कि इन लोगों के सर्विस रूल्स को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जायगा ताकि वर्क चार्ज को कोई नुकसान न हो। आज तक वह अश्योरेंस पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा जो छुट्टी के बारे में कहा, क्या छुट्टियां देते हैं? जो आपके यहां काम करते हैं उनमें अलग-अलग क्लास कर दिया। जो छुट्टियां देते हैं, उसमें भी एक समानता नहीं है, कुछ को कुछ छुट्टियां मिलेंगी, कुछ को कुछ छुट्टियां मिलेंगी। कुछ लोगों को तो १४ दिनों की लीव दे देते हैं। आपके जो वर्क एजेन्ट

[श्री रियासत हुसैन]

हैं, उनको १४ दिन की कैजुवल लीव मिलती है इसके अतिरिक्त अन्य कोई छुट्टी उन्हें नहीं मिलती। जो मेट्स हैं उनको १० दिन की फेस्टिवल लीव मिलती हैं, और कोई छुट्टी नहीं मिलती है।

इन चीजों को देखते हुए मैं कुछ सुझाव आपके सामने देना चाहता हूं। एक तो मेहरबानी करके जो बिल्डिंग्स के कान्सट्रक्शन वर्क्स होते हैं, उनको शाप देखें कि इंजीनियर क्या क्या करता है और कोई क्या करता है। दारुलशफा की इमारत सन् ६० में बनी है, लेकिन मैं आपको उसको देखने के लिए दावत देता हूं, उसकी छतें और दीवालें जगह-जगह से फट गयी हैं, कमरों के अन्दर से जाने क्या चीज झड़ रही है। जो सीमेंट है वह झड़ रहा है और उसे जितना आप इकट्ठा करना चाहें कर सकते हैं। इसका तन्दुरुस्ती पर भी बुरा असर पड़ता है। इसका एक कारण चोरी है। चोरी कौन करता है? आपका इंजीनियर चोरी करता है और २–४ साल की सर्विस के बाद लाखों रुपयों का बैंक बैलेन्स भी करता है, इमारत भी बनवाता है। तो इसको रोकने के लिए जब तक आप कोड आफ कान्डक्ट को सख्ती के साथ अन्डर डी० आई० आर० नहीं रखेंगे कि जब कोई सर्विस में आया था तो उसकी इन्कम और जायदाद क्या थी और २–४ साल की सर्विस के बाद उसकी हैसियत क्या होगयी, और उसको कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तबतक यह चोरी रुक नहीं सकती है। यह कोड आफ कान्डक्ट का रूल ओवरसियर और इंजीनियर सभी पर लागू होना चाहिए। इस जांच में जिन्हें दोषी पाया जाय, उनके ऊपर सख्ती से डी० आई० आर० चलना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसे लोगों के ऊपर आप डी० आई० आर० नहीं चलायेंगे तो जिसके अन्दर सैकड़ों एम० एल० एज० रहते हैं, जिनके परिवार भी रहते हैं, पता चलेगा गिर गया है और उसके अन्दर सैकड़ों आदमी औरत दब गए हैं।

एक सदस्य—

ऐसी अशुभ बात मत कहिए।

श्री रियासत हुसैन—

खुदा न करे, लेकिन यदि ऐसा होगा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार पर होगी। उस चोरी में उन्हें मुनाफा मिलना चाहिए, फिर चाहे जितने लोगों की जान ही क्यों न चली जाय।

रोजाना ठेलों और ट्रकों के सैकड़ों ऐक्सीडेन्ट होते हैं, क्या आपने कभी इसका कारण सोचा है कि इसकी क्या वजह है? १०–१२ फुट चौड़ी मुश्किल से सड़कें होंगी और कहीं-कहीं पर आपने उन पर मिट्टी किनारे डाल दी है। ट्रकें आदि जब ओवर पास होती हैं, तो इतनी धूल उड़ती है कि उन्हें फिर थोड़ी देर तक कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, सड़क पर चलने वाली सवारियों और आदमियों को दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेन्ट हुआ करते हैं।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मांग माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने प्रस्तुत की है, उसका समर्थन और जो कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, यह जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, इसके ऊपर देश की बाह्य और आन्तरिक सुरक्षा निर्भर है। यदि हमारे देश के अन्दर और सीमाओं की सड़कें ठीक से निर्मित नहीं होंगी तो हम अपने देश की सुरक्षा कैसे कर सकेंगे? ऐसी अवस्था में जो धनराशि बजट में निर्धारित की गयी है, वह बहुत कम है। मैं, विभाग के द्वारा सीमाओं पर जो सड़कें बनाई गई हैं तथा संकटकाल के आने पर जिस तेजी के साथ कार्य किया गया है, उसके लिए विभाग को धन्यवाद दूंगा। कुम्भ के मेले की व्यवस्था जिस प्रकार से सड़कों और पुलों के द्वारा की गयी, एक छोटी-सी भी घटना नहीं घटने पायी, इसके लिए विभाग धन्यवाद का पात्र है। लेकिन जहां विभाग ने तेजी से ये अच्छे कार्य किए हैं वहां पूरे प्रदेश के अन्दर विभाग का कार्य या मैं

कहूं कि सरकार ही का सौतेला व्यवहार अवध के कुछ जिलों जैसे उन्नाव, हरदोई, रायबरेली आदि के साथ जो हो रहा है वह उचित नहीं है। मैं उदाहरण के लिए उन्नाव जिले को आपके सामने रखना चाहता हूं।

उन्नाव जिले में स्टार-ग्रिड सूत्र के अनुसार पक्की सड़कों की आवश्यक लम्बाई ३१९ मील रखी गयी है और बीस वर्षीय बाम्बे योजना के अनुसार पक्की सड़कों की आवश्यक लम्बाई ४९४ मील रखी गयी है। सन् १९४७ में पक्की सड़कों की लम्बाई इस जिले में कुल १८० मील थी जिसम से कुछ ६६ मील सार्वजनिक निर्माण विभाग की थी। विभाग द्वारा पिछले वर्ष जो आंकड़े दिए गए —इस वर्ष के आंकड़े तो हम अभी पढ़ ही नहीं सके हैं क्योंकि आज ही वह पुस्तिका वितरित हुई है, उसके अनुसार केवल ३८ मील सड़क विभाग दिसम्बर, १९६३ तक उन्नाव जिले में बनी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्वतन्त्रता के पश्चात् के वर्षों में उन्नाव जिले में सार्वजनिक विभाग द्वारा बनाई गयी सड़कों का औसत एक वर्ष में करीब २ मील पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो बड़े भाग्यवान हैं।

श्री श्रीराम तिवारी—

उन्नाव जिले की सड़कों के जो आंकड़े सरकार द्वारा दिए गए हैं उनको जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि ९९ मील सड़क विभाग द्वारा और बन जाय तो उन्नाव जिले मे स्टार-ग्रिड सूत्र के अनुसार निर्धारित लम्बाई पहुंच सकती है। इसके साथ ही जब हम प्रदेश के अन्य जिलों को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि प्रदेश के २२ जिले स्टार-ग्रिड सूत्र को पार कर चुके हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात्, दूसरे जिलों में बनायी गयी सड़कों के आंकड़े जो हमें मिले हैं उनके अनुसार सिर्फ बरेली, फतेहपुर और बाराबंकी को छोड़ कर अन्य जिलों में उन्नाव जिले से अधिक लम्बाई में सड़क बनी हैं। जहां तक बरेली का सवाल है, अगर वहां १० मील सड़क और बन जाय तो स्टार-ग्रिड सूत्र के अनुसार वह लम्बाई पूरी हो जायगी। बाराबंकी जिला स्टार-ग्रिड सूत्र को पार कर चुका है। फतेहपुर जिले में ६६ मील सड़क और बननी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्नाव जिला सड़कों के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि चौथे प्लान के अन्त तक ९९ मील सड़कें उन्नाव जिले में बन जानी चाहिये ताकि वह उस समय तक स्टार-ग्रिड सूत्र की लम्बाई तक पहुंच जाय।

जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनके सम्बन्ध में मैं अपने जिले के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। विभाग द्वारा ली गयी दो सड़कों के बीच में कानपुर से लखनऊ मोहान होकर जो सड़क जाती है उस पर सई नदी में मोहान का एक पुल है। यह कई वर्षों से टूटा पड़ा है। दोनों ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क है। माननीय मन्त्री जी ने बड़ी कृपा करके पुल विभाग में नहीं था उसको विभाग में ले लिया है। विगत वर्ष जब मन्त्री जी मोहान गए थे तब उसके निर्माण के लिए घोषणा की थी लेकिन बड़ा दुख है कि अभी तक वह पुल जैसे का तैसा पड़ा हुआ है और उस पुल के न बनने से मोटर और गाड़ियां जो उधर से गुजरती हैं उनकी स्थिति बड़ी खतरनाक रहती है।

जिले की सड़कों के विषय में मैंने कुछ पत्र भी लिखे लेकिन खेद है कि उन पत्रों को प्राप्त करने तक की सूचना प्राप्त नहीं हुई। मेरा जिला क्रिमिनल जिला कहा जाता है। उसके लिए अन्य कारणों में मैं इस समय नहीं जाऊंगा लेकिन उसमें सड़कों की कमी भी एक मुख्य कारण है। उदाहरण के लिए असोहा पुलिस स्टेशन है, यह सड़क पर नहीं है। वहां से लेकर कालूखेड़ा मार्ग के लिए जिला परिषद् की ओर से सुझाव दिया गया है। इसी प्रकार अजगैन पुलिस स्टेशन रोड पर है लेकिन वह जिले के अन्तराल से नहीं मिलता। अजगैन-भोलीमुंशीगंज

[श्री श्रीराम तिवारी]

मार्ग के लिए जिला परिषद् से सुझाव आया है। मैंने भी अपने पत्र में इसकी उपयोगिता के बारे में लिखा है। मेरी प्रार्थना है कि इन सड़कों का तुरन्त जैसे ही पैसा मिले निर्माण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जिले की अन्य कई सड़कें हैं। यदि उनका निर्माण कर दिया जाता तो उन्नाव, रायबरेली और हरदोई, तीनों जिलों का कल्याण हो सकता है। रायबरेली कुर्री सिधौली के भौरेश्वर महादेव और उन्नाव जिले के सुमरेहा के बीच में पुल सई नदी पर बने, इसके लिए मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। यदि यह और यहां से होकर सुमरेहा तक कालूखेड़ा की सड़क, तथा अजगैन मुंशीगंज की सड़क जिनका जिक्र मैंने किया है बना दिए जायं तो रायबरेली, उन्नाव और हरदोई जिले मिल जायेंगे और इन सड़कों की युद्धकाल में उपयोगिता बढ़ेगी और शान्ति के समय व्यापारादि में इनसे सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से उन्नाव जिले में पुलों की समस्या है। गंगा पर जाजमऊ में पुल बनने की योजना है। लेकिन वह खटाई में पड़ी है। उन्नाव नगर का बाईपास बहुत दिनों से है कि बनेगा लेकिन पता नहीं कि क्यों नहीं बन रहा है। जहां लखनऊ में गोमती नदी पर बांध बनाया गया है बाढ़ से रक्षा के लिए, सई नदी पर रायबरेली के पुल को चौड़ा करने की मांग बहुत दिनों से है, सैकड़ों बीघा कृषि भूमि बाढ़-ग्रस्त होती है, लेकिन इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब अधिक समय न ले कर मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उन्नाव, रायबरेली और हरदोई जिलों की मांगों पर जिनके विषय में मैंने विस्तार से नहीं बताया है भली प्रकार ध्यान दें क्योंकि ये जिले किसी भी प्रकार से पूर्वी जिलों से आर्थिक रूप में कम पिछड़े हुए नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय रियासत हुसैन जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मुझे बड़ा खेद है कि यह रिपोर्ट हमें आज मिली है और बिना इसको देखे हुए कुछ कहना कठिन है। यह कम से कम तीन रोज पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली आज ही है। और आज हम कुछ कहना भी चाहें तो उसको बचाने के लिए यह दी जाती है ताकि हम कोई टिप्पणी उस पर न कर सकें।

दूसरी बात यह है कि माननीय मन्त्री जी ने गत वर्ष कहा था कि जो सुझाव माननीय सदस्य देंगे उन पर विचार किया जायगा। माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में नहीं बताया कि जो उनको सुझाव गत वर्ष दिए गए थे उन पर क्या कार्य किया गया है। केवल वर्क चार्ज के विषय में बताया कि उनको कुछ सुविधा दी गई है और उनकी तनख्वाह को बढ़ाया गया है और कुछ एलाउन्स में भी वृद्धि हुई है। परन्तु जो कठिनाई है उसके लिए नहीं बताया कि जो सुझाव दिए गए थे उन पर कोई विचार किया गया है या नहीं। यह खेद की बात है। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि जो सुझाव दिए जाते हैं उन पर विचार करके उनके निराकरण का उपाय करना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अनुदान निरन्तर बढ़ता जाता है। आज यह अनुदान ३६ करोड़ का है। यह बड़े दुख का विषय है कि इनको आये १८ वर्ष बीत चुके हैं और प्रति वर्ष माननीय मन्त्री जी इस अनुदान को यहां सदन में रख देते हैं और सदन से पास हो जाता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का दायित्व अफसरों पर रहता है जो अपना दायित्व निभाने में उदासीन रहते हैं। जैसा अभी रियासत हुसैन साहब ने कहा, अफसर भी भ्रष्ट होते हैं। हमारा गरीब देश है। यातायात का साधन ही ऐसा है जो जन-जीवन के स्तर को उठाने में निर्भर करता है। परन्तु होता क्या है? यह जो ३६ करोड़ का अनुदान है इसमें जितना वास्तविक काम पर खर्च होना चाहिए वह नहीं होता है। इसके लिए उत्तरदायित्व अफसरों के ऊपर होता है जो ठेका देते हैं। एक काम की पूर्ति जितने रुपए में इनके द्वारा की जाती है वह लगभग दूना अमाउन्ट होता है। वास्तविक खर्चा इससे आधा हो सकता है उसी काम के लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि दुगुना रुपया उस काम के

लिये लिया जाता है। एक सड़क अगर २ मील लम्बी बनाई जाती है तो उतने रुपए में ४ मील लम्बी सड़क बन सकती है। इस पर हमारे अफसर ध्यान नहीं देते हैं। वह केवल अपनी सुख-सुविधा का ही ध्यान रखते हैं। मन्त्री महोदय इस बजट में देखेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने अपनी सुविधा के लिए जो बंगले बनवाए हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब देश की दशा खराब हो रही है, खाने के लिए अन्न पैदा नहीं हो रहा है उस समय उन्होंने ३५ हजार में एक एक-एक बंगला बनाने पर खर्च किया है जो उचित नहीं कहा जा सकता। इन्होंने जिस बंगले के बनाने में ३५ हजार रुपया खर्च किया है वह बंगला २५ हजार में अगर बना दिया जाता तो इनका काम उससे भी चल सकता था। यह काम कम रुपए खर्च करके भी किया जा सकता था और छोटे घर में रह कर भी काम चलाया जा सकता था। देश की दशा जब खराब है तो देश की दशा को देखकर के व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना जरूरी था। वह तो आप करते नहीं और अपने कार्यालय की सुविधा के लिए आप खर्च करते हैं। इस पर मन्त्री जी को विचार करना चाहिए। इस अनुदान में हम अपने लिए खर्च करते हैं और उस सुविधा के लिए भवन और कार्यालय बनाते हैं।

कुछ खर्चा तो बिल्कुल ऐसा है जो बचाया जा सकता था। जैसे राज्यपाल महोदय का भवन निर्माण कर देना और नैनीताल में उनकी झील की बाउन्डरी खींचना है। इस प्रकार का खर्चा बचाया जा सकता था। उस खर्चे को बचाकर हम अपनी दृष्टि कृषि की ओर केन्द्रित कर सकते हैं। उससे पैदावार बढ़ सकती है। यदि पैदावार बढ़ेगी तो उससे अन्न की समस्या हल होगी। आज हर देश से आप भीख मांग रहे हैं। यह लज्जा आने की बात है। सारे देशों के गिर्जाघरों में प्रार्थना की जाती है कि इनको भीख दो, अन्न दो। सड़क पर, रास्ते में लड़के प्रोसेशन निकाल रहे हैं और डच तथा हंगरी जैसे देश हमको चावल तथा गेहूं की सहायता दे रहे हैं। जो अधिक पैसा खर्च हो रहा है उसे बचा कर हम सिंचाई तथा कृषि की ओर लगाने का प्रयत्न करें तो हमारी दशा अच्छी हो सकती है। यह दायित्व उन्हीं अधिकारियों पर है जिन को आप हर साल ३६ करोड़ रुपया सौंप देते हैं और अन्त में वे कह देते हैं कि हम उसे खर्च नहीं कर सके।

इसके अलावा आप देखें कि बजट किस तरह से बनाया जाता है। माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि किस तरह से ठेकेदारों को कमीशन दिया जाता है और कमीशन न मिलने पर क्या व्यवहार उनके साथ किया जाता है। जो कमीशन दे देते हैं उनकी इमारतों का क्या हाल होता है, यह भी आपको मालूम है। वे एक साल में ही चूने लगती हैं, और कुछ गिरने लगती है। मिनिस्टर साहब, चीफ और असिस्टेंट इंजीनियर, सभी इस बात को जानते हैं। इस बजट के खण्ड ४ के पेज ४१५ पर आपने चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, दो को ही रखा है और उसके बाद यहां एक प्रधान अभियन्ता आ गए। इस अनुदान में आप उस की रकम कैसे ले सकते हैं? आपने उसका नाम हेडिंग में दिया ही नहीं। इस के अलावा आप ने उस की तनख्वाह २,००० रखी है और साल भर में अनुमानित व्यय २७,००० रुपया रख दिया जब कि वह २४,००० होना चाहिए। यह तीन हजार रुपया आप ने जबरदस्ती बढ़ा दिया। यह मकान तो बनाना नहीं है कि कुछ कमी बेशी हो सकती है, २४ की जगह २७ हजार खर्च हो सकता है। इसी तरह से सारे बजट को अगर आप आइटमवाइज देखेंगे तो हर जगह आप यही त्रुटि पायेंगे। वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के लिए दूसरा आइटम है। वह इसमें नहीं आता। अगर वह इस में आता तो आप को उस का जिक्र इसमें करना चाहिए था।

दूसरे मुख्य अभियन्ता का वेतन १,८०० से २,००० रखा है। अगर हम मान लें कि सभी दो हजार रुपया पाते हैं तो भी २४,००० रुपया होता है, लेकिन आपने इसमें २५,८००

[हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री]

रुपया लिख रखा है। इसी प्रकार उप अभियन्ता १२ हैं जिनके लिए ४४,००० रुपया लिखा हुआ है जब कि होना चाहिए ४०,००० रुपया। तो इसमें इस तरह से आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर रखे गए हैं। यह बढ़ी हुई रकम कहां जायगी? जब यह पहले से ही बढ़ा कर लिखा गया है तो इसे यूटिलाइज करने का सवाल ही नहीं उठता। यह सारा बजट इसी तरह से गलत बना हुआ है। एक जगह लिख दिया गया पेज ५०९ पर नयी सड़कों का निर्माण, यह पता नहीं कि वे सड़कें हैं कहां। इसी तरह दो जगह सड़कों के सर्वेक्षण की बात पेज ५२० पर दी गयी है.....

(श्री बलवानसिंह द्वारा सदन का त्याग करने पर)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय बलवान सिंह जी, यह तरीका नहीं है आने जाने का।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

अब मैं अपने क्षेत्र बीकापुर की तरफ आता हूं। इसमें बीकापुर तहसील में १९४७ के बाद आज तक एक इंच भी सड़क नहीं बनी। एक पुल फैजाबाद से रायबरेली सड़क पर है। पहले दो साल तक यह डेंजरस था, फिर बनाया गया। कहा जाता है कि ६०,००० रुपया इस पर खर्च हुआ। फिर उसे बन्द कर दिया गया इसलिए कि वह क्रैक हो गया है और फिर तीन महीने-बरसात पर---इस पर ट्रान्शिपमेंट होता था। १२ बसें वहां चलती हैं, उन की सवारियां इधर से उधर नाव पर आती जाती थीं। इस साल इस रोड पर १४, १५ मील के बीच में एक पुलिया बनायी गयी। ३,००० रुपया उसके लिए दिया गया। इंजीनियरों ने बताया, ठेकेदारों ने उसे बनाया, लेकिग फिर उसे पाट दिया गया। यह है आप के विभाग के कार्य!

इसके अतिरिक्त आप के यहां का एक सर्वे डिवीजन है। वह २६, २६ जिलों में बांट दिया गया है। इस में भी जो खर्च हो रहा है वह व्यर्थ खर्च हो रहा है। क्या डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर इतने अयोग्य होते हैं कि वे इस सर्वेक्षण के काम को नहीं कर सकते? सर्वेक्षण का काम अलग होने से दोनों का कोआर्डिनेशन नहीं हो पाता। इसलिए मेरा सुझाव है कि सर्वेक्षण का कार्य भी जिला इंजीनियर को सौंप देना चाहिए।

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान पर बोलने के लिए समय प्रदान किया। मेरा यह पहला अवसर है कि जब मैं इस पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे और मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी को मैंने पारसाल भी उन के कमरे में निवेदन किया था और उनको अपने जिले की मुख्य सड़कों की लिस्ट दी थी और मन्त्री जी के आश्वासन पर भी आज तक उनकी कोई जांच नहीं हुई है, न कोई सव्रक ही बनायी गयी। यह पश्चिमी सोरांव का क्षेत्र वह है जहां से पंडित जी चुन कर आते थे और अब विजयलक्ष्मी पंडित जी वहां से चुनी गयी हैं। मैं भी वहीं से आया हूं। वहां सड़कों की हालत बड़ी खराब है। कल्याणपुर से एक सड़क सोरांव की आती है जो कि लालबहादुर शास्त्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटित की गयी थी। उस पर पुल टूटा हुआ पड़ा है। वह सड़क बहुत जरूरी है। इसे मन्त्री जो नीट कर लें और जांच कराकर बनाने की कृपा करें। दूसरे कछाई क्षेत्र में बहुत सी सड़कें खराब हैं। वहां आने जाने की बड़ी परेशानी है। जगदीशपुर से बंधराय के थाने को जाने वाली सड़क बहुत खराब है। ऐसे ही बहुत सी सड़कें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े समय में जितना सम्भव हो यह विभाग वहां कार्य कर दे। उन्नाव रोड भी अधूरी पड़ी हुई है। इस विभाग को पैसा बहुत मिलता है, लोग दिलचस्पी भी लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे यहां कोई काम नहीं होता।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के ओवरसियर, मेट आदि की तनख्वाहें बहुत कम हैं। जब आप अपने दूसरे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं तो आपको इन छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाना भी बहुत जरूरी है।

ओवरसियर लोगों में जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है उसका मुख्य कारण यह है कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं और काम ज्यादा पड़ता है। सभी उच्च श्रेणी के अधिकारी अपना काम ओवरसियर से कराते हैं। ऐसी दशा में ओवरसियर, कामदार, बेलदार और बारहमासी जिसको कहा जाता है उसकी तनख्वाह बढ़ाना बहुत जरूरी है। मुझे विशेष न कह कर फिर यह दोहराना है कि हमारी जो मुख्य-मुख्य सड़कें हैं और जो लिस्ट दी है उसको बनवाने की कृपा करेंगे। और मुझे ज्यादा कहना नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

जो बजट माननीय मन्त्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो किताब इस विभाग से हमें मिली है उसमें शुरू में पहली सतर में दिया हुआ है कि "जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने के लिए, तथा खाद्य पदार्थों, वस्त्रों, निवास गृहों एवं देश की सुरक्षा सामग्री में आत्म निर्भरता प्राप्ति की मूल समस्या को सुलझाने में सड़कों का प्रमुख स्थान है।" माननीय मन्त्री जी मानते हैं कि जनता के रहन-सहन को ऊंचा करने के लिए सड़कों की भी जरूरत है, लेकिन जब मैं इस विभाग के कर्मचारियों को देखता हूं, लेबर और मेट को तो जैसा कि मन्त्री जी ने शुरू में बतलाया रीजन-वाइज उनकी तनख्वाहें निर्भर करती हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि चाहे पूरब का लेबर हो या पश्चिम का हो, खोना तो हर एक खाता है और यू० पी० के अन्दर गल्ले का भाव एक-सा है। जो कुदाल फरसा चलाने वाला है उसकी खूराक अधिक होती है, लेकिन उसमें डिफरेंशिएट करना यह किसी तरीके पर न्याय प्रद नहीं है। इसलिए मन्त्री जी रीजन का जो बहाना ढूंढ़ते हैं उसको साफ करना चाहिए। और लेबर और मेट को पूरब में ३५-३७ और ४७ रुपए मिलते हैं और पश्चिमी जिलों में १०-१० रुपए का फर्क है, वहां ४७ और ५७ रुपए मिलते हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन समाप्त होना चाहिए।

जहां तक सड़कों के निर्माण का सवाल है, मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने बड़ा न्यायप्रद बटवारा उत्तर प्रदेश के बजट का किया है। लेकिन आगरे में ही सिर्फ ८१,८३,००० रुपया पुलों में गया है और यू० पी० में ६ पुल बने हैं जिसमें से ३ पुल आगरे में बने हैं और ११ लाख रुपया उन पर लगा है और मन्त्री जी ने लिया है। एक पुल और बना है धौलपुर सड़क पर वह २,९० हजार रुपए का है। इस तरीके पर बजट का जो बटवारा हुआ है तो केवल मिनिस्टर जहां का हो उसके घर में सड़कें बन जायं और दूसरे जिले में न बने यह उचित नहीं है। लेकिन और जिले जो पूर्वी क्षेत्र में हैं या जिनका नामो-निशान बजट में नहीं है। श्रीमन्, उनके धन का इस तरह से दुरुपयोग हो, यह उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि यह उदासीनता का जो कारण है वह पक्षपात है। मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चार पूर्वी जिलों में केवल १५ मील नयी सड़कों का सुधार होगा, यही आपका विकास है? ताड़ीघाट और बक्सर का झगड़ा लगाया गया पूर्वी जिलों का और नतीजा यह हुआ कि कानपुर में वह रुपया पुल बनाने में लगाया गया। इस तरह की जो कूटनीति चल रही है, एक दूसरे जिले के लोगों को लड़ाकर इस तरह से गलत-गलत जो काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि किसी तरीके पर उचित नहीं है। माननीय मन्त्री जी को खुद सोचना चाहिए कि सन् १९६१-६२ में हमने देखा कि चीन की लड़ाई में पी० डब्ल्यू० डी० क्या कर रहा था। आपको याद होगा, यहां पर किसी माननीय सदस्य ने कहा था, कई मील लम्बी सड़क बननी थी, केन्द्रीय सरकार से उसके लिये रुपया मिला था, यहां के इंजीनियरों ने उससे वह सड़क तो

[श्री कमलासिंह यादव]

बना दी जिस पर होकर चीनी फौजें यहां आ सकती थीं मगर वह सड़क नहीं बनायी जिसके द्वारा हमारी फौजें मौके पर पहुंच सकती थीं। जब हमारी फौज को वहां पहुंचना था, मिलीटरी आफिसर इस सड़क के बारे में पूछने के लिये हमारे इंजीनियरों के पास गये, उस समय वे ताश खेल रहे थे। यह उसी तरह हो रहा था कि जब रोम जल रहा था तो नीरों बांसुरी बजा रहा था।

श्रीमन्, गाजीपुर जिले के लिये पटेल आयोग ने ९२ मील सड़क बनाने की सिफारिश की थी और १२ मील लम्बी सड़क बनाने की योजना भी तृतीय योजना में स्वीकार की गयी थी। मगर इस ११३ मील सड़क में से केवल ८ मील लम्बी सड़क ही बन पायी है। वहां के लिये ४ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ४ असिस्टेन्ट इंजीनियर तथा १८ ओवरसियर रखे गये हैं, और जो काम हुआ है वह मैंने अभी बताया कि ८ मील सड़क बनी है। सारा रुपया अधिकारियों के वेतन आदि पर खर्च हुआ है। डिप्टी कलेक्टर का जो क्वार्टर वहां बना है वह एक नमूना है, जहां ५० प्रतिशत रुपये का दुरुपयोग हुआ है। यहां पर सदन में माननीय मंत्री जी ने बताया कि देवकली के अस्पताल का सारा रुपया ठेकेदार को दे दिया गया, मगर मेरी सूचना यह है कि अभी काफी रुपया बाकी है, यह गलत सूचना दी गयी, जो उचित नहीं है।

श्रीमन्, हमारे यहां दो सड़कें बनाने का जिक्र है। रूरल मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत उनको बनाने की बात कई साल से चल रही है। मगर अभी तक एक मील सड़क भी नहीं बन पायी है, केवल सारा अर्थ वर्क ही हो रहा है। विभाग मस्ती ले रहा है, और कोई काम हो नहीं रहा है।

यह कहा गया कि लैन्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही चल रही है। श्रीमन्, जो कलेक्टर कम्पेनसेशन आफिसर हैं वही लैन्ड एक्वीजीशन का काम भी करता है। गोरखपुर में लैन्ड क्वीजीशन आफिसर बैठाकर यह सारा काम कराया जा रहा है, यह कितनी हास्यास्पद बात है। श्रीमन्, अगर इसी प्रकार की उदासीनता हमारे पूर्वी जिलों के लिये बरती गयी तो इससे बड़ा नुकसान होगा, पटेल आयोग ने भी लिखा है कि इन चारों पूर्वी जिलों को अगर यही गति रही तो यह जिले बरबाद हो जायेंगे, और फिर हम अपनी आवाज केन्द्रीय सरकार तक भी नहीं पहुंचा पायेंगे।

श्रीमन्, ४० लाख रुपया गाजीपुर के हास्पिटल को माडर्न टाइप का बनाने के लिये स्वीकृत हुआ था। वह रुपया लैप्स हो गया। पालीटैक्नीक के लिये ५ लाख रुपया मंजूर हुआ था, वह सारा रुपया लैप्स हो गया। इसमें कोई शुबहा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है अगर यही रवैया आपने आगे भी अपनाया तो मैं समझता हूं कि हमारा भला होने वाला नहीं है लेकिन रुपया जो इतनी मुश्किल से मिल रहा है अगर उसका भी दुरुपयोग हुआ तो मैं समझता हूं कि जिस बजट का बहाना लेकर हम चलते हैं उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। गाजीपुर--बहरियाबाद रोड जंगीपुर से शुरू की गई है और इस के नाम से जितना रुपया सरकार दे रही है, उसमें कुल साढे सात लाख रुपये की स्कीम है। कभी उसमें पांच या छः कभी ५० हजार रुपया करके दिया जाता है। इसी तरह से सैन्क्शन रुपया हो रहा है। कैसे सड़क बनेगी इससे? मैंने माननीय मंत्री जी के पास एक एप्लीकेशन अपनी रिकमैन्डेशन के साथ भिजवाई है कि धिरनी--बहरियाबाद गाजीपुर--दुल्लहापुर रोड से वहां मिलती है उससे तीसरी सड़क न मिला कर अच्छे-अच्छे बागों को वहां नष्ट किया जा रहा है। अगर दो बड़ी सड़कें जहां मिल रही हों तो तीसरी सड़क को भी वहीं मिलाना चाहिये ताकि मुसाफिरों को दिक्कत न हो। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको कम से कम गाजीपुर या पूर्वी जो चार जिले लिये गये हैं उनकी तरफ

इस ओर अच्छा कदम उठाना चाहिये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले में माननीय मंत्री जी आये। माननीय मंत्री जी के जरिये हमको यह मालूम हुआ कि पचास लाख रुपया पुल के लिये मिला है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पचास लाख रुपया मिला है तो जो पटेल आयोग के अन्तर्गत पचास लाख रुपया मिला है वह केन्द्रिय सरकार का रुपया है। ये पचास लाख रुपया भी पूर्वी जिलों में जहां पुल वगैरह बनने हैं वहां लगाते, परन्तु आपका यह कहना कि अलग से रुपया मिलेगा तब बनेगा, उचित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज जो अनुदान पेश हैं मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, पी० डब्लू० डी० के महकमें में जितनी ग्रान्टस के लिये हमारे मंत्री जी ने मुतालिबा किया है मैं समझता हूं यह बहुत कम हैं क्योंकि सब से ज्यादा प्राथमिकता जिस काम को मिलनी चाहिये वह सड़कों का काम है। हमने वायदे किये थे कि हम गांव गांव को जोड़ देंगे। हमने वायदे किये थे कि ग्रामीण जनता, जिनकी बैलगाड़ियां पड़ी रहती हैं और बरसात के महीने में उनकी जो दुर्दशा होती है, हम उनको निकालकर स्वर्ग में ले आयेंगे; हमने जितने बड़े बड़े वायदे किये थे, श्रीमन्, कहा जा सकेगा कि बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने आईं लेकिन दिक्कतें एक के बाद एक आती चली जाती हैं। उसके बाद भी हमारे वास्ते जो असल काम है जिस पर हमारा रुपया खर्च होना चाहिये वह नहीं हुआ है। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ उस वक्त ९३८७ मील पुख्ता सड़क हमारे प्रदेश में थी लेकिन आज हम आहिस्ते आहिस्ते १६,६०० मील पुख्ता सड़क मुकम्मिल करने जा रहे हैं। यह कहा जायगा कि यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि यह कुछ नहीं है। क्योंकि १८, २० साल में आप इसे दोगुना भी नहीं कर सके। हमारी जरूरी सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रूरल मैनपावर स्कीम निकाली गई और ५०० लाख रुपया उसमें रखा गया। कहा गया कि ६८० मील पक्की सड़क, और १७५ मील पुरानी सड़कों की मरम्मत की जायगी और ४ पुल बनाये जावेंगे। हुआ क्या? हमने उसमें से ७४.२५ लाख रुपया चौथे साल में खर्च किया और ७४ मील सड़क बनाई। यह किताब जो मिली है इसमें वह कहते हैं कि ६० मील और बनायेंगे और ५० लाख रुपया खर्च करेंगे। ५०० लाख रुपये में से चौथाई आप खर्च कर पाये या पावेंगे। हम उन बदकिस्मत लोगों में से हैं जो मैन पावर स्कीम को सुनकर समझे कि एक सड़क तो हमारी बन ही जायगी। चुनांचे जिला परिषद से प्रस्ताव पास करके भिजवाये गये और मंजूरी आ गई कि डुमरियागंज चमरियाघाट सड़क बनेगी। ३, ३, मीटिन्ग्स में कहा गया कि सरकार को बधाई दो, सड़क बन जायगी। उसके बाद यहां आकर अधिकारियों से मालूम हुआ कि सरकार ने सभी योजनायें रोक दीं और मैन-पावर स्कीम खत्म कर दी है और सड़क नहीं बनेगी। २ पुल हमारे यहां के लिये ६२ में मंजूर हुए जो निहायत जरूरी थे, एक डुमरियागंज में राप्ती पर और दूसरा गुप्तचर का घाट बूढी राप्ती पर। इन दोनों पुलों की इतनी चर्चा हुई और इतनी बधाई दी हम लोगों ने सरकार को कि अगर उसे जमा किया जाय तो एक पोथी तैयार हो जायगी। रामकुमार शास्त्री जी ने रोज एक सर्कुलर भेजा। सर्वे के लिये इतने इंजीनियर गये कि लाखों रुपया उनके आने जाने में सर्फ हो गया होगा। लेकिन दोनों पुलों पर एक ईटा भी नहीं रखा गया। सुना है, रामकुमार शास्त्री जी की बदौलत फिर कुछ जिन्दगी पैदा हुई है और हम चाहते हैं कि उसे कुछ तेज कर दिया जाय ताकि सालभर के अन्दर उन पुलों की शक्ल नजर आने लगे।

[काजी जलील अब्बासी]

वह क्षेत्र पहले भानु प्रताप सिंह जी के क्षेत्र में था, अब हमारे में आ गया है। एक सड़क सिर्फ नौ मील की है। एक सड़क बस्ती में बांसी और दूसरी बस्ती से डुमरियागंज जाती है। बीच में १८वें मील पर दोनों से एक सड़क मिली है, रुदौली से भानपुर। वह नौ मील की है। उसके लिये सारे क्षेत्र का मतालबा था कि वह बननी चाहिये। पी० डब्लू० डी० के पहले मंत्री गिरधारी लाल जी वहां गये, जनता ने उन्हें फूलों से लाद दिया और आशा लगी कि अब सड़क बन जायगी। लेकिन नहीं बनी। हम अपने मौजूदा मंत्री जी की खिदमत में हाजिर हुए। उनकी बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने भी वहां जाकर देखा और उनके मुंह से शब्द निकले कि यह बहुत आवश्यक सड़क है। आशा थी कि मिनिस्टर ने कह दिया है, सड़क बनेगी। लेकिन नहीं बनी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का जोरदार अलफाज में ध्यान आकर्षित करूंगा कि अगर वह सड़क नहीं बनी तो जनता में यह बात जावेगी कि मैंने तो कोई कोताही नहीं की, मगर सरकार ने की। हर साल बराबर मैं चिल्लाता रहा कि नौ मील की सड़क पर केवल कंकड़ डाल कर बना देना है, कच्ची सड़क मौजूद है लेकिन मैं बड़ा बदकिस्मत हूं कि वह नहीं बन पाई। जैसा बारिश से नुकसान भी होता है और फायदा भी। लोगों के घर भी बह जाते हैं तो कहीं खेती बन भी जाती है। वैसे ही एक लेटरल रोड आकर हमारे यहां आसमान से गिरी। उसने बहुत से काश्तकारों को तबाह कर दिया, वह उजड़ गये। वह सड़क गोन्डा को बस्ती से जोड़ती है। उस पर एक बाई-पास जो भानपुर के पास बन रहा है। वहां के लोग इन्तहाई परेशान हैं चूंकि तीन तरह के प्रोपोजल आये हुए हैं। तीसरा प्रोपोजल जनता को स्वीकार है चूंकि छोटे छोटे किसान उसमें बच जाते हैं। मगर पहले प्रोपोजल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है चूंकि बड़े बड़े किसान और बड़े बड़े लोग उसमें बचते हैं। मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह खास तौर पर नोट कर लें कि तीसरे प्रोपोजल ही मंजूर किया जावे। इस विभाग के छोटे कर्मचारियों के, इस विभाग के और लेबर की हालत वाकई बहुत खराब है। इस विभाग में दिन ब दिन ठेकेदार मोटा हो रहा है, लेकिन लेबर क्लास को कोई सुविधा नहीं दी जाती। मैं मंत्री जी के विचारों को जानता हूं कि वह प्रगतिशील हैं और मैं आशा करता हूं कि वह जरूर छोटे कर्मचारियों और लेबर क्लास की तरफ भी ध्यान देने की कृपा करेंगे।

इन अलफाज के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, किसी विभाग की ख्याति के लिये कुछ विशेष आवश्यकतायें होती हैं कि वह अपना उत्तरदायित्व भली प्रकार से निर्वहन करता हो, अपने क्षेत्र में सब से ज्यादा सम्पन्न व्यवस्था करता हो, उसकी सीमा की भली प्रकार रक्षा करता हो और जिस कार्य का निर्माण करता हो उसमें अच्छा सामान लगाया जाय। वह विभाग कार्यकुशल कहा जाता है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इन सभी दिशाओं में बहुत पिछड़ा हुआ है और उसमें सभी खामियां हैं। जो कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, उससे भी यही बात प्रतीत होती है। सड़कों के निर्माण के प्रश्न को ले लें। यह पुस्तिका छपी है, इसमें बहुत से आंकड़े दिये गये हैं। इस प्रदेश को पांच भागों में विभाजित किया गया है पहाड़ी, बुन्देलखन्ड, पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रीय। पहाड़ी क्षेत्र को सुरक्षा का बुन्देलखन्ड को कुछ विशेष परिस्थितियों वाला, पूर्वी क्षेत्र को पटेल कमीशन और ग्रामीण जन शक्ति योजना का, पश्चिमी क्षेत्र को एक सम्पन्न क्षेत्र और मंत्रियों की बाहुल्यता का और केन्द्रीय को अगर उपेक्षित कहूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप देखें कि किस जिले में कितनी सड़कें १९४७ में थीं और आज तीन योजनाओं के बाद कितनी हो गयी है। प्रदेश में सब से कम अगर कहीं सड़कें बनी हैं तो फतेहपुर जिले में। हालत कुछ भी हो लेकिन यह तथ्य है। आवश्यकताओं के अनुसार सड़कों का निर्माण किया जाय, इसके लिये दो फारमूले बनाये गये एक स्टार ग्रिड फारमूला और दूसरा बाम्बे प्लान। लेकिन ऐसा लगता है कि अलग अलग

जिलों के लिये अलग अलग तरीके पर बिचार किया गया है। जिन जिलों में सड़कें कम बनीं हैं वे हैं जालौन, कानपुर, मेरठ, अलीगढ, हरदोई, बदायूं, फतेहपुर और सीतापुर। और ज्यादा जिन जिलों में बनायी गयी हैं, वे इस प्रकार हैं—

जिला	सन् ४७ से पहले मीलों में	आजकल मीलों में
इलाहाबाद	३१९	३७७
आजमगढ़	३१२	५२७
बिजनौर	१४७	३५६
देवरिया	१०८	६०६
गोरखपुर	१६७	४१३
खीरी लखीमपुर	१०५	३३०
मुजफ्फरनगर	११८	४२९
सुल्तानपुर	१६०	३५०

जहां तक लक्ष्य का सवाल है, गोरखपुर में १० प्रतिशत और देवरिया में १८ प्रतिशत लक्ष्य से अधिक कार्य हुआ है।

हर जिले के लिये आपने कमेटियां बनायीं। माननीय सदस्यों से भी आपने पूछा लेकिन फतेहपुर के सिलसिले में न तो आपने कमेटी की बात मानी और न जिला परिषद की बात ही मानी और न मेम्बरों की बात ही मानी। मालूम नहीं जाने किस आधार पर वहां पर सड़कें बनायी जा रही हैं। अच्छा हो अगर आप उन सड़कों को ही बना देते जिनको आपने पिछले वर्ष प्राथमिकता दी थी लेकिन उनको भी छोड़ दिया गया है। उनको छोड़ कर आपने विशिष्ट जिलों को जिनमें मंत्रिगण रहते हैं, ले लिया है।

इस समय चौथी योजना बन रही है उसमें एक खास बात आपको ध्यान रखना चाहिये। बड़ी-बड़ी सड़कों के बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको पहले उन छोटे छोटे टुकड़ों को बनाना चाहिये जो तृतीय योजना में बनी हुई सड़कों में ३-४ मील के रह गये हैं ताकि उन सड़कों का उपयोग हो सके। जिला परिषद के सदस्यों के सुझावों का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिये, जिससे जन प्रतिनिधियों का मान बढ़ सके। ऐसा नहीं होता। इसके बारे में मुझे एक मिसाल याद आ रही है। एक जाट नवयुवक फौज में भर्त्ती हुआ। डाक्टरी के लिये अस्पताल भेजा गया। सारे कपड़ों को उतरवा कर उसकी डाक्टरी हुई। फिर वह फौज में चला गया। थोड़े दिनों के बाद जब वह बीबी के पास आया। जब एकान्त में बीबी से उसकी छेड़खानी होने लगी तो उसने कहा यह सारी चीज सरकारी हो गई, जब तक मैं फौज के अफसर से न पूछ लूं किसी चीज का एक दूसरे से लगाव नहीं होगा। यह सरकार का जनतंत्र है और एक तरह से पूरा डिक्टेटरशिप है। मैं चाहता हूं कि सरकार जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनकी भावना को सुने। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंच जाय और मैं चाहता हूं कि इन सब बातों को देखना चाहिये।

एक सब से बड़ी सड़क जो फतेहपुर रायबरेली की सीमा पर है उसके गंगा के पुल की बहुत आवश्यकता है और बांदा फतेहपुर कीसीमा पर भी चिल्ला घाट के पुल की बहुत आवश्यकता है। मुझे बहुत तकलीफ है कि इन दोनों सड़कों के पुलों को छोड़ दिया गया है।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

इसके अलावा जो आपका एक दूसरा तरीका भवन बनाने का निकला है उसमें भी ऐसा लगता है कि कुछ खास शहरों को आप ने चुन लिया है। कुछ पूर्व के और पश्चिम के जिलों को आपने ले लिया है और बीच के जिलों को छोड़ दिया है। इसके अलावा जो सामान इन भवनों के बनाने में प्रयुक्त होता है उसमें जितने प्रतिशत सीमेन्ट होना चाहिये वह नहीं लगाया जाता, मौरंग भी कम लगाया जाता है। कितनी ही बार विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया कि सीमेन्ट की चोर बाजारी होती है, हम चाहते हैं कि किसी तरह से आप सीमेन्ट की चोरबाजारी को रोकें। जो भवन निर्मित हों उनसे टेस्ट के लिये ममूने लेकर देखा जाय कि कैसा मेटीरियल लगा है। जो कर्मचारी और ठेकेदार दोषी पाये जायं उनको अवनत करना चाहिये। यह आम शिकायत है कि ठेकेदारों से इंजीनियर ओवरसियर कमीशन लेते हैं। इसको देखना चाहिये और ऐसे लोगों को सजा देना चाहिये, इस संबंध में बहुत अन्धेरगर्दी है।

इसी तरह से पुलों पर भी बड़ी गड़बड़ होती है जो आपके पुलों के ठेकेदार है वह पैसा लेते है। कानपुर की सीमा में हमीरपुर के पास एक पुल है वहां पर बावजूद मनाही के पुल से ट्रक पास करा दी जाती हैं और दस रुपया एक ट्रक के लिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की अनियमिताओं को रोकने की कोशिश की जाय।

इसके अलावा सड़कों के दोनों तरफ जो एन्क्रोचमेंट होता है और खेतों में या दुकानों में जो जमीन ले ली जाती है उसको रोकना चाहिये या उससे जो जायज आय हो वह लेना चाहिये। सड़कों के किनारे की दुकानों का प्रबन्ध करना चाहिये और उन पटरियों की दुकानों से आय की जाय। गौरी औवरा सड़क पर लोन नदी का पुल बनाना भी बहुत जरूरी है और इसी तरह से रिन्द नदी पर जाफरगंज का पुल बनाना चाहिये। इन छोटे-छोटे पुलों के बनने से ग्रामीण अञ्चल में रहने वाले किसानों का बहुत लाभ होगा और वह अपनी उपज का ठीक मूल्य पा सकेंगे, इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार होगा।

श्री अधिष्ठाता—

श्री जे० पी० मिश्र, आपने २ मिनट का समय मांगा है, आप २ मिनट बोल लें।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

२ मिनट में क्या बोल पाऊंगा, आपने समय दिया है...

श्री अधिष्ठाता—

तो ३ मिनट बोल लीजियेगा।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, अपनी ऐसी बात है कि सिवा आपकी सिफारिश के और कोई दूसरी नहीं है, इसलिये आशा है कि आप हमारा थोड़ा सा समय बढ़ा देंगे और अब मैं आपके माध्यम से अपने बिचार सरकार के सामने प्रस्तुत करता हूं। यह विभाग इतना होशियार है और इसमें इतने तजुर्बेकार सेक्रेटरी व इंजीनियर्स हैं कि जो मिनिस्टर इस महकमे में पहुंचा, तुरन्त उसके जिले के पास पड़ोस की कुल सड़कें, व पुल पुलिया सामने पेश हो गये, उनका निर्माण होने लगा और उसके बाद पूरे प्रदेश का क्या होता है, क्या नहीं होता। माननीय मंत्री जी को ब्राइव किया और फिर वह ५० जिलों को विभागीय अधिकारियों की राय पर छोड़ देते हैं। वही स्थिति आज हरदोई जिले की है। मैं बार बार ३ वर्ष से कह रहा हूं कि वहां पर १५० गांवों का एक क्षेत्र ऐसा है जो डूबा हुआ है, जिसके काश्तकार मंडियों तक नहीं पहुंच पाते हैं और जहां के काश्तकारों से इन्टरमीडियरी ४ सेर और ५ सेर का मक्का खरीद कर डेढ़ और दो सेर का बेचते हैं। अब जिला परिषद ने सर्वसम्मति से पास करके एक प्रस्ताव सरकार के पास संडीला-मेंहदीघाट सड़क बनाने का भेजा है। उसका सर्वे हो चुका है लेकिन १९६६-६७ में आदेश आ गये कि लड़ाई की वजह से बन्द हो गये। सड़कें बन्द हो गयीं, पुल बन्द हो गये

और उसके खिलाफ हरदोई में इंजीनियर्स के आलीशान बंगले बनकर तैयार हो गये हैं। इस सड़क के न बनने से लगभग ५०० गांव के किसानों की फसल का ठीक दाम नहीं मिल पाता, जिसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। रुपया इमारतों में लगा दिया जाता है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे काश्तकार, जिनको स्वतंत्र हुए १७ साल हो चुके हैं, आज भी डूबे हुए क्षेत्रों में पड़े हुए हैं। वहां पर मिट्टी तक डालना जुर्म है और एक भी पुल बनाना जुर्म है। आज जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, जैसे लखनऊ, वाराणसी, आगरा जहां पर सरकार की गद्दियां हैं उनको शामिल किया गया है। मैं तो यह कहता हूं कि डिफेन्स के बाद दूसरा नम्बर कन्ट्री रोड्स देहात की सड़कों का होना चाहिये जिनसे वहां के काश्तकारों को उनकी पैदावार का उचित दाम मिल सके। हमारे माननीय मंत्री जी ने किसी जिले में यह कहा था कि कांग्रेसी अपनी बात कहना भूल गया। कांग्रेसी को निर्भीकतापूर्वक अपनी बात कहनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ३६ १/२ करोड़ रुपये के बजट में से जो खर्चा होगा, उसमें सार्वजनिक निर्माण में कितना खर्चा होगा, कितना तन्ख्वाहों में जायेगा, कितना टी० ए० और डी० ए० में जायेगा और कितना रुपया रिश्वत में, जो ११ परसेन्ट इंजीनियर और ओवरसियर को देना पड़ता है, जायगा ?

एन्टी करपशन भी पी० डब्लू० डी० में उल्टी चलती है। विजिलैन्स कमीशन भी है लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। इसका वृक्ष ऊपर है, जड़ें भी ऊपर हैं पर दाना नीचे निकलता है। २ १/२ वर्ष हुए, रिश्वत व कमीशन खाने के सम्बन्ध में मैंने एक रिपोर्ट हरदोई के जिला इंजीनियर के विरुद्ध की थी लेकिन आजतक तहकीकात पूरी नहीं हो पाई। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक का कमीशन उसमें है। अभी तक भी उसमें कुछ भी नहीं हुआ। सी० आई० डी० के पास इन्क्वायरी के लिये केस गया लेकिन उन्हें अब तक कागजात तक नहीं दिए गये। तो हमारा तो आखिरी साल है १९६६–६७ और इसमें है कि कोई सड़क या पुल नहीं बनेगा। १९६७ में जो चुनकर आयेगा, उनका बनेगा। क्या मालूम अधिष्ठाता महोदय, आप आयेंगे या नहीं आयेंगे, हम नहीं आयेंगे और यह भी नहीं मालूम कि माननीय मंत्री जी भी चुनकर आयेंगे या नहीं। खतरा है। हमारी १९६४ में और १९६५ में जबान बन्द रही लेकिन १९६६ में कोरा जबाब मिल गया। "राम नाम सत्य" हो गया। हमें अफसोस है कि इस पी० डब्लू० डी० में करीब करीब पांच वर्षों में १५० करोड़ रुपया अनुदान में चला गया लेकिन ६–६ मील और ३–३ मील की लिंक्ड रोडस नहीं बन पायीं। चीन आया, पाकिस्तान आया। न तो पिथौरागढ़ में ही सड़कें बन पायीं और न ही गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में ही बन पायीं। बना क्या, यह तो सरकार जानती है, मंत्री महोदय जानते हैं। हम सब ९८ फीसदी कांग्रेस पार्टी और विरोधी दलों के मेम्बर जानते हैं कि हम तीन तीन मील भी सड़क नहीं बना पाये हैं। एक एक और सवा-सवा लाख का रिप्रेजेन्टेशन हम लोग करते हैं लेकिन हमारी बातों को बिल्कुल ठुकरा दिया जाता है, कोई कदर नहीं होती है क्या कहते हैं, क्या बकते हैं, क्या सलाह देते हैं। यह हमारी हालत है। ऐसी सूरत में आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी का किस्सा खतम हो रहा है, इंदिरा गांधी जी, प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेन्सी को खत्म करने की बात कह दी है और इसी पार्लियामेंट के सेशन में इमरजेंसी का अन्त हो जायगा तो उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी सूरत में कंट्री रोड्स का जो हिस्सा है, गांवों की सड़कों का जो हिस्सा है वह हिस्सा हमारा इसी बजट में हमको मिलना चाहिये, पूरा होना चाहिये, वरना उस गरीब साढ़े ८ करोड़ में जो आज ७ करोड़ गरीब जनता है अगर उसके उत्पादन की खपत के लिये हम मंडियां न दे सकें, सरकार सड़क न दे सकी, पानी तो मिलना मुश्किल है, अगर सड़क भी मिल जाय तो काश्तकार आज अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि आप के माध्यम से कि प्रान्तीय सरकार इस तरफ तवज्जह दे, गरीब काश्तकारों को उनकी उपज के लिये मंडियां मिल सकें, इतना ही मुझे कहना है।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान पर जब हम विचार करते हैं तो मैं इस अवसर पर पुनः आपका ध्यान जो बजट प्रस्तुत करने का समय हमारा है वह गलत है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिये कि सबसे अधिक प्रभाव इसी बजट के ऊपर पड़ता है। इस विभाग के बहुत से अनुभवी और पुराने कर्मचारियों और अधिकारियों से मुझे बात करने का अवसर मिला। उनका स्पष्ट मत है कि जिस बजट को हम मार्च में पास करते हैं और अप्रैल में शुरू होता है उसमें १, २ महीना हमारे सचिवालय में और लग जाता है, नतीजा यह होता है कि उसके बाद बरसात का सीजन प्रारम्भ होता है। तीन चार महीने काम नहीं कर पाते हैं और उनका कहना यह है कि मुश्किल से ४, ५ महीने हम को काम करने का अवसर मिलता है और आखिरी २, ३ महीने जो होते हैं उसमें रश अप करते हैं एक्सपेंडीचर को और इस से हमारी क्षमता और कार्य-कुशलता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिये मैं इस अवसर पर पुनः कहना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान का यह मसला है, लेकिन सभी विधान मंडलों और संसद को इस पर विचार करना चाहिये। क्या यह उचित नहीं होगा कि बजट हमारा पहली जुलाई को या जुलाई में पेश हुआ करे ताकि अगर, सितम्बर के बाद फौरन हम इस पर काम करें और ८, ९ महीने काम करने के अवसर मिले ? जहां ३६ करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं उसको इस प्रकार से जल्दी में खर्च करना कि उस का पूरा लाभ गरीब मुल्क के लोग न उठा सकें, मैं समझता हूं कि इसका सबसे अधिक प्रभाव इसी विभाग पर पड़ता है। इसलिये हमको इस पर विचार करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इस विभाग की बहुत सारी शिकायतें हैं और उन पर निरन्तर हम जोर डालते रहते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जब इकोनोमी के मेजर्स हम ले रहे हैं और काफी बचत की योजनायें हम चला रहे हैं तो हमारा ध्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ जाना चाहिये। मेरा निश्चित मत है कि इस विभाग का प्रशासन जो है इस में आवश्यकता से अधिक अधिकारी और कमचारी लगे हुये हैं। मैं इस अवसर पर खास तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आप देखें कि एक मुख्य अभियन्ता हैं, दो उनके सहायक मुख्य अभियन्ता हैं, दो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हैं और एक प्रमुख अभियन्ता हैं। प्रमुख अभियन्ता की पोस्ट इस राज्य में क्रीएट की गई। यह एक प्रणाली सी बन गई है और अगर कोई अफसर रिटायर होता है तो एक नये पद का सृजन करके उसकी रोटी का साधन जुटाना मैं समझता हूं यह निहायत गलत बात है। इस विभाग के अन्दर एक प्रमुख अभियन्ता की पोस्टक्रिएट करके २,००० रु० महीना खर्च करना उचित नहीं है। उसके लिये कोई औचित्य नहीं है कि एक मुख्य अभियन्ता के साथ साथ दो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हैं, दो उप मुख्य अभियन्ता हैं और दूसरे उच्चाधिकारी हैं। बहुत गलत बात है। उस पोस्ट को फौरन खत्म करना चाहिये। किसी जमाने में अधीक्षण अभियन्ता की पोस्ट क्रियेट की गयी और यह खयाल किया गया कि ये अनुभवी इंजीनियर हैं। इस राज्य में २३ अधीक्षण अभियन्ता हैं। किसी जमाने में यह काम असिस्टेंट इन्जीनियर ही किया करते थे लेकिन हमारे उच्चाधिकारी ज्यादा हों इस खयाल से उनकी तादाद बढ़ा दी गई। यह बहुत गलत बात है। २३ अधीक्षण अभियन्ताओं में अधिक से अधिक ८ हमारे राज्य में होने चाहिये। शेष जितने पद हैं उनको अविलम्ब तोड़ना चाहिये अगर इकोनोमी मेजर्स को टाइटन करना है। लेकिन इकोनोमी के मेजर्स को लाज किया गया तो उसकी तलवार सड़क कूटने वाले बेलदार और मेट पर चली। १२ बेलदारों में से घटाकर उनकी संख्या ९ कर दी गयी। इकोनामी की तलवार उन पर चलती है जो कंकड़ कूटने वाला होता है, मेहनत का काम करने वाला होता है। उस पर काम का सवा अथवा डेढ़ गुना भार बढ़ाया जाता है और इकोनोमी की जाती है। कितना विरोधाभास है। इस विभाग के टाप हैवी एड मिनिस्ट्रेशन देख कर हैरत होती है, उसमें छटनी न करके मजदूरों की छटनी करके इकोनामी की तलवार चलाई जाती है। यह खेद की बात है, इसे बन्द करना चाहिये। आज से १५ साल पहले ३० लाख रुपये पर एक डिवीजन काम करता था और आज भी ३५, ४० लाख

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये पर वह डिवीजन काम करता है जब कि वह डिवीजन ७५ लाख रुपये का होना चाहिये। इतना खचीला इस विभाग को बना दिया गया है यह गौर करने की बात है।

इस विभाग में भष्टाचार का मूल कारण ठेकेदारी प्रथा है। आजादी के बाद ठेकेदारी के कारण ही इस विभाग के अधिकारियों की आर्थिक स्थिति सुधरी है जिनके जरिये उन्होंने जायज और नाजायज तरीके से रुपया कमाया है और जिन्दगी के रहन-सहन का स्तर उनका बहुत ऊंचा चला गया है। इस विभाग के स्वीकृत बजट का १०, १५ फीसदी रुपया गलत तरीके से ठेकेदारों की जेब में, ओवरसियर तथा इंजीनियर्स की जेब में चला जाता है और हम यहां केवल शोर करके रह जाते हैं, जैसे एक परम्परा सी बन गयी है उसका चर्चा करना। मेरा निवेदन है कि ठेकेदारी प्रथा को फौरन खत्म करना चाहिये। इस विभाग का यह विश्वास है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जायगी तो प्रशासन नहीं चलेगा। एक पुल टूट गया तो कमेटी बैठती है, जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर पाती। किसी को ट्रांसफर कर दिया या सस्पेंड कर दिया। आप विभाग के अन्दर जिम्मेदारी फिक्स कीजिये और जो भी उसके लिये जिम्मेदार हो उसे पकड़ा जादा चाहिये।

फेरीज बनती हैं। सारा काम विभाग करता है। पीपे लाना, पुल बनवाना, सभी काम विभाग करता है और फिर ठेकेदार के सुपुर्द कर देता है कि पैसा वह वसूल करे और जितना मुनाफा इस प्रकार होता है वह ठेकेदार के घर चला जाता है। क्यों नहीं विभाग से यह काम कराया जाता है जब सारी की सारी जिम्मेदारी विभाग की है ? इसलिये ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना निहायत जरूरी है क्योंकि अधिकारी और ठेकेदारों की जेब में खूब रुपया जाता है और उसका भार गरीब जनता पर आता है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सूबे के अन्दर सड़कों का कार्य काफी हद तक पूरा नहीं हुआ है। पूरे देश के मुकाबिले में यह प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। यातायत के साधन जब तक सुलभ नहीं होंगे तब तक सामानों के दाम भी बढ़ेंगे। सामानों का मौके पर पहुंचना भी कठिन होता है और यह सब कठिनाइयां हमारे सूबे में इसीलिये हो रही हैं कि सारी योजनायें पूरी नहीं हो रही हैं।

मैं इस विभाग के कर्मचारियों के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बदकिस्मती है कि मेहनत करने वाला मजदूर है उसकी ओर यह सरकार ध्यान नहीं देती है। जो सड़कें हैं उन पर १,२८५ गैंग काम करते हैं उनमें ४०, ५० हजार मजदूर काम करते हैं। मजदूरों के साथ इस सरकार की नीति बड़ी शर्मनाक है। गाजीपुर और आजमगढ़ के मजदूरों को मिलने वाले वेतन में बड़ा फर्क है। एक गैंग के अन्दर एक ही स्थान पर भेदभाव है। सरकार का कहना यह है कि उसको जहां मजदूर सस्ता मिलता है, वहां पर सस्ती मजदूरी देती है और जहां मजदूरों का अभाव है वहां मंहगी मजदूरी देती है। इस प्रकार मेहनत करने वालों के साथ यह सरकार सौदे बाजी करती है। चमोली में एक मजदूर को ४५ रुपये मिलता है तो नैपाल से आये मजदूर को १००, १५० रुपये तक दिये जाते हैं।

(इस समय २ बजकर ५९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

यह सौदेबाजी, मैं समझता हूं, मजदूरों के साथ बन्द होनी चाहिये। प्रजातंत्र तथा कल्याणकारी राज्य के अन्दर यह अनुचित है। मजदूरों को परमानेंट किया जाय। २५, ३० साल से ज्यादा के जो मजदूर, मेट तथा बेलदार काम कर चुके हैं उनको स्थायी करना चाहिये और उनको दूसरी सुविधायें मुहैया होनी चाहिये। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय ने पिछले साल कुछ आश्वासन दिये थे। आजमगढ़ में सड़क कूटने वाले मजदूरों की जनवरी की तनख्वाह नहीं मिली, दिसम्बर में नहीं मिली। एक महीने के बाद जनवरी की तनख्वाह मार्च में मिलती है। इंजीनियर को तनख्वाह अगर कलक्टर से कम मिलती है तो वे काला बिल्ला लगाकर घूमते हैं और कहते हैं कि हम टेक्नीकल आफिसर हैं, हमारा सम्मान होना चाहिये, हमारा आदर

[श्री चन्द्रजीत यादव]

होना चाहिये। हम इस बात में उनके साथ हैं कि उनका सम्मान होना चाहिये, उनको आदर मिलना चाहिये और अगर उनको आदर नहीं मिलता है तो यह गलत बात है। लेकिन आप देखें कि सड़क कूटने वाले मजदूर की तनख्वाह अगर एक महीने बाद मिलती है तो भी बड़ी गलत चीज है। मेरी वहां के इंजीनियर से बात हुई। उसने कहा कि १० तारीख तक उनको तनख्वाह मिल जानी चाहिये लेकिन इस बात का ध्यान आफिसर्स नहीं रखते हैं। हमारे पास स्टाफ नहीं है, इसलिये बिल नहीं बन सकते हैं और समय पर तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। यह कितनी हैरत की बात है कि छोटे आदमी को अगर समय से तनख्वाह न मिले तो कैसे मंहगाई के जमाने में उसकी जिन्दगी बसर हो सकती है? इसी तरह से उनको दूसरे अन्य सुविधायें भी मिलनी चाहिये। जैसे प्रावीडेंट फंड, वर्दी की बात है, समय पर काम की बात है और छुट्टी की बात है, इस के लिये माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसके लिये आदेश भेज रहे है और वे सुविधायें उनको मिलेंगी, लेकिन हमें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे के सारे आश्वासन कोरे पड़े रह गये है। यह बड़ी गम्भीर बात है। उसके ऊपर मैं आपके द्वारा मनानीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अन्त में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज तक जब सरकारी कर्मचारियों में बेचैनी है परेशानी है और वे अपनी जायज मांगों के लिये शान्तिपूर्वक तरीके से आन्दोलन चला रहे हैं। इस विभाग में जहां धन इतनी बड़ी मात्रा में खर्च किया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों की तरफ जो छोटे कर्मचारी हैं, सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

मैं एक बात अपने जिले के सम्बन्ध में भी कह देना चाहता हूं। हमारे जिले आजमगढ़ में एक ५ मील का टुकड़ा सठियांव के मुबारकपुर तक का है। इसकी एक अजीब कहानी है। २० हजार की आबादी का यह एक छोटा सा कस्बा है। वहां की बनी हुयी रेशमी साड़ियां बनारस के नाम से बेची जाती हैं। इस कस्बे के बुनकर लोग उस सड़क से जाने का साहस नहीं कर सकते क्योंकि उस सड़क से जाना जिन्दगी को खतरे में डालना है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस सड़क का उद्घाटन किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह सड़क एक साल में बन जायेगी। लेकिन आज तक नहीं बन पायी है। मै आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस सड़क की जिसका नाम सुचेता कृपालानी रोड है, इतनी उपेक्षा ठीक नहीं है और जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री के नाम का और प्रतिष्ठा का खयाल करते हुये इस को जल्द बनवाने की कृपा की जायेगी।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। आज निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिस विभाग का जो मालिक होता है जैसे आज सरकार का कोई मंत्री है तो उसे सारें प्रदश को अपना क्षेत्र समझना चाहिये। इस विभाग में आप देखेंगे कि कई जिले ऐसे छोड़ दिये गये है जिसमें कई वर्षों से एक भी सड़क नहीं बनी है और कागजों में दिखाया गया है कि इतनी लम्बी सड़कें बनेंगी। लकिन आज तक सरकार का उधर ध्यान नहीं गया। क्या इस विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी जो इतनी तनख्वाह पाते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता है कि एक जिले से दूसरे जिले में जान के लिये साधन नहीं हैं और जिलों में सड़कें नहीं हैं जिनसे किसानों की उपज बाजार में जा सके? जो पूर्व वक्ता ने कहा वहीं सही मालूल देता है कि मंत्री जी जिस जिले में रहते हैं उसमें सड़कें बननी चाहिये और जहां नह रहते हैं वहां नहीं बननी चाहिये। यह गलत बात है। रोज हाहा कार मचता है कि देश भूखों मर रहा है। आप कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं। जब तक गांव तक सड़क नहीं पहुंच पायेगी केवल शहरों में सड़क बनेंगी तो देहात में पैदा होने वाला गल्ला शहर तक कैसे आयेगा? मुझे कई एक जगह की जानकारी है दस साल में मैंने इस सदन में कई बार कहा है कि फैजाबाद जिले में टांडा तहसील में पूर्वी एरिया में जो दूसरे जिलों को कनेक्ट करता है वहां सड़कें बननी चाहिये। उन सड़कों पर ध्यान नहीं दिया गया। एक सड़क बस्ती में बन रही है जो कि कार्यान्वित की जा रही है कलारी से लेकर सिरौली तक, गोरखपुर से फैजाबाद वाली रोड पर नकी रोड पर सड़क बन गयी है, बीच में एक फर्लांग बाकी है। जब कि किसानों की जमीन

ले ली गयी, उनकी खेती बरबाद कर दी गयी, फिर भी एक फर्लांग बाकी रह गया ? वह सड़क रोक दिया और बीच से तोड़ कर निकाल रहे हैं। वह सड़क पूरी नहीं कर रहे हैं। तो जिस इंजीनियर ने सर्वे किया और मिट्टी डलवाई वह क्या अंधे थे? देख नहीं पाते थे ? इस तरह से सरकार का पैसा दुरुपयोग करना और किसानों की जमीन पर बरबाद करना कहां तक न्यायसंगत है ? इस तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिये।

फैजाबाद जिले में अंग्रेजों के जमाने में जो सड़क बनी थी वही आज भी है। ७-८ मील सड़क पिछले साल बनने को थी नहीं बनी। इस वर्ष ५ फर्लांग बजट में है। गोसाईगंज से रनियां खां रोड। और जिलों में दो-दो पुलियां बन गयीं बड़ी-बड़ी रकम में और सड़कें भी बन रही हैं। फैजाबाद में बसखारी से आजमगढ़ रोड है जो जहगीरा गंज से पक्की है और वहां से राजे सुल्तानपुर तक कच्ची है। बीच में पिकिया तदी पड़ती है। यह १२ मील का एरिया ऐसा है कि वहां यातायात का कोई साधन नहीं है। अगर कत्ल डकैती हो जाय तो थाना जहांगीरगंज तक आने की नौबत नहीं होती। मरीज अस्पताल तक नहीं आ सकता। वहां की जनता को इस सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी। हम लोग आखिर यहां आते हैं तो किसानों की बात कहने के लिये आते हैं। आखिर सरकार किस मर्ज की दवा है ? यहां सरकार के अनुयायी कह दें शहर में बने तो शहर में बनायी जाय, लेकिन उसके अलावा जन प्रतिनिधि आये हैं उनकी बात झूठी मान ली जाती है और काम नहीं किया जाता है। अगर सरकार गांवों की जनता की उन्नति करना चाहती है तो गांव से शहर तक जाने के लिये उनको मार्ग दे। मैं यह चाहूंगा कि जहांगीरगंज राजे सुल्तानपुर सड़क १२ मील की है उसे बनायें। जाहंगीरगंज खंभरियाघाट होते हुए राजे सुल्तानपुर सड़क जाती है जो कि इलाहाबाद को कनेक्ट करती है। गोरखपुर के लोग आते हैं खंभरियाघाट। वहां से पैदल इलाहाबाद या फैजाबाद जाते हैं। अगर वह सड़क बन जाय तो प्राइवेट बसों से इलाहाबाद जान की आसानी हो जाय। इतना बड़ा मेला हुआ लोग पैदल गय काफी सड़कों पर भीड़ रही, लेकिन यहां की पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिली। मैं चाहूंगा कि यह बातें सत्य हैं, इसकी जांय की जाय।

एक सड़क है जो कि फैजाबाद से आजमगढ़ जाती है, फैजाबाद से ५ मील दूर पर दर्शन नगर से अयोध्या तक, अयोध्या तीर्थ स्थान है, दो बार मेला लगता है, दूर-दूर से यात्री आते हैं। सावन में १५ दिन का मेला होता है। वह सड़क ऐसी है कि वहां आप रात को पैदल चलें तो गिर जायं। चार मील का फासला है। वह सड़क आज तक नहीं बनवाई। यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी मिले १८ वर्ष हो गये, इस बीच में तीर्थ स्थान को जो सड़क कनेक्ट करती है सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। इस सड़क पर ध्यान दिया जाय ताकि लोगों को आने जाने की सुगमता हो। अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि इस विभाग में ५०-६० रुपये की मजदूरी करने वाले कुली बेलदार को इतवार को भी छुट्टी नहीं मिलती। उनकी तनख्वाहें दो, दो महीने नहीं दी जातीं जब कि क्लर्क और इंजीनियर अपनी तनख्वाह पहली तारीख को ले लेते हैं। लेकिन जिनके पास के खाने को नहीं, कपड़ा नहीं, उनकी तनख्वाह दो महीने के बाद दी जाय, यह कहां का न्याय है ? सरकार को चाहिए कि यह कोई न कह सके कि हमारी तनख्वाह नहीं दी गयी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री हिम्मतसिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग पर जो वादविवाद चल रहा है वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कटौती द्वारा सुझाव दिये जा रहे हैं और अपने अपने जिलों की मांगें रखी जा रही हैं और इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है वह भी बताया जा रहा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]

मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी के द्वारा जांच करवाना चाहता हूं कि विधान भवन में लोहा लगाया जा रहा है लेकिन जिस मोटाई का लोहा लगना चाहिये वह नहीं लगाया जा रहा है। इसकी जांच करवाइये। दूसरे, मेरे जिले में नरौरा पर बांध बन रहा है। वहां पर लोहा पूरी तादाद में नहीं लगाया जा रहा है, और सीमेंट भी ढंग से नहीं लगायी जा रही है। सामान निकाल कर चार, चार मील दूर चला जाता है। नौ-नौ मन लोहा चोरी हो जाता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जांच करवायें। नरौरा बांध पर अपने रिश्तेदारों को ठेकेदारी में लगाये हुये हैं। वहां रोड़ा आता नहीं रोड़ा दिखा दिया जाता है। काफ़ी गबन है। जो आदेश जाते हैं उनका इंजीनियर पालन नहीं, करते। जून में काम समाप्त न करके उसको आगे खींचा जा रहा है। बाढ़ में कितना माल दबा और कितना माल नहीं दबा, इसकी जांच होनी चाहिये।

इसके अलावा गोंडा जिले में उत्तरौला-रसूलाबाद लेटरल रोड पर काम हो रहा है। वहां असिस्टेंट इंजीनियर ने एक ओवरसियर को लिखा, क्योंकि वहां पर लक्ष्मीचन्द गुप्ता थे, जो ए० ई० के कृपापात्र थे, उन्होंने लिखा कि लक्ष्मीचन्द गुप्ता का उस ठेके में कोटा पड़ रहा था, घाटा पड़ रहा था, और जो आपके इंजीनियर आर० एस० वैश्य थे उनको चिट्ठी लिखा कि उसके द्वारा उस काम का ठेका दूसरे आदमी को दे दो और इंडिकेट कर दो। यह २५ सितम्बर, १९६५ को हुआ। जब उसे नहीं किया गया तो इसकी भी जांच मंत्री जी को करनी चाहिये। वैश्य का इसी मामले पर ट्रांसफर कर दिया गया और इसके बाद वैश्य ने अपना चार्ज देना चाहा तो कोई अधिकारी चार्ज लेने को तैयार नहीं है कि यह सारा सामान कहां जायेगा। तो यह सारी दिक्कतें हैं। मैं यह सारी बातें आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं। यदि यही स्थिति रही तो कैसे काम चलेगा? इस पुस्तिका के २२वें सफे की १९वीं लाइन पर लिखा है—"अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी मसाला, कंक्रीट, पत्थर, बालू, सीमेंट, चूना, डामर तथा ईटों आदि के नैतिक्य परीक्षण किये गये। विभाग में निर्माण कार्य की अभिवृद्धि के साथ ऐसे नैतिक्य परीक्षणों में भी वृद्धि हुयी।,, अब कितना किया, क्या क्या किया, कहां कहां किया, इसमें सदन अन्धकारमय है। कितने मामलों की जांच कराई कितनों में छानबीन हुयी और कितने सही पाये गये, किसी भी मामले को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सभी मामले गोल-माल है। मैं प्रार्थना करूंगा कि जब मंत्री जी भाषण दें, तो इस बात का भी जिक्र करें तो बड़ा अच्छा होगा।

आपने जो पुस्तक दी है, उसमें टारगेट के ऐसे २८ जिले हैं, जिनमें काम पूरा नहीं हुआ। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादा काम हुआ, जैसे देवरिया है और कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर बहुत कम काम हुआ है, जैसे एटा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां पर काम बिलकुल नहीं हुआ है वहां पर काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो मैंने आपके सामने कुछ मोटी-मोटी शिकायतें रखीं जो विभाग में गड़बड़ हो रहा है।

अब मैं कुछ अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। नीम नदी पर गालिबपुर पर पुल बनना बहुत जरूरी है, वहां पर लोगों को आने जाने की बड़ी कठिनाई है। दूसरे, वहां पर जो मेला जाता है उसके भी हित में यह होगा कि यह पुल बन जाये। जिला गोंडा में पिपराघाट पर भी पुल बनना चाहिये। हम लोगों से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये जो सुझाव इस बारे में मांगे गये थे उसमें हमने इन पुलों की मांग की है। उत्तरौला-तुलसीपुर के पिपराघाट पर जो राप्ती नदी पर है, एक पुल बनना आवश्यक है। इस से २०० गांवों के निवासियों का फायदा होगा। वियाट से रामघाट तक सड़क बननी चाहिये, जिस से बुलन्दशहर मिल जायेगा। नरौरा बांध बन रहा है, उसमें घूमकर जाना पड़ता है नरौरा बेलगंज होते हुये। तो यह सीधा रास्ता हो जायगा। यह बातें मैं मंत्री महोदय तक उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं।

मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो एस० ई० के इतने ज्यादा आफिस खोल रखे हैं, यह भी ठीक नहीं है और इसमें तमाम फिजूलखर्ची हो रही है। १-१ एस० ई० आफिस पर डेढ़ लाख रुपये का सालाना खर्चा आता है। जबकि यह आफिस केवल लेटर बाक्स का ही काम करता है। इस आफिस का कोई सक्रिय काम नहीं होता है। इनका कमिश्नरी के आधार पर विभाजन किया जाना चाहिये। एक कमिश्नरी में एक ही एस० ई० आफिस होना चाहिये। इस हिसाब से १२-१३ ही एस० ई० के आफिस होंगे और इस तरह से करीब १८ लाख रुपये सालाना की आपकी बचत होगी। जैसा कि रियायत हुसैन जी ने कहा, चीफ इंजीनियर के ऊपर एक इंजीनियर इन चीफ बैठा दिया गया है। यह भी चीज गलत है। एक रिटायर्ड आदमी को जो ६४ में रिटायर हो गया, सर्विस में बनाये रखने के लिये एक नया पद ही इंजीनियर इन चीफ का बना दिया गया, जिससे उसे फायदा पहुंचे। यह परिपाटी जो आप चला रहे हैं यह बहुत गलत है और बहुत गड़बड़ है तथा यह प्रजातंत्र में ठीक नहीं रहेगी इससे आपका समाजवाद खतरे में पड़ जायगा। आप हर अफसर को कहां कहां नौकरी देंगे ? एडिशनल भी आपने एक कर रखा है, उनको भी कम किया जाय और सब को कम करते हुये आप बचत कर सकते हैं।

अब इस बचत को आप कहां दें ? इसके लिये मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो सड़कें टूट गयी हैं तथा जो अपने खून पसीने को एक करके सारे निर्माण कार्य को करते हैं और अपना समय लगाते हैं, उनकी तनख्वाह आपको बढ़ानी चाहिये और उन सड़कों के निर्माण कार्य में लगावें। अभी एक सवाल के जवाब में बतलाया गया कि पूरब में पश्चिम से तनख्वाह कम है। इसका कारण यह है कि पश्चिम में लेबर नहीं मिलते, वहां भी पूरब से ही लेबर आते हैं और फिर उनको आप पश्चिम के हिसाब से ही तो मजदूरी देते हैं। तो इस हिसाब से पूरब और पश्चिम के डिफरेंस को खतम कर सब लोगों को एक सी तनख्वाह दें। साथ ही वर्कचार्ज मैन के सर्विस रूल्स भी अभी तक आपके यहां नहीं बने हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये कि उनके सर्विस रूल्स शीघ्र से शीघ्र बन जायं जिससे २०-२० वर्ष से जो कर्मचारी टेम्पोरेरी पड़े हुये हैं वे परमानेंट हो सकें। आपका विभाग तो टेम्पोरेरी नहीं है, फिर भी इस तरह की चीज वहां है जो नहीं होनी चाहिये। लिहाजा उनके सर्विस रूल्स जल्द से जल्द बनवाने की आप कृपा करें।

इसके अलावा पहले ढाई हजार रुपया प्रति मील सड़कों के रखरखाव पर मिलता था जिसे बढ़ा कर आपने साढ़े ३ हजार रुपया तो कर दिया, लेकिन जहां पहले एक आदमी था वहां आपने पौन आदमी कर दिया। रखरखाव पर खर्चा तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन आदमी को कम दिया। जब आपने खर्चा बढ़ा दिया तब तो आपको आदमी बढ़ाने चाहिये थे और जो छटनी की योजना है उसे न लागू करके वहां तो आदमियों की तादाद बढ़ा देनी चाहिये। अगर यह नियम लागू कर दिया जाय तो लेबर डिपार्टमेंट का कल्याण हो जायगा। आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे छोटों को अधिक दें तथा ठेकेदारी प्रथा को इस विभाग से समाप्त कर दिया जाय तो इससे भिाग का बहुत लाभ हो सकता है। आज स्थिति यह है कि ठेकेदार असिस्टेंट इंजीनियर से मिलकर ४ हजार का काम एक काम एक हजार में ही कर देता है और बाकी रुपया दोनों मिल कर खा जाते हैं। इसलिये ठेकेदारी प्रथा को इस विभाग से खतम कर देना चाहिये क्योंकि इसी प्रथा की वजह से ही इस विभाग में सारी गड़बड़ी है। बहुत जगह उचित मात्रा में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है जिससे छतें चूती हैं और यह चीज तो आपके आडिट रिपोर्ट में ही मौजूद है कि २ करोड़ से ज्यादा रुपया विभागीय कर्मचारियों द्वारा जो खर्च हुआ है वह गलत है। इसलिये ठेकेदारी प्रथा तो आप शीघ्र से शीघ्र समाप्त करें।

श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर सदन में काफी आलोचना हुई और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जिन लोगों को कहा जाता है कि वे सरकारी पक्ष से किसी बात के उपस्थित किये जाने पर उसकी तारीफ करते हैं उन्होंने भी आलोचना की। इसलिये मेरी राय में अब मुझे न आलोचना करनी चाहिये न तारीफ, लेकिन वास्तव में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आलोचना में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं और इस पहाड़ की आलोचना की गई कि इससे अधिक और क्या हो सकती है। एक तो अपने अपने जिलों की सड़कों के बारे में विशेष जोर दिया गया है और यहां तक एक माननीय सदस्य चन्द्रजीत यादव ने कहा कि एक प्रमुख अभियन्ता की पोस्ट अलग से करके सरकार ने इस तरीके से रिटायर होने वाले व्यक्तियों को यह मौका दिया है कि उन्हें आराम से खाने पीने के लिये पेंशन के रूप में पैसा मिलता रहे। हमारे माननीय कमलासिंह यादव तथा हरदोई वाले जे० पी० मिश्र जी ने इस बात का संकेत किया है कि मंत्री न होने पर सड़क या कोई काम इस विभाग द्वारा उस जिले में मुश्किल से हो पाता है और अगर होता भी है तो नहीं के बराबर होता है। मेरी राय में अगर ऐसी धारणा जन प्रतिनिधियों एवं जनता में बनती जा रही है तो मैं समझता हूंकि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में यह बात हितकर नहीं है। जिस जिले का कोई मंत्री नहीं है उस जिले में कोई काम नहीं होगा यह धारणा नहीं बननी चाहिये।

वास्तविकता क्या है, किन परिस्थितियों में क्या करना पड़ा इसकी बिना सही जानकारी के किसी को ऐसी बातें कहना मुनासिब नहीं है। मैं किसी की नीयत पर शक करने के लिये तैयार नहीं हूं। हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति के कारण कहीं कोई काम ज्यादा होता हो, यह बात तो अपनी जगह पर अलग है। क्योंकि मंत्री सब जिलों के एक साथ नहीं हो सकते हैं, उनकी संख्या निश्चित है। काम सब जिलों में होना है, इसलिये प्रत्येक विभाग के मंत्रियों को समानता की दृष्टि रखना आवश्यक है।

मैं अपने जिले की किसी खास बात के लिये संकेत नहीं करता हूं, केवल दो-तीन बातें आपकी मार्फत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं जो अधिक जिलों के लिये लाभदायी होंगी। श्रीमन्, आप जानते हैं कि एक इटावा-बरेली रोड जो फर्रुखाबाद होकर जाती है उस पर गंगा व रामगंगा पड़ती है। उसके आस-पास के रहने वाले सभी लोग इससे संबंधित हैं। लगभग २० वर्ष पहले से जब यहां पर अंग्रेजी शासन था तब से उस पुल के बारे में बड़ी चर्चा हम सुनते हैं। पुराने लोग यही कहा करते थे कि उनकी जिन्दगी में यह पुल नहीं बनेगा, यह स्वप्न की बात है। जिस प्रकार से लोग हवाई जहाज के लिये पहले बहुत ताज्जुब किया करते थे उसी प्रकार से उस पुल के लिये लोग आज भी यह ताज्जुब करते हैं कि क्या सरकार इस पुल को बनाने की सोच रही है और क्या यह पुल कभी बन जायगा? मैं ऐसा समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में शायद कोई ऐसा महत्वपूर्ण किसी दरिया का पुल नहीं है जो बाकी रह गया हो। मैं यह शिकायत नहीं करता मेरा जिला कोई अलग नहीं है। वहां किस लिये नहीं बन रहा है, कौन सी बात है, कहीं कोई कमजोरी है? यदि कुछ बात है तो सरकार को पूरा ध्यान देकर बीच के जिलों की जनता की इस धारणा को दूर करने का प्रयास करना चाहिये कि हमारे जिलों में कोई मंत्री नहीं है नहीं तो पुल बन जाता। सरकार सबके लिये समान है इसलिये इस पुल पर पूरा ध्यान देना उचित है। इस कार्य के संबंध में जो पुस्तिका यहां पर प्रस्तुत की गई है उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि उत्तर प्रदेश में किन-किन बड़ी योजनाओं के लिये सरकार ने केन्द्रीय सरकार से १९६६-६७ के बजट में पूरा करने के लिये सिफारिश की हैं। इसके आंकड़े जरूर दिये जाने चाहिये थे कि हमारे प्रदेश में कौन-कौन से काम होने के लिये पी० डब्लू० डी० द्वारा पूरा कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की गई है। मैं इसलिये आपकी मार्फत सरकार से बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि यह पुल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका ७-८ जिलों की जनता से बड़ा

घनिष्ट संबंध है। इसलिये उद्योग की तथा सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उसका बनाया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वहां पर फतेहगढ़ मिलीटरी ट्रेनिंग सेन्टर है और उत्पादन में डेढ़ करोड़ मन के लगभग आलू पैदा होता है जो बाहर जाता है। उद्योग की दृष्टि से भी वह बहुत ही आवश्यक रोड है। औद्योगिक दृष्टि से भी फर्रुखाबाद महत्वपूर्ण स्थान इस पुल के बनने पर हो सकता है। यातायात और औद्योगीकरण और सैनिक दृष्टि से. उस पुल को बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उसको प्राथमिकता देकर निश्चित तौर पर पुल बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

एक बात मैं और सफाई के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० के जितने घाट हैं जिन पर रोडवेज की बसें चलती हैं, पता नहीं यह सरकार के ध्यान में क्यों नहीं है कि उन घाटों से गुजरने से बस की सवारियों पर टोल टैक्स चार्ज करते हैं। वह टोल टैक्स कहीं-कहीं इतना हो जाता है कि जितना बस का किराया भी नहीं होता। मैं यह नहीं समझता कि जब हमारा केन्द्रीय रेलवे मंत्रालय या यातायात मंत्रालय ऐसा काम करता है तो यहां पर क्यों अन्तर किया जाता है? वह सड़क भी बनाता है और रेल का पुल भी बनाता है। हमारा परिवहन विभाग पुल नहीं बनाता है और सड़क भी नहीं बनाता है, तब भी यह क्यों इस तरह से किराया चार्ज करते हैं? पी० डब्लू० डी० ने जनता के लिये पुल बनाकर दिया है तो क्यों टोल टैक्स चार्ज करते हैं? कहीं-कहीं पर तो ऐसा होता है कि है पांच आना किराया रोडवेज का और ४१/२ आना टोल टैक्स लग जाता है। मेरी राय में यह न्याय संगत नहीं है। सरकार को इस पर गौर करना चाहिये और जनता को इस प्रकार के टक्सों से बचाना चाहिये।

तीसरा सुझाव मैं सरकार के सामने रखता हूं। मुझे यह जान कर बहुत प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने संभवतः अपने किसी जी० ओ० द्वारा मुरादाबाद, चन्दौसी, बदायूं, फर्रुखाबाद रोड को प्राविन्शियल हाई वे रोड के नाम से घोषित किया है। लेकिन इस बजट में इसको कोई तरजीह नहीं दी गई है जिससे फर्रुखाबाद से मुरादाबाद केवल १२६ मील रह गया है। जो सड़क ४५ जिलों के यातायात के लिये सुविधा प्रदान करती है उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें बस बीस मील ही रोड कच्ची रह गई है, चन्दौसी में बिजली का पावर हाउस है। जहां बिजली नहीं है वहां चन्दौसी से बिजली दी जा सकती है। वह इलाका ऐसा है कि जहां बहुत अन्न उत्पादन हो सकता है। राम गंगा और गंगा के बीच का वह इलाका है और अधिक उपजाऊ इलाका है और जो बदायूं और शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद जिलों में है। वहां सरकार रोडवेज की बस चला कर जनता को यातायात की सुविधा प्रदान कर सकती है। इसके लिये केवल उसे १०-२० मील सड़क पक्की बनानी थी उसका जिक्र इस बजट में नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करें और यदि असंभव न हो तो इसके लिये वह कुछ विशेष व्यवस्था करें ताकि लाखों लोगों को यातायात की सुविधा मिल सके। इसके बाद में प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो, तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। देवरिया और गाजीपुर जो पूर्वी जिले हैं उनके लिये एक पटेल कमेटी बनी थी उसने जांच भी की और उस पर सरकार का पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन उसकी सिफारिशों पर कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने दो पुलों का सुझाव दिया जो बिहार से संबंध रखते हैं। वहां एक छोटी गंडक है जो बिहार और यू० पी० की सरहद पर है। वह देवरिया के पूर्व में पड़ती है। देवरिया का कुछ हिस्सा उस के पार है जो बिहार में है। उस पर पुल बनाने

[श्री कृष्ण]

के लिये पटेल कमेटी ने सुझाव दिया था, लेकिन मंत्री जी का ध्यान उस ओर नहीं गया है। हम लोग बराबर पुरानी बरहज सड़क के लिये ध्यान दिलाते रहे हैं। पटेल कमेटी से भी उस सड़क के बारे में कहा गया कि अगर यह बना दी जाय तो सरकार का बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन इस किताब में केवल दो सड़कों का नाम है। देवरिया में एक भी पुल बनाने का जिक्र इस किताब में नहीं है। सिर्फ ११ मील की सड़क एक भटनी से, एक हाटा से और एक सलेमपुर से लिये जानें की बात कही गयी है। कुल देवरिया में ११ मील की सड़क बनने वाली है। श्रीमान् जी, आपके द्वारा मैं मंत्री जी का ध्यान देवरिया में बने बस स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। साल भर उसे बने हुये हो गया, उसकी सारी बिल्डिंग्स फूट गयी हैं। वहां एक पुल बना है वह भी टूट गया है। मंत्री जी इसको अपने आप देख लें कि इस में कितना बालू और कितना सीमेंट लगाया गया है। आज सीमेंट दस रुपये बोरी मिल रहा है, लेकिन जब वह बना था तो ब्लैक में सीमेंट २२ रुपया बोरी बिकता था और वहां का सारा सीमेंट ठेकेदारों और इंजीनियरों द्वारा ब्लैक कर लिया गया है। अब हम तो मंत्री जी से कहेंगे कि फिर से जांच कर लें। जो इंजीनियर, ओवरसीयर देवरिया के बस स्टेशन को पास किया है उस पर उनको कार्यवाही करनी चाहिये और जांच करें कि वह कैसे पास हो गया और फिर ढह गया, टूट गया, फट गया, मंत्री जी चल कर देख लें।

दूसरी बात यह कि देवरिया से पूरब दोनों तरफ बिहार से सड़क आ गयी है, देवरिया से सड़क चली गयी है। सिर्फ एक छोटी गंडक है, वही रुकावट हो गयी है। अगर एक पुल महुवा पाटन और बरियारपुर के बीच बन जाय तो बिहार से यू० पी० का संबंध स्थापित हो जायगा। देवरिया में दो-दो डिग्री कालेज हैं। वहां पर बिहार से, छपरा जिले के लोग पढ़ने आते हैं। छोटी गंडक के पार दूसरे गांवों के विद्यार्थी देवरिया में आते हैं। पिछले साल छोटी गंडक में जिसमें छोटी-छोटी नावें चलती हैं, उसमें एक नाव उलट गयी और ४–५ व्यक्ति मर गये। तो वह पुल निहायत जरूरी है संबंध स्थापित करने के लिये, लेकिन मंत्री जी का ध्यान उस तरफ नहीं गया है। कोई बड़ी नदी नहीं है, बरसात में जरूर पानी हो जाता है, आज कल तो बहुत कम रहता है।

जो छोटे मजदूर सड़क पर काम करते हैं, चाहे मेट हों या चौकीदार ये सब अधिकारियों के घर का काम करते हैं। मंत्री जी चाहें तो जांच कर लें, स्वयं चल कर देख लें। वही गाय चराते हैं, बर्तन धोते हैं, चौका बर्तन करते हैं। अगर वह काम करने में हिचकें या कोई जवाब सवाल करें तो उनको दूर ट्रांसफर कर देते हैं, उलट पुलट देते हैं। जो उनकी खिदमत में रहेंगे तो उनको वहां पर रखेंगे। इस संबंध में मंत्री जी को उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

गोरखपुर, देवरिया, छपरा बार्डर के जिले हैं जो नेपाल-चीन की सरहद पर हैं। हमारे साथी कहते हैं कि पूर्वी जिलों का ज्यादा काम हो जाता है। श्रीमान् जी, यह सरकार समाजवादी सरकार होने का दावा करती है तो जो पिछड़े हुये जिले हैं, गरीब हैं, अगर उनको उठा कर जो आगे बढ़े हुये हैं उनके बराबर में नहीं लायेंगे तो समाजवादी सरकार क्यों कर है? तो यह पूर्वी-पश्चिमी जिलों की बात तो हम बिलकुल नहीं चाहते हैं, हम तो कहेंगे कि जहां गरीबी हो, पिछड़ापन हो उस जिले को पहले लिया जाय और पिछड़ेपन को दूर किया जाय।

(लाल बत्ती होने पर) मुझे एक मिनट और देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो मिनट ले लें।

श्री कृष्ण—

मंत्री जी जरा ध्यान दें कि एक डाकखाना देवरिया में बना है, जो ठेकेदार और इंजीनियर था उसने पास किया है। आप चल कर देख लें कि उसमें बालू की मात्रा कितनी ज्यादा है और

सीमेंट की कमी है। वह मकान सब गिर जायेगा और सारा रुपया सरकार का बरबाद हो जायेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, काफी लोग बोलने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि समय बोलने का कुछ कम कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, अब ५-५ मिनट माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

अनेक सदस्य—

एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुझे कोई एतराज नहीं है, सदन जब तक बैठना चाहें बैठ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती यशोदादेवी (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझ बोलने का अवसर दिया। मैं अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहती हूं। हमारे क्षेत्र में एक पुल और एक सड़क की बहुत जरूरत है। उसके न होने से जनता को बड़ी परेशानी होती है। हमारे यहां यातायात के साधन बिलकुल नहीं हैं। न वहां पर कोई रेलवे लाइन है और न ही अब तक वहां के लिये कोई विकास के कार्य हुये हैं। वहां की जनता बहुत परेशान है। वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे हमारे यहां कम से कम तिकरीगंज से तोपाई घाट ४ ठोकर, बेलघाट से कुरी तकतवा उरवा से घुरियापार होकर नरगड़ा पार तक एक सड़क बनवा दें। यह सड़क पी० डब्लू० डी० द्वारा बनायी जाय। इसकी बहुत जरूरत है। १० मील लम्बी यह सड़क बन जाने से जनता की काफी परेशानी दूर हो जायगी।

इस सड़क के अलावा दो पुल बनना भी बहुत आवश्यक हैं। तोपाई घाट और घुरियापार पर एक पक्का पुल बनना बहुत जरूरी है। वहां पर लकड़ी का एक पुल बना दिया जाता है। उसको पार करने के लिये कभी-कभी दो-दो घंटे तक इन्तजार करना होता है।

मेरा यही नम्र निवेदन है कि मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र में एक घुरियापार में और उरवा से घुरियापार होकर नरगड़ा पार तक एक सड़क अवश्य बनवा दें। यही मुझे निवेदन करना था।

हमारे एक भाई ने पूर्वी जिलों की बात कही। आज जा कर देखिये कि वे लोग सड़क पर बसे हैं जिनका मकान दरिया में चला गया है। जैसा कि हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि स्त्री पुरुष, बच्चे सभी एक ही मकान में रहते हैं, चल कर देखिये, वैसे ही वहां पर हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर कुछ होना चाहिये। वहां पर हम सड़क और पुल चाह रहे हैं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोध करूं या इसके पक्ष में बोलूं, इसमें कोई अन्तर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं, श्रीमन्, आप भी यह देख रहे होंगे कि जो हक में बोलने वाले हैं वे सिवाय इस शब्द के कि मैं हक में हूं, बाकी सारी जितनी बात कहते है सब विरोध की कहते हैं। कोई भी सदन के अन्दर ऐसा भाषण नहीं हुआ जिससे यह मालूम हो कि सदन के सदस्य आज के इस अनुदान के पक्ष में बोल रहे हों या सन्तुष्ट हों कि जो कुछ हो रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से, उस से प्रान्त के अन्दर सन्तोष है या सदन के सदस्यों के अन्दर सन्तोष है।

मैं उन तमाम बातों की तरफ ध्यान नहीं दिलाना चाहता जो सदन में कही जा चुकी हैं। लेकिन एक बात जरूर मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं कि यदि आपने पंजाब के अन्दर जो इस वक्त लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ उस तरफ जरा-सा ध्यान दिया होता तो श्रीमन्, आपको पता चलता कि अमृतसर से चौदह मील पर वाघा पड़ता है। उस इलाके के अन्दर जो हालत हमारी फौजों की थी बार्डर की सुरक्षा की, वह न आपसे छिपी हुई है और न हमसे छिपी हुई है। लेकिन जितनी तैयारी पाकिस्तान की उस दिन से पहिले होती रही और हमारे यहां इस चीज में सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसके बावजूद हमारी फौजों ने जितना काम करके दिखाया वह बहुत ही सराहनीय रहा है। उसके अन्दर पंजाब के सार्वजनिक निर्माण विभाग का बड़ा हाथ था। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस तरफ जरूर दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां सड़कों के दोनों तरफ खाली जमीन पड़ी हुई है, हजारों नहीं लाखों एकड़ धरती बिलकुल बेकार पड़ी हुई है, जिसके अन्दर न पेड़ हैं और न घास है। श्रीमन्, जिस वक्त आक्रमण हुआ पाकिस्तान का और उनके हवाई जहाज उड़ कर हमारे रास्ते से आने लगे तो पंजाब सरकार ने पता नहीं जाने से या अनजाने से कुछ ऐसा कर रक्खा था कि सड़कों के दोनों तरफ चार-चार लाइनें पेड़ों की लगी हुई थीं और घने पेड़ थे। हमारी फौजे उन पेड़ों के नीचे-नीचे जा रहीं थीं। पाकिस्तान के हवाई जहाज ऊपर मंडरा रहे थे। चौबीसों घंटे हमारी फौजें सामान लेकर आगे बढ़ती चली जाती थीं और उनके हवाई जहाज बिलकुल नाकारा साबित हुए। वे लोकेट नहीं कर पाये।

श्रीमन्, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं सुरक्षा की दृष्टि से नहीं केवल पूरे प्रान्त के अन्दर देश के अन्दर हर वर्ष हम वन महोत्सव मनाते हैं, लाखों पेड़ लगाये जाते हैं। अगर हमारा यह सार्वजनिक निर्माण विभाग वन लगाने की तरफ ध्यान दे, अगर खुद न लगा सके तो वन विभाग को दे दे तो बहुत पेड़ लग सकते हैं। उससे वर्षा भी अच्छी हमको मिल सकेगी, सड़कों के किनार साया भी हमको मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमारी जनता के अन्दर एक हिम्मत पैदा हो जायगी। हम देखते हैं कि पेपर मिलों और गल्ला मिलों के लिये जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनको लगाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़कों के किनारे पड़ी हुई लाखों एकड़ जमीन इसके काम में लायी जा सकती है। आप पंजाब में जाकर देखिये जहां से आपका बार्डर खत्म होता है, फर के दरख्त शुरू हो जाते हैं। इस बारे में पंजाब से सबक लेकर आप जंगलों का जाल सारे प्रान्त में बिछा दीजिये। इससे सड़कों पर साया मिलेगा, सड़कों की मजबूती होगी, ईंधन की लकड़ी मिलेगी, चारा भी मिल सकता है।

यह ठीक है कि हमारे प्रान्त में जितनी सड़कें बननी चाहिये थीं उतनी नहीं बन पायी हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें धन की कमी भी हो सकती है और काम करने वालों की नेकनीयती में भी कमी हो सकती है। मंत्री जी भी इस बात को मानते हैं और हम भी बारबार इस चीज को दुहराते हैं, उसका भले ही असर हो या न हो। बहुत-सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कहा तो जा सकता है, लेकिन उन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत-सी ऐसी सड़कों की तरफ में माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा जिनको बनते हुये १५–२० साल हो गये लेकिन पूरा होने के पहले ही उनका टूटना शुरू हो गया है। सहारनपुर से दिल्ली को दो मार्ग जाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सन् ४७ से उसको बनाया जा रहा है। अभी १०० मील का टुकड़ा ही बन पाया है और इस १०० मील में करीब ४० जगह इस समय मरम्मत हो रही है। वह भी १-१, २-२ मील लगातार टूटी होगी। जब तक यह ठीक होगी दूसरी जगह से टूट जायगी। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और सड़कों की मजबूती और अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर ध्यान देना चाहिये। यह देखना चाहिये कि कितने दिनों में कोई चीज मरम्मत के काबिल होनी चाहिये। अगर सरकार ने इन दो बातों की तरफ भी ध्यान दिया तो वह प्रान्त की काफी तरक्की कर सकेगी।

श्री रघुबीरसिंह—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय मन्त्री महोदय के भाषण को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने अपने भाषण में अपने विभाग का विवरण और परिचय देते हुए अन्त में यह विचार व्यक्त किया कि इस साल वह केवल महत्वपूर्ण मार्गों और पुलों को ही निर्माण हेतु ले सके हैं। बात ठीक है, जब धन का अभाव है तो काम कम होगा ही लेकिन मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कार्य को कराने का उनका आधार क्या है? कभी-कभी तो यह विभाग स्टार-ग्रिड फार्मूले की बात करता है और कभी कहता है कि हम आवश्यक और महत्वपूर्ण मार्गों को ही ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी अपने भाषण में स्पष्ट कर दें कि अब भी उनका आधार स्टार-ग्रिड फार्मूला ही है या जिस कार्य का वह महत्व समझेंगे वही महत्वपूर्ण माना जायगा। जो स्टार-ग्रिड फार्मूले का सिद्धांत था वह एक तरह से ठीक था लेकिन आज मन्त्री जी या उन का विभाग यह कह कर भले ही सन्तुष्ट या खामोश कर दें कि अमुक स्थान सुरक्षा की दृष्टि से या किसी और कारण से ज्यादा महत्व का है लेकिन इस संसार में, या इस देज में या इस प्रदेश में सब से पहली जो सब से आवश्यक वस्तु है वह है खाद्यान्नों का समाधान। इसके अभाव में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए सब से आवश्यक है। जिन जिलों में खाद्यान्न सब से अधिक पैदा होता है उन स्थानों को सड़कों एवं पुलों के निर्माण में प्राथमिकता देना चाहिए वर्ना जितनी भी वहां की पैदावार है वह ठीक समय से बाजार में नहीं पहुंच पायेगी और किसानों को ठीक से मूल्य नहीं मिल सकेगा। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह जो पुस्तिका मिली है उसमें उन्होंने बता दिया है कि स्टार-ग्रिड फार्मूला के अनुसार कितना होना चाहिए था और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना हो पाया है और कितना बाकी है। जो यह कालम ९ में बाम्बे फार्मूला के अनुसार दिया है उस में भी उन्हीं जिलों की ज्यादा सड़कें दी गई हैं जो कि पहले से ही सरप्लस थे। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि स्टार-ग्रिड फार्मूला की अवहेलना इस हद तक क्यों की गई है कि जो जिले माइनस में चल रहे थे उन को क्यों पिछड़ा हुआ रखा गया है? यह कार्य विभाग की उदासीनता का प्रतीक है।

नदरई-जलेसर सड़क के लिए २ साल पहले मैंने एक प्रस्ताव रखा था और सुझाव भी दिया था और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी कहा था कि हमारे जिले का एक चौथाई भाग ऐसा पिछड़ा हुआ है जहां कोई सड़क नहीं है जब कि फार्मूले के अनुसार भी वहां के लिए औचित्य है। यदि वहां सड़क बनाई जायगी तो वह ३ नेशनल हाईवेज को मिला देगी, जैसे १—बरेली-मथुरा, २—एटा से जलेसर होती हुई जो सड़क आगरे को जाती है, और ३—जी० टी० रोड जो एक नेशनल हाईवे है और इन ३ सड़कों को मिलाने वाली नदरई-जलेसर सड़क के

[श्री रघुवीरसिंह]

लिए मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगर जिला परिषद् इस के लिए प्राथमिकता देगी तो चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में इसको ले लिया जायगा। तदनुसार जिला परिषद्, एटा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर के भेजा और मैंने दूसरी मीटिंग में मन्त्री जी की सेवा में उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अब सड़क को विभाग द्वारा पक्का कराने की कृपा कीजिएगा। हमें आशा थी कि इस सड़क को इस वर्ष ले लिया जायगा। उस सड़क का सर्वे भी कराया गया लेकिन इस सड़क की हां बात क्या, एटा जिले के नाम पर एक फर्लांग भी कोई सड़क नहीं है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई है। जब सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जाती हैं तो मेरठ, आगरा डिवीजन आदि जिलों को सरप्लस कहा जाता है कि वहां कोई दूकानें खोलने की जरूरत नहीं है, वह सरप्लस जिले हैं, जब पूर्वी जिलों में ५०० दुकानें खोली जाती हैं तो वहां ४०–५० ही खोली जाती हैं। लेकिन अगर ऐसे जिलों में सड़कों की भी कमी होगी तो न केवल इन जिलों को ही कठिनाई उठानी पड़ेगी अपितु अन्य जिले जहां खाद्यान्न की कमी है, उन्हें भी सुविधापूर्वक अन्न नहीं मिल सकेगा। तो मैं कहता हूं कि आखिर किसी भी जगह पर किसी एक सिद्धांत से काम नहीं किया गया है। माननीय मन्त्री जी से आशा तो कम है मगर विश्वास अधिक है। अगर माननीय मन्त्री जी स्वयं जाकर देख लें तो ठीक समझेंगे कि यह सड़क अत्यन्त आवश्यक है और इसी निष्कर्ष पर आयेंगे कि इसका निर्माण होना जरूरी है।

जो जिले सड़कों के सम्बन्ध में सरप्लस हैं और जिन जिलों में पटेल कमीशन चल रहा है, उन जिलों को प्राथमिकता देनी चाहिए या उन जिलों को जो माइनस में हैं? जब तक धन का अभाव है हमें निरीक्षण भवन नहीं बनाने चाहिए। इतने भवन बनाने जरूरी नहीं हैं जितनी सड़कें और पुल। और यदि कहीं भवन की आवश्यकता भी है तो वहां पर हमें मितव्ययिता बरतनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें सड़कों और पुलों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने चर्चा की और हर वर्ष इस विभाग के अनुदान के समय सदन में यह चर्चा होती है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि यह बात असत्य है। मैंने यह सोचने की कोशिश की कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं और दूसरे अधिकारी हैं, वे बड़े-बड़े विद्वान हैं, उन पर इन आलोचनाओं का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर ही पहुंचा कि असल में इसका मूल कारण हमारी शिक्षा पद्धति ही का दोष है। माननीय मन्त्री जी की कृपा से मुझे रुड़की जाने का अवसर मिला और वहां पर इंजीनियरिंग कोर्स के पढ़ने वाले जो हमारे लड़के हैं उनसे बातचीत भी की और उनको देखने का अवसर हुआ। मैंने देखा कि उनका रहन-सहन का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि आगे चलकर सर्विस में भी उन्हें वही खर्चीला रहन-सहन बनाना पड़ता है। उसकी पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में छात्र सादगी से रहना सीखें। अगर इसको ठीक समझा तो मेरे सुझाव को मुख्य मन्त्री तक पहुंचा दें। वहां पर किसी भी बच्चे का २०० रुपए प्रतिमास से कम का खर्चा नहीं है। किसी-किसी बच्चे का तो ३०० और ५०० रुपए तक है। जब एक लड़का ५०० रुपए खर्च करता है तो दूसरे बच्चे को भी अगर अधिक नहीं तो संगत में रहकर कम से कम २५० रु० प्रति मास खर्च करने पड़ते हैं। इसका माता पिता पर कितना वजन पड़ता है और उससे पीड़ित होकर उसके माता पिता भ्रष्टाचारी होते हैं। वह लड़का, जिसका जीवन स्तर ऊंचा उठ गया है, ऊंचे रहन-सहन का आदी हो गया तो उसे उस खर्चे को पूरा करने के लिए अपने सर्विस काल में भ्रष्टाचार करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रघुवीरसिंह—

श्रीमन्, मुझे एक मिनट और दे दीजिए।

साथ ही साथ यह भी देखने की जरूरत है कि हमारे जो इंजीनियर हो जाते हैं, उनके वेतन के अतिरिक्त घूस की आदमनी से धनी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए समाज के धनी लोग, बड़े-बड़े अधिकारी और बड़े-बड़े नेता भी आज अपनी लड़कियों के रिश्ते उनसे करते हैं। वे लड़कियां भी खूब खर्चीली होती ही हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए उन्हें मजबूरन भ्रष्ट होना पड़ता है। इसलिए मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि मेरा यह सुझाव माननीया मुख्य मन्त्री तक पहुंचा दें कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में रहन-सहन सादा होना चाहिए और जो विद्यार्थी निरन्तर सादगी से रहे उसे एक विषय के समतुल्य सादगी के नम्बर मिलने चाहिए। शिक्षा संस्थाओं में एक आध्यात्मिक विषय भी होना चाहिए और उसके भी नम्बर होने चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा के प्रभाव से विद्यार्थी भ्रष्टाचार को पाप समझेगा। तभी हमारे बच्चे आगे चलकर भ्रष्टाचारी न बनेंगे और भविष्य में सादा जीवन उच्च विचार से ओतप्रोत होकर भ्रष्टाचार करने से रुक सकेंगे।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल की ओर से जो इस बजट में कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसके समर्थन में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। वास्तव में इस विभाग में संयोजित भ्रष्टाचार होता है, यदि यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि वह भ्रष्टाचार कौन-सा है। उस के लिए तो विरोधी पक्ष हमेशा और भारतीय जनसंघ खास तौर से कहता ही रहा है। आज जो दोनों पक्षों के भाषण मैंने सुने तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के सदस्यों ने भी इधर-उधर घुमा करके भ्रष्टाचार की बात कही। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो ठेकेदारों को पहले तीन प्रतिशत की घूस देनी पड़ती थी वह अब १५ फीसदी हो गई है। अब आप ही सोचें कि जब ठेकेदार को इतने प्रतिशत घूस देनी पड़ेगी तो वह अपना काम कैसे ठीक बनायेगा या पक्का बनायेगा? पहले तो यह बात ओवरसियर तक ही होती थी लेकिन आज तो चोटी के अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं। जो अधिकारी भ्रष्टाचार के काम करते हैं अगर उन के खिलाफ कोई आदमी काम करता है तो उस का दूसरी जगह स्थानान्तरण हो जाता है या उस को सस्पेंड किया जाता है, या उसकी तरक्की रोकी जाती है, इसका उदाहरण माननीय हिम्मत सिंह जी ने बताया और माननीय नेता, विरोधी दल ने गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर परची दिखा कर कहा था राधे श्याम ओवरसियर के बारे में। वह स्पष्ट है, गोंडा जिले में, बलरामपुर में, उसके बारे में आप को जानकारी है।

जो स्टार-ग्रिड योजना बनी और जिसमें क्षेत्र का रकबा और जन-संख्या का ध्यान रखते हुए सड़कों की लम्बाई निश्चित की गई, उसके आधार पर काम नहीं किया। जिले-जिले, क्षेत्र-क्षेत्र में पक्षपात किया गया है। हमारी मांग है कि मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें और वहां पर ठीक से नई योजना के अनुसार सड़कें बनायें। मन्त्रियों के मकानों तक तो सड़कें बन जाती हैं, लेकिन जो स्थान पिछड़े हुए हैं और खास तौर से गोंडा जिले में तराई का क्षेत्र, जिसके बारे में मैं बाद में कहूंगा, उसकी तरफ मन्त्री जी विशेष ध्यान दें।

एक और बात मुझे कहनी है कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको जो वेतन और भत्ता मिल रहा है वह बिल्कुल नगण्य है। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि उनके बारे में जो श्रमिक कानून छुट्टी, छुट्टी, वेतन और भत्ता के बारे में है उस को लागू किया जाय। गैंग मैन और वर्क चार्ज का वेतन कम से कम १०० रु० से १२५ रु० तक होना चाहिए। जो पांच साल से अधिक काम कर चुके हैं उन को स्थाई किया जाना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे गोंडा जिले में तराई क्षेत्र में सड़कें बनायी जायं। जो बस्ती से तुलसीपुर होते हुए हरैया और चौघरीडीह से बहराइच को मिलाने की बात है उस में जो पुलिया

[श्री सुखदेवप्रसाद]

आदि बन रही हैं उनमें बालू और गीली इंटें ज्यादातर लगायी जा रही हैं, इस की मन्त्री जी जांच करें। इसके अतिरिक्त जो हरिहरगंज से ललिया सड़क जाती है उसकी मंजूरी माननीय मन्त्री जी न दी थी। उदरहिया के पास काठ का बहुत बड़ा पुल है जो कि दो लाख रुपए का मंजूर हुआ था मगर वह शुरू नहीं हुआ और बरसात में सारा काम चौपट हो जायगा। ललिया थाना है और शिवपुरा ब्लाक हेडक्वार्टर है। इनके बीच में ३, ४ पुल बहुत बड़े हैं जिनको बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार टहड़वा से लेकर कौवापुर तक महाराजगंज से हरैया रोड होते हुए सड़क जाती है जो कि बहुत उपयोगी है और इसके जरिए लाखों रुपए का व्यापार होता है, इसको माननीय मन्त्री जी पूरा कराने की कृपा करें। इसी प्रकार लेटरल रोड उतरौला होत हुए बलरामपुर होत हुए बहराइच जाती है उसे नहर बालागंज और हरिहरगंज उजाड़ कर बनाया जा रहा है जबकि बीच के अन्य गांव उकौना, बिजलीपुर और श्रीदत्तगंज के बाहर से उस सड़क को ले जाया जा रहा है। मेरा निवदन है कि नहर बालागंज और हरिहरगंज के बाहर से ही यह सड़क बनाई जाय ताकि लाखों रुपए की सम्पत्ति, पेड़ तथा मकान नष्ट न होने पाय। इसी प्रकार चौधरीडीह से मथुरा बाजार से कटरा बाजार तक पक्की सड़क बनाई जाय जो सरहद होने के नाते बहुत महत्वपूण है।

श्री गणशप्रसाद (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करन का अवसर प्रदान किया। म यह कहूंगा कि बांसगांव तहसील गोरखपुर जिल की सबसे पुरानी तहसील है और बस्ती, गोंडा तथा बहराइच जिले को इस तहसील ने शिक्षा प्रदान की है, लकिन इस तहसील की सदा उपेक्षा होती आई है। इसम एक वर्ग मील के एरिया में १,२५० की आबादी है जो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। इसमें एक वर्ग मील में आठ-आठ गांव ह और वहां एक इंच भी रेलवे की लाइन नहीं है। भारत सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक सड़क थोड़ी सी बनी लकिन फिर उपेक्षा बरती जा रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वहां सड़क का नामोनिशान नहीं है। इसलिए म अधिक समय न ल कर बांसगांव और गोरखपुर जिल की मुख्य-मुख्य सड़कों की तरफ माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

गोरखपुर से कौड़ीराम तक पक्की सड़क है लेकिन कौड़ीराम से बांसगांव तक ५ मील की सड़क पक्की नहीं है। उसे पक्का कराया जाय। कौड़ीराम से गोलाबाजार तक १४ मील सड़क आजमगढ़ को जोड़ती है, लकिन वह पक्की नहीं की गयी और गोला इलाके में जो गन्ना बोया जाता है, पक्की सड़क न होने के कारण वह ८ आन मन पर बिकता है जबकि सारी दुनिया म २ रुपए मन से कम उसका भाव नहीं है। इसी तरह से एक सड़क सिकरीगंज से बेलाघाट जाती है। वह केवल १० मील लम्बी है। वहां पर गन्ना आठ आने मन बिकता है अगर यह सड़क बना दी जाय तो गन्ना दो रुपए मन बिकेगा। इसी तरह से जो किसानों को गरीबी में रखा गया है, उसकी हालत अच्छी हो जायगी। इसी तरह से एक सड़क बांसगांव से नरगडाघाट जाती है जो कमरियाघाट से फैजाबाद को मिलाती है। इसको पक्का कर दिया जायगा तो आजमगढ़, फैजाबाद, बस्ती और गोरखपुर का सम्बन्ध हो जायगा। इसी तरह से एक सड़क खजनी से गोपालपुर तक जाती है जो कि बांसगांव तहसील के बीच से होकर जाती है। यह २० मील लम्बी है, इसको भी ध्यान में रखा जाय और इसको पी० डब्ल्यू० डी० में लिया जाकर इसका सुधार कर दिया जाय। इससे जनता का बड़ा हित होगा और जनता की गरीबी दूर होगी। यहां के लोग गरीब हैं और बाहर कुली बन कर जाते हैं। गोरखपुर का जो कुलियों का अड्डा है उसमें यहां के ९० प्रतिशत कुली और १० प्रतिशत फरेन्दा, महाराजगंज और सदर तहसील के होते हैं। यहां के लोग ही बाहर जाने के लिए फाजिल हैं। एक सड़क और है जिस पर हमारे राष्ट्रपति माननीय राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपने सिर पर मिट्टी लेकर डाली थी। यह जैतपुर से बुकहारोड तक है। यह श्रमदान से बनी थी। इसको जल्दी से जल्दी पक्का करा दिया जाय। यह चार मील लम्बी है। इससे

दोहरी घाट से लेकर बस्ती जिले को मिलाया जा सकता है। आजकल इसके न होने की वजह से गोरखपुर होकर बस्ती जाना पड़ता है। यह बहुत जरूरी है। सरकार को इसे बनवा देना चाहिए। इसको इसी पंचवर्षीय योजना में लेना चाहिए। एक सड़क है कौड़ीराम से गजपुर होकर रुद्रपुर से देवरिया जिले तक पहुंचती है यह ली जाय। बांसगांव से ६ मील है और रुद्रपुर से इसे मिला दिया जाय तो सीधी सड़क देवरिया तक ही जाती है। इसी तरह एक सड़ क है रामजानकी रोड जो फैजाबाद से लेकर अयोध्या होकर सिकरीगंज के उस पार तक जाती है। अगर सिकरीगंज पर पीपा का पुल बना दिया जाय तो बड़हलगंज से सम्बन्ध हो जाय और अगर बडहलगंज से बरहज तक पक्की कर दी जाय तो इससे पूरे देवरिया का सम्बन्ध हो जायगा। एक और सड़क है जो भैंसा बाजार से होकर रजबल, मुदेवा होते हुए मुलनापुर होकर बस्ती से मिलाती है। इसे बना दिया जायगा तो बस्ती जिले से सीधा कनेक्शन हो जायगा। एक सड़क है कैम्पियरगंज से तरमैनीघाट तक जो चार मील लम्बी है, उसको बनवा दिया जायगा तो गोरखपुर से सीधा सम्बन्ध हो जायगा। कैम्पियरगंज-तरमैनीघाट होकर बस्ती जिले से संबंध हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

*श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट के सम्बन्ध में सदन में विचार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने विचार सदन के सामने रखूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग का उत्तरदायित्व प्रदेश पर काफी होता है बल्कि सारे देश में राज्य सरकारों का इस विभाग पर बड़ा उत्तरदायित्व है। मन्त्री जी जब इस पक्ष में थे कि मैं रचनात्मक कार्य करना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी को मुझसे कोई शिकायत न हो, यह भी मैं कहना चाहता हूं कि दो वर्ष पहले उन्होंने माननीय सदस्यों के पास एक इनविटेशन भेजा था और उसमें कहा गया था कि यदि किसी सदस्य को अपने क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई काम कराना हो तो वह कृपया अपने सुझाव हमारे पास भेज दें। जहां तक मैं समझता हूं कि इसको सुनकर मुझ को बहुत बड़ी आशा हुई माननीय मन्त्री जी से। मैं आगरा का रहने वाला हूं और खुशी है कि माननीय मन्त्री जो भी आगरा के रहने वाले हैं, मैं उनकी भावना से सहमत हूं। मैंने उनको अपने सुझाव लिखकर दिए थे, लेकिन जब मैंने सार्वजनिक विभाग का बजट देखा तो मैंने पाया कि मेरे सुझावों को किसी टोकरी में उठाकर डाल दिया गया है। इस पर हमें बड़ा दुख है। इसलिए मैं बहुत ही दुखी हूं। जब जनतन्त्रीय सरकार के अन्तर्गत कभी कोई मिनिस्टर नहीं होता है, तो शायद ऐसी आलोचनाएं करता रहता है, लेकिन जब वह मन्त्री पद पर बैठता है तो वह उन बातों को, जनता के हित को भूल जाता है और वह अपनी पहली कही गयी बातों से बिलकुल पलट जाता है। पहिले तो वह जनता की समस्या को यहां पर हाउस में रखते हैं, अपने विचारों से सरकार को प्रभावित करते हैं और जनता को फायदा भी कराते हैं, लेकिन मन्त्री बनने के पश्चात् अपनी राय बदल देते हैं और अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। केवल एक विचार ही उनके मस्तिष्क में रहता है, जिसके अनुसार वे काम करते हैं। मंत्री जी ने जिन अनावश्यक चीजों को इसमें शामिल किया है वह आवश्यक जरा भी नहीं थीं। यदि उनको न शामिल किया गया होता तो अच्छा था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनवारीलाल विप्र]

श्रीमन्, आप देखेंगे कि आगरा हमेशा से सार्वजनिक विभाग के मामलों में पिछड़ा रहा है। मैंने सन् ६२ से निरन्तर इस बात की मांग की कि जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें इस बात की कोशिश की जानी चाहिए और उनमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए पिछड़े हुए जिलों को, उसमें आगरा भी एक है। सड़कों के निर्माण का जो उद्देश्य है उसके बारे में स्पष्ट लिखा गया है कि सड़कों के विकास का ध्येय यह है कि देश के देहाती क्षेत्रों को विकसित किया जाय और परिवहन के लिए सड़कें पक्की की जायं ताकि वहां के लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। यह जो भावना है वह इस बजट के कार्यक्रम से कतई पूरी नहीं होती है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिस वक्त समसाबाद रोड के अन्तर्गत उटंग नदी का पुल पूरा हुआ और उसका उद्घाटन करने के अवसर पर राजबहादुर जी आए थे, वहां पर मैंने उनको एक ज्ञापन समशाबाद–फतिहाबाद रोड को बनवाने के बारे में दिया था कि इस रोड को पक्का कर दिया जाना चाहिए। वहां पर एक दूसरी मंडी से जिनका आपस में व्यापारिक सम्बन्ध है वह भी जुड़ जाती है, उस रोड पर एक वेटनेरी सेन्टर भी है जिसका कि आजकल बड़ा महत्व है लेकिन उस रोड को पक्का करने की दिशा में इस सरकार के विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया था कि चूंकि वह आपरेशन एरिया है और आए दिन वहां पर डाकुओं की समस्या खड़ी रहती है, दिन में डकैतियां पड़ा करती हैं वह चीज भी इससे हल हो जायगी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस विभाग और परिवहन विभाग को भी यह शिकायत रही है कि यदि यहां पर सड़क बनवा दिया जाए तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायगा। यहां पर इतना डाकुओं का आतंक है कि जब यहां पर बारातें आईं तो वह भी डाकू दलों द्वारा लूट ली गयीं, बारातियों का उन्होंने बुरी तरह से अपहरण तक कर लिया, क्योंकि सड़कों की कमी के कारण घटनास्थल पर पुलिस समय पर नहीं पहुंच सकी। इस सड़क क निर्माण से यह भी फायदा है जिसके द्वारा समसाबाद से फतेहाबाद वाली सड़क कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि यह १२ मील का जो टुकड़ा है वह अछूता ही पड़ा रहा है। यहां पर सारी बसें खराब हो जातीं है, सड़कों की खराबी के कारण, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि वह सड़क नहीं बनवाना चाहते हैं, तो वह हमसे साफ कह दें कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम नहीं बनवा सकते हैं। इसके बावजूद भी सब की यह मांग है कि व्यापारिक दृष्टि से उस सड़क का बन जाना नितान्त आवश्यक है। वहां पर सड़क इतनी टूटी-फूटी है कि हर साल हजारों रुपये बसों की मरम्मत आदि पर खर्च हो जाते हैं। अगर पिछले १८ वर्ष के आंकड़ों को देखा जाय तो जितना रुपया बसों की टूट-फूट पर खर्च हुआ है उतने रुपये अगर उस सड़क के बनाने पर लगा दिये गये होते तो वह सड़क पूरी हो गयी होती।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री गंगासिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा-पिथौरागढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं औपचारिकता के नाते इस बजट का समर्थन करता हूं, क्योंकि मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि जो काम अधूरा है....

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय वक्ता ने कहा कि औपचारिकता के कारण मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। यहां तो हर माननीय सदस्य स्वतंत्र है और उसे अपनी स्वतंत्र राय देने का हक मिला हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य के ऊपर सरकारी पक्ष से दबाव पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके माने यह नहीं लगाये जा सकते हैं।

श्री गंगासिंह विष्ट--

मैं निवेदन कर रहा था कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जिन कामों को पूरा हो जाना चाहिये था वह नहीं हुआ। वे सब काम अधूरे के अधूरे पड़े हुए हैं। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अल्मोड़ा-लोहाघाट सड़क पचेश्वर सड़क बननी थी। उसका प्राविजन बजट में था, लेकिन तत्कालीन जो मंत्री थे उन्होंने यह सुझाव दिया कि अल्मोड़ा और पौढार के बीच में जो एक छोटा-सा टुकड़ा साढ़े ५ मील का है, पहले उसे ले लिया जाय, लेकिन विभाग की लापरवाही व गलत स्टेटमेन्ट से वह टुकड़ा लिया गया और उसके लिये जो अनुदान रखा गया था उसे दूसरे कार्य पर खर्च कर दिया गया और आज तक वह सड़क ५ मील का टुकड़ा पूरा नहीं बन सका। दोबारा गत वर्ष ही अल्मोड़ा-लोहाघाट सड़क के नाम पर बजट में रुपया रखा गया था, लेकिन इस बजट में जब मैंने देखा तो उनका नाम भी नदारद। वह सड़क अल्मोड़ा तहसील से लोहाघाट तहसील को मिलाती है, वह सड़क एक जिले से दूसरे जिले को मिलाती है और औद्योगिक दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, जनता के लाभ के दृष्टिकोण से उस सड़क की उपादेयता को हमारे मंत्री महोदय भी सदैव मानते रहे हैं, विभागीय कर्मचारी भी मानते रहे हैं और हम सरकारी कर्मचारी भी मानते चले आ रहे हैं कि वह एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में १३ मील सड़क लोगों ने श्रमदान व टैस्ट वर्क से बनायी हुई है और जिसकी चौड़ाई २४ फीट से २८ फीट तक है। अल्मोड़ा और लोहाघाट के बीच की दूरी इस सड़क के रास्ते से कम से कम होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस सड़क की उपादेयता बहुत ज्यादा है। ११ मील के टुकड़े में ७ मील का टुकड़ा तो नदी के इस पार तक बन गया है और नदी के पार भी ४ मील का टुकड़ा बना है। जब कि सन् ६२-६३, ६३-६४, और ६४-६५ के बजट में वहां एक पुल के लिये बजट में प्राविजन था क्योंकि नदी के आरपार सड़क बन चुकी है, लेकिन अभी तक वह पुल नहीं बन सका है। पुल बनने की बात तो दूर रही, पुल के एबटमैन्ट व अप्रोच रोड भी वहां तक नहीं बन सकी है।

सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस सड़क की उपादेयता बहुत बड़ा है। अल्मोड़ा जिले में भी इस सड़क के दोनों सिरों पर बाईडिंनग चल रही है और दूसरे जिले की सीमा पर भी इस सड़क की वाइडनिंग चल रही है। पिठौरागढ़ जिले में ४ दर ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है। अल्मोड़ा तथा पिठौरागढ़ दोनों जिलों के लिये अलग-अलग अनुदान मिलता है। नाम अल्मोड़ा जिले का ही होता है पर वास्तव में काम पिठौरागढ़ में होता है क्योंकि उनके यहां तो डिवीजन अलग माना गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आज तक इन ४ वर्षों में एक मील सड़क भी नहीं बन सकी है। नगर के मध्य से सीमा वर्त्ती क्षेत्र को जो मोटर मार्ग जाता है उस मोटर मार्ग पर दो मील के टुकड़े का एक लिंक मिलना है वह पूरा नहीं हो सका है। माननीया मुख्य मंत्री जी जब वहां नगर में पधारी थीं तथा माननीय मंत्री जी भी वहां पधारे थे तो वहां के सारे कर्मचारियों ने, सारे नागरिकों ने उनसे प्रार्थना की कि इस सड़क के ऊपर हैवी ट्राफिक है और इसमें कभी दुर्घटना होने की संभावना है। अतः इस छोटे से लिंक को जोड़ दिया जाय। उन्होंने इस सुझाव को माना। अधिकारी वर्ग ने भी कहा यह ठीक है। और जब मिलिटरी यहां से सीमा क्षेत्र को मार्च करेगी तो बड़ी कठिनाइयां इस मार्ग पर होंगी। बड़ी रुकावटें रास्ते में हैं और अगर २ मील का लिंक मिला दिया जाता उसमें कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन वह नहीं मिलाया गया। सिर्फ २ मील का टुकड़ा शेष है।

[श्री गंगासिंह विष्ट]

मैं विभागीय लोगों की लापरवाही का दूसरा नमूना देता हूं। उसी नगर में दूसरी सड़क बागेश्वर व पिथौरागढ़ जाती है? यहां पिथौरागढ से सारा ट्राफिक यहां काठगोदाम से सारा ट्राफिक इधर से आता है क्योंकि यही दोनों को मिलाने वाली सड़क है। अब इसी नगर में दूसरी लोअर माल के नाम से एक नयी सडक का निर्माण किया जा रहा है जिससे नगर की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बरबाद होगा। माननीय मंत्री जी ने स्वयं वहां आकर यह आश्वासन दिया था कि इस २ मील के लिंक टुकडे को मिला दिया जायगा।

अब मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप चाहते हैं कि काफी मात्रा में सब्जी, फल, लकडी, कोयला सस्ता लोगों को उपलब्ध हो सके तो केवल ४ मील के टुकड़े को अल्मोड़ा, पौधार को मिलाना बाकी है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से उसकी भी उपेक्षा हुई है गलत इस्टिमेट से जिसका परिणाम यह हुआ है कि एक तहसील से दूसरे तहसील और एक जिले से दूसरे जिले को हम नहीं मिला पा रहे हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इन दो बातों की ओर आप विशेष ध्यान दिलायें। सार्वजनिक दृष्टि से इस सड़क की बहुत ज्यादा इम्पार्टेंस है इसलिये २ मील का टुकड़ा लिंक करना है और ४ मील का टुकडा बनाना है। जहां तक मैं समझ पाया इस सदन में आकर देखा कि जैसे मदारी का जमूरा नाचता है वैसे ही यह अधिकारीवर्ग इन मंत्रियों को नचाते हैं। मिनिस्टर लोग इनके इशारे पर नाचते हैं। मुख्य मंत्री जी के सामने बात आयी, माननीय मंत्री के सामने बात रखी गयी, लेकिन अभी उस वह कार्य का रुके पड़ा रहना इसके स्पष्ट मानी यही हो सकते हैं। इस विभाग के विषय में मुझे ज्यादा नहीं कहना है जहां तक सदाचार का प्रश्न है वह सर्वविदित है। भ्रष्टाचार तो इस विभाग से दूर होने से रहा, कहीं सदाचार भी न दूर हो जाय मुझे इसकी शंका है। इसलिये मेरा निवेदन है सरकार से कि जो मैंने प्राथना की है उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें ताकि हम दुश्मनों से मुकाबिला करने के लिये तैयार रहें। दूसरी योजनाओं के अधूरे कार्य पूरे हों।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं आपको कोटिशः धन्यवाद देता हूं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी पता नहीं कहां चले गये, लेकिन प्रसन्नता है कि माननीय बनारसी दास और माननीय हुकुम सिंह विसेन यहां हैं। देहली से लेकर यहां तक मान्यवर बड़ी खूबसूरत सरकार बनी है और इसलिये जब मैं खडा होता हूं तो इससे मुहब्बत होने लगती है। लेकिन सूरत अगर बुरी है तो बेकार हुस्न है, नजरों पर क्या चढ़ेगा, जो दिल से उतर गया। यह सरकार सबके दिल से उतरती जा रही है और इसीलिये यह कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की तरफ से आया है। मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। इसलिये बोल रहा हूं कि सरकार की आदत बडी खराब है। मिनिस्टर लोग जो बैठे हुए हैं जैसा मेरे दोस्त ने अभी कहा सरकारी अधिकारियों के इशारे पर जमूरे की तरह नाचते हैं। मैं जब से एम० एल० ए० होकर यहां आया तब से ५० बार चीफ इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण मंत्री और सुचेता कृपालानी जी को लिखते-लिखते परेशान हो गया कि यह सडक बननी चाहिये। हमारा जो इलाका है वह पिछड़ा हुआ इलाका है। जब बरसात होती है तो सारा इलाका पानी से लबरेज हो जाता है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिससे आदमी जाकर राशन कहीं से ला सके। यह दशा है उस इलाके की। मैं क्या कहूं। यह सरकार बहुत बाहरी सरकार है। हालांकि हमने हल्ला, गुल्ला, झगड़ा और लड़ाई सब करके देख लिया है पता नहीं इस सरकार को कब अकल आयेगी। यहां पर जबाब मंत्री जी नहीं देते हैं और देते हैं तो ऊटपटांग जवाब देते हैं। मैं जो सार्वजनिक निर्माण कमेटी बनी है उसका सदस्य भी हूं। मैंने मंत्री जी को लिखकर भी दिया और कहा कि और कुछ मत वहां पर कीजिये केवल उस सड़क को बना दीजिये और जो सड़क बनानी शुरू किया है उसको पूरा कर दीजिये। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कहा है कि हाटा से पिपराइच तक सड़क बनना बहुत जरूरी है

क्योंकि वह सीमा से सम्बन्ध रखती है। एक सड़क हाटा से कैप्टेनगंज तक जाती है वह भी सीमा से संबंध रखती है। हाटा से पिपराइच सड़क को पटेल आयोग ने लिया था। उससे आपके विभाग ने ले लिया है पर पता नहीं जो सड़क ले ली जाती हैं उनको सरकार को बनाने में क्या कठिनाई है।

आप और सड़क लेने की बात करते हैं, लेकिन हमारा तो यह निवेदन है कि जिन सड़कों को आपने लिया है उनको बना दीजिये तो हमें सन्तोष हो जाय। आप यहां पर दुनियां भर के कलमें पढ़ते हैं कि यह सड़क ली और वह सड़क ली और अपनी मर्जी के मुताबिक जो समझा उस सड़क को ले लिया और बना दिया। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने अपने इलाके में और अपने क्षेत्र में सारी सड़कों को ठीक कर दिया होगा और आगे की योजना में भी उनको जरूर ले लिया होगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। अगर आप विरोधी पक्ष की बात को नहीं मानेंगे तो प्रजातन्त्र मर जायगा। कहां से आपको ताकत प्राप्त होगी ? इसलिये अपोजीशन के लोग जो सही बात कहते हैं उस पर सरकारी कर्मचारियों को, सरकार को, मिनिस्टर को और मुख्य मंत्री जी को, सब को ध्यान देना चाहिये, लेकिन हमारे मंत्री जी सिर तो हिला रहे हैं। जब ये मंत्री नहीं बने थे तो सरकार को बहुत गाली दिया करते थे और आलोचना करते थे। अब मिनिस्टर बन गये तो सब भूल गये। समझ में बात नहीं आती। मंत्री बनने के बाद पता नहीं किस वजह से खयाल बदल जाता है ? हमारे १८ आदमी भी उधर चले गये हैं। उधर मिल गये तो मंत्री बन गये। उनका भी खयाल बदल गया। इतने बदल गये जिसका खयाल नहीं हो सकता है। इसलिये मैं पुनः मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पटेल आयोग ने जो सड़क अपने हाथ में ली थी हाटा से पिपराइच और हाटा से कैप्टेनगंज, उन सड़कों का निर्माण अवश्य करा दिया जाय। मगर सरकार का यह हाल है कि 'मन मलीन तन सुन्दर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे"। ऊपर से तो भली बात करते हैं लेकिन तबियत में विरोध रखते हैं। अपोजीशन बढ़ने न पाये यह हमेशा सोचते हैं, लेकिन जिस दिन अपोजीशन नहीं रहेगा, समाप्त हो जायगा तो यहां पर डिक्टेटरशिप आ जायेगी यह मैं कहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी ने जो मांग पेश की है उसका घोर विरोध करता हूं।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं समझता हूं उनके संबंध में सरकार और विरोधी दल का बटवारा करके सोचना कुछ श्रेयस्कर नहीं होता है। किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र में चाहे वह उधर के बैठने वाले हों या इधर के हों, यदि सड़कों का निर्माण होगा तो उनसे दोनों ही पक्ष लाभान्वित होने वाले हैं, इसलिये इस विभाग के अनुदान पर विचार व्यक्त करते हुए सरकार और विरोधी पक्ष और सरकार की नीति, इनकी चर्चा करना श्रेयस्कर नहीं है।

मान्यवर, आज सदन में प्रातःकाल से अब तक मैं दोनों पक्षों के विचार सुनता रहा। कोई माननीय सदस्य अब तक ऐसा नहीं बोला है जिसने मंत्री जी से किसी न किसी सड़क और पुल की मांग न की हो। यदि उन तमाम सड़कों और पुलों के निर्माण का मंत्री जी निश्चय कर लें तो कितनी बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसको स्वयं आप कल्पना कर सकते हैं। विभाग द्वारा जो पुस्तिका प्रस्तुत है उसकी भूमिका में स्वीकार किया है कि हमारा प्रदेश इस दिशा में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। इसमें यदि राजपथों का निर्माण करना है तो उसके लिये जो अपेक्षित धनराशि चाहिये वह हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वस्तुतः आज उन्हें कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न करके बढोत्तरी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये था। मैं किसी जमाने में जब उधर बैठा करता था तो माननीय मंत्री जी के एक मित्र-वह आज भी बैठते हैं उन्होंने किसी दिन इस विभाग को "प्लंडर विदाउट डेंजर" की संज्ञा दे डाली, लेकिन मेरा अनुभव कुछ और ही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निकट एक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, एक लेटरल रोड बनायी जा रही है। उसका भार जिन इंजीनियर महोदय के कंधों पर है, मैं समझता हूं और पूर्व वक्ता महोदय से कहूंगा कि उसका नाम एक-एक बच्चा उनकी ईमानदारी, कर्मठता और कार्य कुशलता से प्रसन्न है और सभी उनके प्रशंसक हैं—ऐसे लोगों का प्रोत्साहन बढाने वाला भी काम होना चाहिये।

श्री बांकेलाल—

वहां का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है, वह सड़क बेकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक वह बोल रहे हैं, आपको खड़े नहीं होना चाहिये।

श्री रामायण राय—

बात ऐसी है कि "सुनना हराम है न सुनाना हराम है, सुनने के बाद तैश में आना हराम है।" तो जरा विधान सभाओं में कैसे आचरण किया जाता है, इसको पहले समझ लें...

श्री बांकेलाल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने उंगली उठाकर संकेत किया है जो कि अवैधानिक है और मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी लोगों में घूमा हूं, मैं अधिकारियों की खुराफातें जानता हूं, वह सड़क नहीं बननी चाहिये, बेकार उस पर रुपया खर्च हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी राय में नहीं बननी चाहिये, उनकी राय में बननी चाहिये। आप बैठिये।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के विभाग में जो इंजीनियर्स हैं वे बहुत ही योग्य और जिम्मेदार लोग हैं। जिस तरह से हर विभाग में कुछ ब्लैकशीप भी हुआ करते हैं, हो सकता है इसमें भी कुछ लोग हों। मैं इस संबंध में एक रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं। लोक लेखा समिति में काम करने से जो तजुर्बा हासिल हुआ उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि मुख्यतः ३–४ कारणों से योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो पाता, उसमें देर लगती है। एक तो टैक्नीकल पर्सोनल नहीं मिलते, दूसरे वांछित यंत्रों का अभाव रहता है और तीसरे भूमि प्राप्त करने में देरी लगती है। यह समस्या है। इसके साथ ही एक समस्या और है। इस विभाग का जो सर्वे डिवीजन है उसमें जिस अधिकारी की पोस्टिंग होती है वह ऐसा महसूस करता है कि वह दंडित किया गया है। इसका परिणाम यह होता है कि किसी योजना के लिये जो भी पेपर भेजा जाता है वह सर्वे डिवीजन में ही पड़ा-पड़ा सड़ जाता है। मेरा सुझाव यह है कि वहां जब किसी इंजीनियर्स को नियुक्त करें तो एक निश्चित अवधि के लिये करें, उसे यह मालूम होना चाहिये कि उसकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिये हुई है। उसके बाद उसका दूसरी जगह ट्रान्सफर हो जाना चाहिये और अन्य जगह भी उनको सेवा करने का मौका मिलना चाहिये।

वर्कचार्ज कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये जो कदम उठाया गया है वह बड़ा ही क्रान्तिकारी कदम है और इसका बहुत अच्छा असर होगा। इससे, जो आक्रोश इस विभाग के प्रति लोगों में पैदा हो गया है, वह सदैव के लिये समाप्त हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री सूरज पाल वकील को बुलाने पर)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

जो पार्टी की तरफ से नाम जाते हैं उनको ही क्या आप बुलाते हैं या....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये, मैंने आपको नहीं बुलाया है।

*श्री सूरज लाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को हर जिले को एक ही नजर से देखना चाहिये। परन्तु देखने में यह आया है कि सड़कों आदि के निर्माण में बहुत पक्षपात किया जाता है। जहां मंत्री महोदय का घर होता है वहां पहले सड़क बना दी जाती है, लेकिन जहां इसके विपरीत बात होती है वहां कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जब से मैं चुनकर आया हूं, तब से बराबर अपने क्षेत्र में सड़क के निर्माण के लिये कहता चला आया हूं, परन्तु मैंने देखा कि आज तक उतरौला क्षेत्र में एक इंच भी सड़क नहीं बन पाई है। श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, नेपाल बार्डर पर है और डिफेन्स के लिये बहुत इम्पार्टेन्ट यह स्थान है। एक सड़क उतरौला से तुलसीपुर तक है उस पर एक नदी आती है। उस पर पिपराघाट है। वहां पर एक पुल बनना बहुत आवश्यक है। केवल पांच मील है। हमने चीफ मिनिस्टर को और मंत्री महोदय तथा अन्य अधिकारियों को भी लिखकर भेजा, जबानी भी कहा, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। यहां तक कि आप देखें उतरौला में तहसील है, उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है। साढ़े तीन लाख रुपया उसके लिये सैन्क्शन भी हो चुका है, और डेढ साल हो चुका है, पर अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। अफसोस की बात है कि अभी हमारे यहां माल मंत्री गये थे। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर उतरौला तहसील उठकर मनकापुर उनके रिश्तेदार के यहां जाती है तो वहां की जनता एक संघर्ष करेगी और वहां से तहसील उठ नहीं पायेगी और जो सजेशन मैंने दिया है उसी पर बनायें क्योंकि वह बहुत उपयुक्त स्थान है। हमारे यहां खुशकिस्मती से केन्द्रीय सरकार एक लिटरल रोड का निर्माण कर रही है और आपके इस प्रान्त के द्वारा भी इसका निर्माण हो रहा है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस लिटरल रोड के बनाने के लिये जो इंजीनियर महोदय जो असिस्टेन्ट इंजीनियर महोदय नियुक्त हैं वे बहुत ही भ्रष्ट हैं और उनकी भ्रष्टता अभी हमारे वक्ताओं ने बताई है। मैं उसकी एक कापी लाया हूं कि वे किस तरह भ्रष्टाचार मचाये जा रहे हैं। उस क्षेत्र के एक ओवरसियर जो ईमानदारी करना चाहते थे उससे यह कहा जाता है कि आप बैक डेट करके....मैं आपको सुना देना चाहता हूं अंग्रेजी में है--

"Sri R. S. Vaish—Inspite of my repeated instructions, the bill of Sri K. C. Gupta for the P.W.A. for earth work has not been submitted by you Please get the new P.W.A. registered on the date October 25, 1965 and submit the bill positively on October 22, 1965 otherwise the matter will be reported to higher authorities for non-compliance."

१९-७ को आर्डर देते हैं और कहते हैं कि २८-९-६५ को एक दूसरे कान्ट्रेक्टर के नाम उसके भाई के नाम बैक डेट में एन्ट्री करके और पी० डब्लू० ए० बनाया जाय। यह वह लक्ष्मी चन्द्र गुप्ता हैं जिन्होंने मई के महीने में कान्ट्रेक्ट दिया था उसमें दस हजार रुपये का घाटा था,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सूरजलाल गुप्त वकील]

उनसे पिनाल्टी ली जाती। इंजीनियर महोदय को एक हजार रुपया रिश्वत दे दी क्योंकि चार हजार रुपया घूस में जो खाना था उसको बचाने के लिये। के० सी० गुप्ता जिनका कोई भी कान्ट्रेक्ट जब मई जून में सड़क बनी थी, उस वक्त कोई काम नहीं था, लक्ष्मी चन्द्र गुप्ता के नाम था। उसको बचाने के लिये यह कहा जाता है कि के० सी० गुप्ता के नाम अगस्त या सितम्बर के महीने में बिल बनाया जाय। इसके बारे में मिनिस्टर से कहा। मिनिस्टर महोदय ने बहुत ही गंभीरता से विचार किया और उन्होंने आदेश दिया कि जब तक ओवरसियर से चार्ज न लिया जाय उसको दूसरी जगह भेजा न जाय। जैसा अभी बिष्ट जी ने बताया, ये मदारी के कहने पर नाचते हैं, जैसे बंदरिया नाचती है वैसे ये नाचते हैं। जब यह बात बताई गई कि चार्ज न दिया जावे तो चीफ इंजीनियर ने बताया कि इसमें प्रेस्टीज इनवाल्व्ड है, एक ओवरसियर के द्वारा अगर इंजीनियर को ट्रांसफर कर दिया जायगा तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़बड़ हो जायगा। जब फिर हम लोग मिले तो कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाना है और इसमें सही या गलत बात नहीं देखी जाती है। ओवरसियर का उल्टे ट्रांसफर कर दिया गया और वह इंजीनियर जिसने १,००० रुपया घूस लिया वह वहीं बना हुआ है। मस्टर रोल फर्जी बनाए जाते हैं, जिसकी कापी मेरे पास है। मेट से कहा जाता है कि दूसरा मस्टर रोल बनाओ। उन सड़कों पर जहां इंजीनियर के दोस्त कंट्रेक्टर है ऊंचा रेट दिया जाता है हालांकि उसी काम के लिए दूसरे ठेकेदार ने नीचा रेट दिया था।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य फोटो कापीज या तो आपको दे दें या मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

हां, आप दे दें।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब हमारे पड़ोस के जिले के माननीय सदस्य ने यह कहा कि नैपाल बार्डर पर उनका जिला पड़ता है और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वहां कोई काम नहीं किया जिससे वहां की जनता लाभान्वित होती, तो यदि मैं वास्तविक स्थिति सदन के सामने न रखूं तो अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाऊंगा। नेपाल के पास जो नो-मैन्स-लैंड है उसके पास ही तराई डेवलपमेंट नामक सड़क विख्यात है, जिसमें ८॥ करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। बार्डर पर उस सड़क का निर्माण हो रहा है। मैं नहीं जान सका कि माननीय सदस्य वहां के रहने वाले हैं, गोंडा जिले के हैं या किसी दूसरी जिले से आकर वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं। शोहरतगढ़ से लेकर बेवरुआ थाना होकर तुलसीपुर, पचपेड़वा से होती हुई बहराइच और पीलीभीत को वह सड़क जा रही है जिस तीव्र गति से वह बनाई जा रही है उस एक ही सड़क से मालूम हो जायगा। सुरक्षा की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से, व्यापार की उन्नति के वास्ते, पिछड़ा हुआ अंचल के लिए वह उपयोगी है। क्षेत्र के पनपने के लिए इस विभाग ने अधिक परिश्रम किया है साथ ही साथ न मालूम कितने पुल भी उस ओर बनाए जा रहे हैं जो गोंडा जिले से संबंधित हैं। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे उस तरफ से बलरामपुर की बात कह रहे थे। पिछले वर्ष जब वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी तो ४ लाख ७० हजार रुपया लगा कर एक टेस्ट वर्क खोला गया और सड़क बनायी गयी जो वहां से कौआपुर जाती है। लोगों को इससे उस समय सहायता भी मिली और आवागमन का साधन भी उपलब्ध हुआ।

श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी को पता नहीं है कि उस सड़क पर लाखों रुपया टेस्ट वर्क में लोग खा गए? इसी विधान सभा में कर्मचारियों पर हमने चार्ज लगाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ (व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री--

श्रीमन्, उन्होंने उसमें रोड़ा अटकाया और आन्दोलन किया। मुश्किल से आर्मगार्ड लगाकर वहां लोगों की एक-एक पाई को अदा किया गया। इस तरह से बगावत करने वाले आदमी ऐसी गलत बातें करते हैं। यह एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने वहां के आदमियों को तबाह और बरबाद कर दिया है। (शोर)। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह के आदमी से वहां तबाही और बरबादी आयी हुई है। मस्टर रोल गलत बनाए गए, चोरी करायी गयी। इस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सेवा जनता की की गयी उसको कुसेवा बताया जाता है। अगर वहां पर टेस्ट वर्क न खोला गया होता तो न मालूम वहां कितनी लाशें मिलतीं क्योंकि फसल को बड़ी क्षति हुई थी। लोग परेशानी में थे।

श्री उपाध्यक्ष--

शास्त्री जी, आप शांति से बोलिए।

श्री रामकुमार शास्त्री--

जब वे उत्तेजित कर रहे थे तो आप उनको रोक नहीं रहे थे। उत्तेजना दिलाकर अब वे आप से शांति को कहते हैं। (शोर)।

श्री सुखदेवप्रसाद--

इस मामले की जांच के लिए मैं मंत्री जी से मांग करता हूं। वहां के भ्रष्टाचार की जांच की जाय। (शोर)

श्री रामकुमार शास्त्री--

मैं यह नहीं कहता कि वहां इस विभाग में कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन जो काम अच्छे उसमें किए हैं उनको भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी मेरे साथ गए थे। तुलसीपुर से जो सड़क का टुकड़ा बस्ती जिले तक जाता है उसका निर्माण हो रहा है। उतरौला से आने वाली सड़क का भी निर्माण हो रहा है। जो वास्तविकता है उसको अवश्य कहना चाहिए। गलत बात को मैं यहां सपोर्ट नहीं कर सकता। अयोध्या का जो बड़ा पुल बनाया गया है वह स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने लायक बात है। और भी बहुत से बड़े-बड़े पुल बने हैं। सन् १९३७ से अब तक के कार्यों को देखा अथवा तुलना किया जाय, कितना महान परिवर्तन तब से हुआ है। उस समय से बजट कितना अधिक हो गया है अनुभव करने की बात है। क्या सब पैसा पानी में बहा दिया गया है। लुम्बिनी रोड की ओर कितना बड़ा निर्माण कार्य हुआ है। नेपाल राज में घुसकर २५ मील की दूरी की सड़क ककरहवा से लुम्बनी तक बनाई गई। सराहनीय कार्य है। Tourist देश विदेश से वहां आते जाते हैं गोरखपुर में एक राप्ती पर पुल था। अभी इसका उद्घाटन सेंटर के मिनिस्टर महोदय ने किया। वहां के ओवरसियर की दक्षता के बारे में मार्बिल पर लिखा गया होगा। आखिर हमें निर्माण के काम कराने हैं, वह इसी देश और प्रदेश के लोग करेंगे और अगर कदम-कदम पर इस तरह की आलोचनाएं होंगी। कड़ी बात कही जायगी तो इस तरह से कटौती का प्रस्ताव लाकर सड़कों का निर्माण नहीं होगा बल्कि वह एक ख्वाब हो जायगा और वह काम कभी पूरे नहीं होंगे। अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है तो हमें उसकी सराहना करनी है और बुरा करता है तो उसकी ताड़ना भी होनी चाहिए। अतः माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसका म हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी ने जब से अपने इस पद को संभाला है तब से जब हम अपनी सड़कों की तरफ नजर डालते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि बजाय उनको ठीक कराने के उन्होंने कोई ऐसा सीक्रेट आर्डर भेज दिया है कि उनको बिलकुल ही तबाह कर दिया जाय। जो सड़कें हमारे यहां की थीं उनकी हालत और भी खराब होती जा रही है। आज उन पर बहुत ज्यादा बसें चलती हैं और वह बिलकुल उधड़ चुकी हैं, थोड़े दिन में शायद उनका नामोनिशान भी गायब हो जायगा और आज जो प्लंडर विद आउट डेंजर कहा जाता है वह भी शायद कहने का मौका न मिलेगा। हमें भी कोई ऐसा मौका मंत्री जी दें कि हम भी उनके गुण गा सकें और अपनी आजादी का कुछ सुख उठा सकें। हमारी कांस्टीट्यूएंसी को तो शिड्यूल कर ही दिया गया है और जो दूसरा मेरी जगह आयगा वह कहेगा कि हमारे पहले के मेंबर ने सड़कों के लिए कुछ नहीं किया कराया। मैं अर्ज करूंगा कि बहराइच से नानपारा जो सड़क जाती है उसे चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि बजाय उसको चौड़ा करने के नवाबगंज की जो सड़क है जो उधड़ती जाती है उसे जरा ठीक किया जाय। मैं अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं कहता बल्कि सूबे में जहां भी पिछड़े इलाके हैं वहां की सड़कों पर विशेष ध्यान दें।

अब मैं अंग्रेजी का एक कोटेशन देता हूं कि :

"What was required all these years was not too many flamboyant speeches, but action".

मैं कुछ तारीफ भी कर दूं। हमारी सरकार मरम्मत को कोशिश करती है सड़कों की। लेकिन अफसोस है कि दिनोंदिन सड़कें खराब होती जाती हैं। राधाकृष्णन जी ने कहा है दिसम्बर ६२ में कि "टाक लेस एन्ड ऐक्ट मोर"; उन्होंने कहा था कि हम बातों में बहुत तेज हैं, लेकिन हम जो कहें उसे हमें कार्यान्वित करना चाहिए।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां लम्बी चौड़ी बातें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन चन्द बातें मैं मंत्री महोदय के ध्यान में अवश्य लाना चाहता हूं। इसलिए, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो भी माननीय सदस्य यहां आए हैं उनका कर्त्तव्य है कि वह सरकार को सतर्क रखें और अगर सरकार कहीं गलती करती है तो उसको उससे रोका जाय।

श्रीमन्, पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारी सरकार जो ३१ मार्च को अपना बजट खत्म कर देती है वह सरकार का गलत काम है। काम अधूरे पड़े रहते हैं नवम्बर और दिसम्बर तक वर्षा होती रहती है। एक आध काम जो शुरू होता है वह पूरा नहीं हो पाता है। जो साल का बजट होता है उसका दुरुपयोग ३१ मार्च को किया जाता है हम लोग जो यहां पर चुनकर आए हैं जिन्होंने प्रदेश के लोगों के उत्थान का बीड़ा उठाया है क्या हम और आप उस चीज को तबदील नहीं कर सकते हैं जिससे हमारे बजट की लूट खसोट और उसका जो दुरुपयोग होता है वह बन्द हो सके। क्या बुराई है आप बजट को जून या जुलाई तक एक्सटेन्ड करें बजाय इसके कि रुपये का दुरुपयोग हो।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आपका जो कंटिजेंसी का रुपया होता है हर विभाग का, उसमें से लाखों रुपया १५ रोज के अन्दर ही खर्च हो जाता है। अगर आप इस प्रकार इसमें व्यय करेंगे तो जनता के खजाने के साथ आप बड़ी बेइंसाफी करेंगे।

तीसरी बात जो यहां पर करप्शन की कही जाती है, मैं इस विभाग से कहना चाहता हूं कि हम गुलाम नहीं हैं। हमने संविधान की कसम खायी है और जो झूठ बोलते हैं वे देश के दुश्मन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। आज होता क्या है कि हम में ही से, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर के बैठने वाले सदस्य हों, माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं, प्रोमोशन कराते हैं, सिफारिश करते हैं। अगर आप भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो सिफारिश के लिए न जाइए। जिसको सरकार निकालती है, उनको निकालने दीजिए। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप पहले अपने आप को संभालिए। जो अपने को नहीं संभाल सकते हैं वे ४६ करोड़ व्यक्तियों को कैसे संभाल सकते हैं ?

चौथी बात जो मुझे माननीय मंत्री जी से कहनी है वह यह है कि करप्शन का असली कारण यह भी है कि बड़ी-बड़ी दावतें होती हैं। ओवरसीयर्स को बंगलिंग करने और करप्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है। आप दावतें छोड़ दें। जो बड़े-बड़े लोग हैं वे बड़ी-बड़ी दावतें देते हैं। हमने भी दावतें खायी हैं। इसलिए बता देना चाहता हूं कि आप आज ही अहद कर लीजिए कि दावत खाना ही हराम है। मंत्री जी को चाहिए कि जितने आदमी चापलूस हैं, जितने बर्टरिंग करते हैं, उनको ठोकर मार दीजिए। उन्हें विभाग में न रखिए। भ्रष्टाचार तभी बन्द हो सकता है। लेकिन होता क्या है ? वह कुत्ते की तरह पीछे-पीछे फिरते हैं क्योंकि उन का प्रोमेशन जल्दी होता है, पोजीशन मिलती है, उसको बार्डर पर भेजा जाता है, स्मगलिंग करने के लिए उसको काफी मौका मिलता है। इसलिए विभाग के कर्मचारियों में हार्ट बर्निंग है। ईमानदार आदमी को उपेक्षित किया जाता है क्योंकि वह बर्टरिंग नहीं करता, दावतें नहीं खिला सकता, वह आप लोगों को खुश नहीं कर सकता। इसलिए यदि हममें जरा भी आत्म सम्मान है तो हमको इस प्रकार की दावतें तथा बर्टरिंग को बिलकुल एनकरेज नहीं करना चाहिए।

कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी की बात जो इस मुल्क में है यह गलत नीति है और उसको खत्म करके व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिसके न होने से नतीजा यह होता है कि हर सरकारी कर्मचारी एक से दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। आप रेस्पांसिबिलिटी फिक्स कीजिए और जो भी जिम्मेदार हो उस को सख्त से सख्त सजा दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक कोई काम ठीक से नहीं हो सकता है। कानून में जो कमियां और खामियां हैं उनको दूर कीजिए तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं खासकर माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी से क्योंकि आप ने मूछें रखी हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त हो गया।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जिस दिलचस्पी के साथ माननीय सदस्यों ने दोनों तरफ के मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बहस की मैं उसका शुक्रगुजार हूं। माननीय रामायण राय जी ने यह बात कही कि कुछ और रुपया देना चाहिए। तो मैं यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि डेढ़ करोड़ रुपया आपको और मिला है केंद्रीय सरकार से खासतौर से सुरक्षा की दृष्टि से और वह शायद ज्यादा-तर रुपया बार्डर पर ही खर्च किया जायगा। लेकिन मैं साथ में यह जरूर चाहता हूं कि उसका खर्चा बार्डर में जब करें तो इस तरह से न हो जैसे आपने डोडीहाट सब डिवीजन, पिथौरागढ़ में किया। वहां एक ठेकेदार से ऐग्रीमेंट किया गया १९५९ में कि उसको १९६०-६१ में गिरगांव-मुंसियारी सड़क को पूरा करना है। लेकिन उस काम को अधूरा छोड़ दिया गया और जनवरी, १९६३ तक भी वह काम पूरा नहीं हुआ। उसकी पैमाइश का सर्टिफिकेट जब एस० डी०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसेन]

ओ० ने दिया तो उस समय पूरा काम हालांकि नहीं हुआ था, फिर भी २ लाख २ हजार ४०० रुपये का ओवर पेमेंट उसको कर दिया गया। इसके अलावा उस ठेकेदार की तरफ १,०८,९०० रुपया वाजिब था, ५,३७० रुपया जुर्माने का उस ठेकेदार पर पड़ चुका है, इस तरह से उसकी तरफ २ लाख ७५ हजार रुपया वाजिब था लेकिन दिसम्बर, १९६४ तक उसको रिकवरी का नोटिस नहीं दिया गया, और उसकी सेक्योरिटी ७२,२६१ रु० थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो रुपया आपको मिले वह इस तरीके से बार्डर पर खर्च न हो जिस तरह से इस गिरगांव-मुंसियारी सड़क पर खर्च किया गया।

इसके बाद आपको चिराग तले अंधेरा वाली बात की याद दिलाना चाहता हूं। दारुलशफा और रायल होटल में आपके पंप अटेंडेंट्स रहते हैं। पंप अटेंडेंट तादाद में २० हैं। इनके बारे में इनको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, यह आपके चीफ आफिसर आफ दी असिस्टेंट इंजीनियर के यहां से चिट्ठी जारी हुई है २३ दिसम्बर, १९६४ को। उसमें लिखा है कि—

"After studying the same I am of the opinion that the electric pump attendants be given the scale approved by S. E. (Vide his leter No. 10518 EAE/453 E—53 of 28/X/60 i.e. Rs. 45—65 E.B.—7—75."

आजतक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और उनकी कहीं गिनती नहीं है। आपके यहां से जो चिट्ठी जारी हुई उसमें पंप ड्राइवर के नाम से पोस्ट है पंप अटेंडेंट के नाम से कोई पोस्ट नहीं है। इनमें एक भी पंप ड्राइवर नहीं है और सब पंप अटेंडेंट हैं। इसलिए इन लोगों को पंप ड्राइवर वाली पोस्ट मिलनी चाहिए। जब कि यूनिट मिकैनिक को और दूसरे लोगों को डियरनेस अलाउंस मिलता है तो क्या वजह है कि जो रात-दिन काम करते हैं हाजरी देते हैं उनको केवल ४५-२-६५ रु० ही वेतन मिले और डी० ए० न मिले। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इनको डी० ए० जरूर मिलना चाहिए। यह गरीब तबका है जो हमारे बीच में दिन-रात काम करता है।

अब मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखूंगा। सबसे पहले वर्कमैनों के बारे में सब ने कहा है उनकी तरफ सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आप अपने यहां के वर्कमैनों को भी मद्रास, मध्य प्रदेश और आसाम की तरह से तनख्वाह के साथ-साथ डी० ए० भी दीजिए। इसके अलावा उनको जल्द से जल्द परमानेंट कीजिए जब आप हौर्स अलाउंस ओवरयिर को देते हैं तो मैंगमैन के बेट को साइकिल अलाउंस क्यों नहीं देते हैं?

जैसा मैं कह रहा था आप अपनी सड़कों की चौड़ाई कम से कम २२ फीट कर दें अगर आप एक्सीडेंट्स की तादाद कम करना चाहते हैं। अगर आप सड़कों की चौड़ाई ९-१० फीट रखेंगे तो किसी की जिन्दगी सेफ नहीं है। आप इसे जरूर कर लीजिए। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जिस प्रकार दिल्ली में है वैसे ही जितनी जल्दी आप प्रदेश में कायम करें उतना आपको लाभ होगा। उसके साथ आपने कहा कि हम २० साल के अन्दर हर गांव से चार मील के अन्दर सड़क निकाल देंगे। मैं समझता हूं कि रुपये की कमी के कारण या और परेशानियों की वजह से यह चीज शायद प्रैक्टिकेबिल न हो। लेकिन आप कैनाल डिपार्टमेंट से बात करें और कैनाल और ट्यूबवेल्स के किनारे पर जो सड़कें हैं, उनमें मुख्य-मुख्य सड़कों पर चौका बिछवा दें। कैनाल डिपार्टमेंट उनका मेंटिनेंस नहीं कर पाता। वह प्राब्लम भी साल्व हो जायगी और सड़कें भी हो जायेंगी।

एक चीज और याद दिलाऊं। मैंने एक सवाल भी किया था। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की ट्रैफिक उस हालत में नहीं है जैसी दस साल पहले थी। पिथौरागढ़ जिला बन गया, ट्रफिक बढ़ गई। उसके बाद धनिया रेस्ट हाउस पड़ता है। दोनों तरफ से बसें लंच टाइम में वहां रुकती हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि रेस्ट हाउस में आज तक पानी का इंतजाम नहीं हुआ वहां पानी का इंतजाम हर सूरत में करवाइए। यह बहुत जरूरी है।

हमारे साथी ने कहा कि फर्रुखाबाद, मुरादाबाद की बात कही। मुरादाबाद में एक क्रासिंग पड़ती है। वहां बड़ी प्राब्लेम है। वहां आध-आध घंटे खड़ा रहना पड़ता है। उसमें ओवरब्रिज डबल फाटक पर जरूर बनाएं। इसके अलावा मुरादाबाद में जो १७ मील की सड़क बनाना चाहते हैं वह बिलकुल बेकार है जो कि आपने अपने प्लान से काढ दिया, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान में है। राम गंगा के पुल के बाद पुरानी सड़क मिलने के बाद जो दो मील का टुकड़ा है वह साधारण सड़क से चौगुनी कीमत पर बनेगा क्योंकि वहां बड़ा हैवी अर्थ वर्क है। इस चार मील के टुकड़े पर १५-१६ मील की लागत लगेगी।

एक और सड़क का इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए कि मौजूदा सड़क जो मिलती है वह फ्लडेड एरिया में आ जाती है। खुमरिया बांध बनने के बाद ढेला नदी में आज पानी का पता नहीं है। वह फ्लडेड सड़क नहीं रही। उसको मत बनवाइए। १७ मील जो बना रहे हैं उसकी जगह पर बांके लाल जी मिश्र जी की जो दो-दो, तीन-तीन मील के टुकड़े दे दीजिए। एक सुझाव यह है कि जो सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं मेहरबानी करके उन पेड़ों को लगाएं तो बरसात के मौसम में लगाएं। जनवरी दिसम्बर के महीने में मत लगाएं। आखिरी सुझाव यह है कि जिस पुलिया या सड़क के लिए आपके ओवरसियर के एस्टीमेट के मुताबिक २५ परसेंट जनता जमा कर दे उसको प्रायोरिटी दीजिए। यही बात कह कर में खत्म करता हूं।

श्री जगनप्रसाद रावत—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट पर बहुत से सुझाव दिए और जहां कहीं उन्होंने आवश्यकता समझी, इस विभाग की आलोचना भी की। जहां तक हर जिले में सड़कों और पुलों की आवश्यकताओं का संबंध है, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर तो में विचार करूंगा, लेकिन एक निवेदन में कर दूं, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था—पिछले बजट में जो कुछ एडवांस ऐक्शन लेने की बात मैंने कही थी, सर्वे भी शुरू किया था और लैंड ऐक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स भी शुरू की थी यह सोचा था कि वर्ष ६६-६७ का जो बजट होगा वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख अंग होगा। चूंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है कि उसकी रूप रेखा क्या होगी, कितना धन हमें मिलेगा इसलिए जिला परिषद् के, और यहां के माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार नहीं हो पाया। कोई माननीय सदस्य चिंतित न हों और परेशान न हों कि उनके सुझावों पर कोई विचार नहीं हुआ या कोई विचार होने वाला नहीं है। जैसे ही हमें चौथी पंचवर्षीय योजना के आकार की पता चलेगा, माननीय सदस्यों और जिला परिषदों से सलाह मशविरा करने के बाद ही हम कोई बात आगे तय करेंगे। उसमें हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जिन जिलों में स्टारन्ग्रिट फार्मूला या बाम्बे फार्मूला के कारण अधिक सड़कें बनी हैं वहां पर उसकी रफ्तार हम धीमी करें और जहां कम बनी है, जहां स्टारन्ग्रिट फार्मूला के मातहत हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं, उन्हें ज्यादा हिस्सा देने की कोशिश करेंगे।

दूसरे और भी कई प्रकार के सुझाव रामायणराय जी ने तथा रियासत हुसेन साहब ने दिए। उन सुझाबों का में अलग-अलग तो कोई जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन यह आश्वासन देना

[श्री जगनप्रसाद रावत]

चाहता हूं कि सभी सुझावों पर गंभीरता से और सहानुभूति के साथ विचार करने के बाद कार्य करूंगा ।

जहां तक बार्डर रोड का संबंध है । कुछ थोड़ी सी इसमें लोगों को भ्रान्ति है और वह यह है कि बार्डर रोड्स में दो हिस्से हैं । एक हिस्सा सूबे की पी० डब्लू० डी० के पास है और एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट की बी० आर० डी० सी० के पास है । तो सरयू-पिथौरागढ़ रोड के निर्माण का कार्य उसी के पास है, वही उसको बनाता है, उसमें हमारा किसी प्रकार का दखल नहीं है, इसी प्रकार के और भी बहुत से हिस्से हैं ।

श्री रियासत हुसैन---

टनकपुर से पिथौरागढ़ के बारे में ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

आपने तो उसी के बारे में कहा था । उसको तो हम जरूर देखेंगे जो कि हमारे पास है । दूसरे जो एक माननीय सदस्य ने डाक बंगले का जिक्र किया कि यहां का पानी का प्रबंध हो तो वह जरूर होना चाहिए, उसको करने की कोशिश की जायगी ।

एक माननीय सदस्य ने कुछ मोहाना का जिक्र किया । मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि वहां पर गए माननीय सदस्य को कई महीने हो गये होंगे, लेकिन अब वहां पर काम शुरू हो चुका है, और हमें उम्मीद है कि उस पुल की मरम्मत मई या जून तक पूरी हो जाएगी । अप्रोच रोड पर भी मैटेरियल कलेक्ट हो गया है, वह भी मई या जून तक हम पूरा कर लेंगे ।

दूसरी जो पाइलट प्रोजेक्ट्स या आर्म्ड स्कीम की स्वीकृति की बात हुई है । जिन-जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति आती है, उसका तो हम कोई कार्य शुरू कर पाते हैं । योजना की धनराशि तो बहुत बड़ी वित्तीय धनराशि के रूप में आती है, तो हम कोई कार्य शुरू कर पाते हैं । इसमें जो एक कठिनाई हमने महसूस की है वह भूमि अर्जन की है जो बहुत बड़ी हमारी परेशानी है ।

भूमि अर्जन के सम्बन्ध में कुछ वास्तविक कठिनाई है । यह सही बात है कि गाजीपुर और गोरखपुर जिले में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई हुई । मैं स्वयं आज से लगभग दो महीने पहले गाजीपुर गया था और मैंने उनसे कह दिया कि गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सारे कागजात मंगवा लें और उनसे मैंने आग्रह किया कि भूमि अर्जन के काम में जितनी तेजी ला सकते हों लायें । कई जिलों में जो भूमि अर्जन आफिसर हैं वहां उनके जिम्मे और काम ही इतना अधिक है कि वे उनको पूरा नहीं कर पाते । इसलिये ही स्पेशल लैंड एक्वीजीशन आफिसर रखे गये हैं कि जहां काम ज्यादा हो वहां और कामों को छोड़ कर वे उस काम को ही करें ।

करप्शन की बात कुछ कही गयी । करप्शन के सिलसिले में मैंने पहली मर्तबा भी आपसे निवेदन किया था कि जहां कहीं किसी माननीय सदस्य की शिकायत हो, वे मुझे सूचित करें तो मैं हर तरह से कोशिश करने को तैयार हूं और उसकी जांच वगैरह के लिये और मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने मुझे कई मामले दिये, उन मामलों की जांच हुई और उन में से कई मामले सही साबित हुये, उन पर कार्यवाही की और कुछ लोगों को सजा दी । लेकिन इसी सिलसिले में मुझे दुख के साथ एक प्रसंग छेड़ना पड़ता है जो छेड़ना नहीं चाहिये था । हमें छोटी-छोटी बातों के पीछे नहीं पड़ना चाहिये । वह कुप्रसंग यह है कि एक ओवरसियर का ट्रांसफर हो गया जिसके लिये कहा गया कि उसका ट्रांसफर कैंसिल होना चाहिये और यह भी एक बार नहीं बल्कि दो-तीन बार कहा गया ।

श्री सूरज लाल गुप्त वकील—

ट्रांसफर कैंसिल करने का कोई सवाल ही नहीं था ।

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब आपने प्रसंग छेड़ दिया है तो अब उसे सुनना भी चाहिये । ऐसे मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था । जहां तक ओवरसियर के ट्रांसफर की बात है, उसका ट्रांसफर बहुत नीचे लेविल पर होता है । अगर उसके सम्बन्ध में कोई बुराई है या उनके किसी आफिसर के मुताल्लिक कोई शिकायत है तो मैं उसकी जांच करने के लिये तैयार हूं, लेकिन बिना जांच पड़ताल के किसी माननीय सदस्य के कहने पर अगर किसी का ट्रांसफर हो जाय चाहे वह ओवरसियर हो या इंजीनियर हो, या उसका ट्रांसफर कैंसिल हो जाय, तो आप समझ सकते हैं कि इस से इतना बड़ा केआस पैदा हो जायगा जिसे संभालना आपके लिये और हमारे लिये बड़ा कठिन हो जायगा। जहां तक चार्ज लेने की बात है, मैंने एक माननीय सदस्य की मौजूदगी में चीफ इंजीनियर से कहा कि तमाम सामग्री मुझे दी जाय और अगर उस से चार्ज नहीं लिया जाता तो ओवरसियर को कह दिया जाय वहां जा कर वह चार्ज ले ले, क्योंकि जब वह चार्ज एक जगह से छोड़ ही रहा है तो इसमें उसको करना ही क्या है । इस तरह से एक ओवरसियर के छोटे से मामले को ले कर कोई बात करना मेरी समझ से अच्छा नहीं है । और इसके लिये ज्यादा परेशान होना मुनासिव नहीं मालूम होता है कि उसका ट्रांसफर कैंसिल क्यों नहीं किया गया ।

वर्क चार्ज के सिलसिले में जो कुछ कहा गया और जो सुझाव दिये गये उन सबको ध्यान में रखते हुये मैं और स्टेट्स से भी इस सम्बन्ध में पूछूंगा कि क्या होता है । और किसी स्टेट में कुछ होता हो या न होता हो, लेकिन मैं समझता हूं कि वर्क चार्ज के लिये कुछ न कुछ होना चाहिये। उनके साथ जितनी सहानुभूति और माननीय सदस्यों की है उससे कम मेरी नहीं है । मैं पुनः एक बार सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी स्प्रिट में इस बजट को लिया ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । खासतौर से किसी विभाग से जब रुपये की जरूरत होती है तो उसके लिये कटौती आपके विभाग में ही हुआ करती है, तो क्या भविष्य में आप इस बात पर ध्यान रखेंगे ?

श्री सूरज लाल गुप्त वकील—

श्रीमन्, मैंने ट्रांसफर के कैंसिलेशन के लिये कभी नहीं कहा । मैं तो यह आप से कहता हूं कि उसको कहा जाता है कि वह दूसरी जगह जा कर चार्ज ले विदाउट गिविंग एनी चार्ज । तो जब तक उसे क्लीयरेंस सर्टिफिकेट न मिले तब तक दूसरी जगह जा कर चार्ज कैसे ले सकता है ? यही सारी दिक्कत है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

तो क्या आप कृपया इसको देखेंगे कि यह फिर न होने पावे ?

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जिन जिलों में सड़कें कम बनी हैं वहां अब ज्यादा बनाई जायेंगी । नैनीताल में पांच सौ मील सड़क बनवाई गई, और जिलों में भी पहाड़ों में बनवाई गई, लेकिन गढ़वाल में २२ मील ही सड़क बनवाई गई । इसको आप क्या कृपा करके देखेंगे?

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कौंसिलर्स रेजीडेंस में जो छतें बनी हैं ऐसी सूचना मिली है कि उनमें जितने सूत की मोटी सरिया लगनी चाहिये थी वह नहीं लगायी गयी है। तो क्या आप उसकी जांच उसको कहीं एक जगह तुड़वाकर करायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिस सूत्र से आपको सूचना मिली है कोई टेक्नीकल आदमी होंगे। उनको मेरे पास भेज दीजिये। मैं उनसे बातचीत करके देखूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, ठेकेदार ५ बोरी सीमेंट की जगह ६ बोरी सीमेंट लगाते हैं और फिर भी काम कमजोर होता है जिसका मतलब यह है कि वह ब्लैक में जाता है। तो जो यह भ्रष्टाचार का बोलबाला है इसके लिये क्या आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़कें बनी हैं उनको मैंने देखा है। सड़कें सभी जगह एक तरह की हैं, गोरखपुर में भी और वहां भी, तो मैंने देखा है कि २–२ और तीन तीन प्रकार की मजदूरी लेबर को मिलती है, उसमें बहुत असमानता है। उसको दूर करने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री कृष्ण सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल–उत्तरकाशी)—

क्या सरकार की जानकारी में यह है कि टेहरी गढ़वाल में जो १२ मील की सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनने वाली थी वह बनी नहीं ? वह अब बनेगी या नहीं बनेगी, यह सरकार बताने की कृपा करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिये गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत १४,४४,४९,७०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत ९६,७०,९०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३७—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत २,२४,८५,३०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १८,६६,३४,६०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ मार्च, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२६ पर)

क्रम सं०	नाम व पता	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने का महीना	पंखा व बत्ती शक्ति	कार्य स्थिति
१	२	३	४	५
		वाट्स		
१	श्री हरख चन्द्र लोहार मधुबन ।	फरवरी, १९६६ ।	२०० ..	अनुमानित व्यय पत्र निरीक्षण किया जा रहा है और विद्युत् कनेक्शन सभी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद दिया जायेगा ।
२	श्री सीताराम हलवाई, मधुबन ।	फरवरी, १९६६ ।	५०० ..	,, ,, ,,
३	श्री सत्य नारायन, मधुबन ।	फरवरी, १९६६ ।	३०० ..	,, ,, ,,
४	श्री जगन्नाथ मल्ल, मधुबन ।	नवम्बर, १९६५ ।	.. ५ हार्स पावर (औद्योगिक)	अनुमानित व्यय-पत्र स्वीकृत हो चुका है । शर्त व नियम भेजा जा रहा है और कनेक्शन सभी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद दे दिया जायगा ।
५	श्री सरजू सिंह, मधुबन	सितम्बर, १९६५ ।	.. १५ हार्स पावर (औद्योगिक)	,, ,, ,,
६	श्री राजकुमार राय, सूरजपुर ।	फरवरी, १९६६ ।	३०० ..	अनुमानित व्यय-पत्र निरीक्षण किया जा रहा है । और विद्युत् कनेक्शन शीघ्र ही सभी कार्यवाही पूरी हो जाने पर दे दिया जायगा ।
७	श्री राम वृक्ष चौबे, कमलासागर ।	जनवरी, १९६६ ।	.. १५ हार्स पावर (औद्योगिक)	,, ,, ,,

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३२ पर)

निम्नलिखित ग्रामों में विद्युत् पहुंचाने हेतु पर्यवेक्षण (सर्वे) किया गया और वैद्युतीकरण लाभरहित पाया गया ।

(१) बहुता

(२) लालपुर

(३) शिवनाम

हसवापुर खैरा ग्राम का पर्यवेक्षण किया जा रहा है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३४ एल० ए०—१६६६—८६२ ।